चौथी दुनिया

www.chauthiduniya.com

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

मूल्य 5 रुपये

1986 से प्रकाशित

26 अगस्त–01 सितंबर 2013

सभी फोटो – प्रभात पाण्डेय

मनीष कुमार

काजल की काली कोठरी के बाहर रह कर खुद को बेदाग कहना आसान है, लेकिन काजल की काली कोठरी के अंदर रह कर खुद को बेदाग रखना ही असली परीक्षा है. आम आदमी पार्टी राजनीति की काली कोठरी से अब तक बाहर है. अभी अंदर गई भी नहीं है, लेकिन इसके अंदाज बदलने लगे हैं. राजनीतिक दलों वाली बीमारियां इसे ग्रसित करने लगी है. पार्टी कार्यकर्ता ही झूठ, फरेब और धोखाधड़ी के आरोप लगा रहे हैं. पैसे का हिसाब मांगा जा रहा है. उम्मीदवारों के सेलेक्शन पर पार्टी बंट चुकी है. आम आदमी पार्टी यानी आप का अब बाप यानी भारतीय आम आदमी परिवार बन चुका है. अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी दिल्ली में चुनाव लड़ने जा रही है. इसका दिल्ली के चुनाव व देश की राजनीति पर क्या असर होगा, यह समझना जरूरी है.

कुछ दिन पहले की बात है. आम आदमी पार्टी को चुनाव चिन्ह झाड़ू मिल चुका था. दिल्ली के कनॉट प्लेस में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पोस्टर लगा रहे थे. कुछ देर बाद उन्होंने ऑटो रिक्शा वालों से गुजारिश की कि वे अपने-अपने ऑटो के पीछे आम आदमी पार्टी के पोस्टर लगा लें. ऑटो वालों ने मना कर दिया. कार्यकर्ता उन्हें समझाने की कोशिश में जुटे रहे. देश में फैले भ्रष्टाचार व दिल्ली सरकार की कमियों को समझाने की कोशिश की. करीब आधे घंटे तक कार्यकर्ता उन्हें समझाने में लगे रहे. इस दौरान करीब 20 ऑटो वाले जमा हो गए, लेकिन सिर्फ एक ही ऑटो वाला मुफ्त में पोस्टर लगाने को राजी हुआ. इस बात का उल्लेख करना इसलिए जरूरी है, क्योंकि जब दिल्ली के रामलीला मैदान में अन्ना हजारे ने अनशन की थी, तो दिल्ली के ऑटो वाले इस आंदोलन में काफी सक्रिय थे. रामलीला मैदान जाने वालों को दिल्ली के ऑटो वालों ने मुफ्त सेवाएं दी थीं. आज आम आदमी पार्टी का पोस्टर लगाने में भी ऑटो वालों को आपत्ति है. 2011 और 2013 के बीच ऐसा क्या हो गया कि लोगों के विचार में इतना फर्क आ गया? क्या यह कोई संकेत है?

आम आदमी पार्टी अन्ना हजारे के आंदोलन से अलग होकर बनी है. अरविंद केजरीवाल और उनके साथियों को लगा कि संसद और विधानसभाओं में जाकर ही भ्रष्टाचार खत्म किया जा सकता है. अरविंद केजरीवाल ने अपना आंदोलन खत्म करके पार्टी बना ली. अन्ना के समर्थक इस पार्टी से अलग हो गए. अन्ना ने अरविंद केजरीवाल को साफ-साफ मना कर दिया कि आम आदमी पार्टी न तो उनका नाम और न ही फोटो का इस्तेमाल कर सकती है. अपनी जनतंत्र यात्रा के दौरान अन्ना कई बार कह चुके हैं कि व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई व्यवस्था में शामिल हो कर नहीं लड़ी जा सकती और उनके लिए भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी या आम आदमी पार्टी सब एक जैसी हैं और उन्हें इन राजनीतिक दलों से कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन आजकल दिल्ली में एक एसएमएस भेजा जा रहा है. इस एसएमएस में लोगों से आम आदमी पार्टी को वोट देने की अपील की जा रही है. हैरानी की बात यह है कि इस एसएमएस में अन्ना का नाम है और आम आदमी पार्टी को अन्ना का सहयोगी बताया जा रहा है. हकीकत यह है कि अन्ना हजारे को आम आदमी पार्टी से कुछ लेना-देना नहीं है और न ही उन्होंने कभी इसे अपना समर्थन दिया है. इसलिए आम आदमी पार्टी के लिए वोट मांगने वाले एसएमएस में अन्ना का नाम होना लोगों को धोखा देने जैसा है. अब सवाल यह है कि इस एसएमएस का सूत्रधार कौन है? क्या इसे आम आदमी पार्टी द्वारा भेजा जा रहा है?

दो स्थितियां संभव हैं. एक यह कि अरविंद केजरीवाल और दूसरे वरिष्ठ नेताओं के आदेश से यह एसएमएस भेजा जा रहा हो और दूसरा यह कि अरविंद केजरीवाल को इसके बारे में पता न हो. दोनों ही बातें संभव हैं. अगर आम आदमी पार्टी एक नियोजन के तहत वोट के लिए ऐसे एसएमएस भेज रही है, अन्ना के नाम का इस्तेमाल कर रही है, तो इसका मतलब साफ है कि राजनीतिक दलों की बीमारियां इस पार्टी को भी लग चुकी हैं, क्योंकि ऐसा करने के लिए उनके पास न तो अन्ना की अनुमति है और न ही पार्टी ने यह सार्वजनिक रूप से ऐलान किया है कि वह अन्ना के नाम का इस्तेमाल कर रही है.

दो स्थितियां संभव है. एक यह कि अरविंद केजरीवाल और दूसरे वरिष्ठ नेताओं के आदेश से यह एसएमएस भेजा जा रहा हो और दूसरा यह कि अरविंद केजरीवाल को इसके बारे में पता न हो. दोनों ही बातें संभव हैं. अगर आम आदमी पार्टी एक नियोजन के तहत वोट के लिए ऐसे एसएमएस भेज रही है, अन्ना के नाम का इस्तेमाल कर रही है, तो इसका मतलब साफ है कि राजनीतिक दलों की बीमारियां इस पार्टी को भी लग चुकी हैं, क्योंकि ऐसा करने के लिए उनके पास न तो अन्ना की अनुमति है और न ही पार्टी ने यह सार्वजनिक रूप से ऐलान किया है कि वह अन्ना के नाम का इस्तेमाल कर रही है. भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने का दावा करने वाली पार्टी को कम से कम इतना तो समझ में आना ही चाहिए कि सही क्या है और गलत क्या है? ऐसा भी संभव है कि अरविंद केजरीवाल व पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को इस एसएमएस के बारे में पता न हो और कुछ कनिष्ठ नेता या कोई उम्मीदवार अपने मन से इस तरह के एसएमएस भेज रहा हो. अगर स्थिति यह है, तो मामला और भी गंभीर है. इसका मतलब यह है कि आम आदमी पार्टी कोई संगठन नहीं, बल्कि अराजक तत्वों का जमावड़ा है, जहां जिसे जो मन में आता है, कर गुजरता है. जब अन्ना ने उनके नाम का इस्तेमाल करने से मना कर दिया था, तब आम आदमी पार्टी के नेता या कार्यकर्ता उनके नाम से एसएमएस कैसे भेज सकते हैं. अगर अरविंद केजरीवाल को इसके बारे पता है, तो ऐसे लोगों के खिलाफ क्या एक्शन लिया गया है और पता नहीं है, तो इसका मतलब यही है कि पार्टी नेताओं के नियंत्रण से बाहर है. ऐसे में आम आदमी पार्टी के लिए दिल्ली में चुनाव लड़ना काफी कठिन साबित हो सकता है.

दरअसल, आम आदमी पार्टी की परेशानी इससे भी गंभीर है. दिल्ली विधानसभा चुनाव महज एक चुनाव नहीं, बल्कि अस्तित्व का सवाल बना हुआ है. यह आम आदमी पार्टी के लिए पहली और आखरी अग्नि परीक्षा है. यह करो या मरो की स्थिति है. कैसे? इसे समझना जरूरी है. आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी समस्या यह है कि पार्टी के कार्यकर्ता ही उम्मीदवारों के चयन को लेकर नाराज हैं. नाराजगी की वजह चुनाव प्रक्रिया से ज्यादा कार्यकर्ताओं की महात्वाकांक्षा है. सिर्फ दिल्ली ही नहीं, बल्कि पूरे देश में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता सांसद व विधायक बनने की आशा मन में पाले बैठा है. वैसे तो यह स्थिति न सिर्फ सराहनीय है, बल्कि प्रजातंत्र के लिए अच्छी बात है, लेकिन अगर पार्टी में सब नेता ही रहे, कोई कार्यकर्ता न बचे, तो पार्टी को चलाना मुश्किल हो जाता है. इसलिए कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर करना जरूरी है और उम्मीद तो यही है कि उनकी नाराजगी दूर भी हो जाएगी, लेकिन दिल्ली के चुनाव में क्या होगा? किसे कितना वोट मिलेगा, कौन जीतेगा और कौन हारेगा, यह अभी तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन चुनाव परिणाम के बाद की स्थिति को एनलाइज जरूर किया जा सकता है.

(शेष पृष्ठ 2 पर)

दिल्ली विधानसभा चुनाव में एक और स्थिति पैदा हो सकती है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत जाती है. कांग्रेस हार जाती है. आम आदमी पार्टी को ज्यादा सीटें नहीं मिलती है.

कैसे पटेगी साम्प्रदायिकता की खाई 03

इस सिस्टम में बोलना मना है... 04

जो भ्रष्ट है वही योग्य है 05

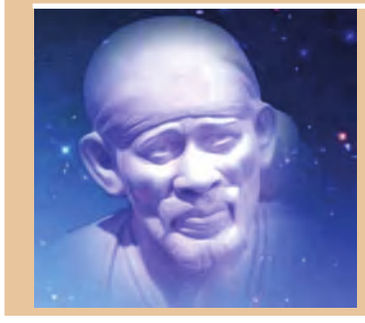

साई की महिमा 12

यह आम आदमी पार्टी की अग्नि परीक्षा है

पृष्ठ एक का शेष

इसमें कोई शक नहीं है कि दिल्ली चुनाव के नतीजों पर आम आदमी पार्टी का भविष्य लटका है. आम आदमी पार्टी पूरी ताकत से चुनाव के लिए तैयारी कर रही है. कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से ज्यादा आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं. यह पार्टी नई है, इसलिए ऐसा करना जरूरी भी है. अरविंद केजरीवाल जिस तरह से प्रचार कर रहे हैं और जिस तरह से उन्होंने मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को चुनौती दी है, तो इससे यही लगता है कि आम आदमी पार्टी की रणनीति बहुमत लाने की है. अगर आम आदमी पार्टी को बहुमत मिल जाता है और केजरीवाल सरकार बना लेते हैं, तो इसमें कोई शक नहीं है कि पूरे देश का राजनीतिक माहौल बदल जाएगा. 2014 लोकसभा चुनाव की कहानी कुछ और ही होगी, लेकिन समस्या यह है कि अब तक जितने भी सर्वे आए हैं, उसमें आम आदमी पार्टी को बहुमत मिलता नजर नहीं आ रहा है. आम आदमी पार्टी हर सर्वे में फिसड्डी है.

इंडिया टुडे–सी वोटर्स के सर्वे के मुताबिक, शीला दीक्षित को 41 फीसद और केजरीवाल को 21 फीसद लोग मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं. वैसे यह हैरानी की बात है, लेकिन सच्चाई यही है कि भ्रष्टाचार के तमाम आरोपों के बावजूद, सर्वे रिपोर्टों में शीला दीक्षित आज भी दिल्लीवासियों के लिए सबसे पसंदीदा मुख्यमंत्री उम्मीदवार हैं. इस सर्वे के मुताबिक, आम आदमी पार्टी को सिर्फ 9 सीटें मिलेंगी. हालांकि इन सर्वे रिपोर्ट्स पर विश्वास नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसे एक संकेत जरूर माना जा सकता है. कहने का मतलब यह है कि दिल्ली में ऐसी स्थिति का निर्माण नहीं हुआ है कि जहां यह दावा किया जा सके कि आम आदमी पार्टी को बहुमत मिल ही जाएगा और यही आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी समस्या है. दिल्ली में अगर किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिलता है, तब आम आदमी पार्टी के सामने यह प्रश्न होगा कि वह किसे समर्थन दे. अगर वह कांग्रेस का समर्थन करती है, तो भ्रष्टाचार को गले लगाएगी और अगर बीजेपी को सपोर्ट करती है, तो उस पर सांप्रदायिक होने का टैग लगेगा. एक तरफ खाई, तो दूसरी तरफ कुआं वाली स्थिति होगी. नुकसान सिर्फ आम आदमी पार्टी का होगा. दुविधा यह है कि चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल इस सवाल का जवाब नहीं देंगे कि ऐसी स्थिति में वह किसे समर्थन देंगे. चुनाव के बाद उन्होंने किसी का भी समर्थन किया या वोटिंग में हिस्सा न लेकर किसी भी पार्टी को सरकार बनाने का मौका दिया, तो लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी लोगों की नजरों में एक विश्वसनीय पार्टी नहीं रह पाएगी. आम आदमी पार्टी की छवि मायावती और मुलायम सिहं यादव की पार्टी जैसी होगी, जो संसद के बाहर तो कांग्रेस को भला–बुरा कहती है, लेकिन संसद के अंदर हमेशा मदद के लिए तैनात रहती है.

दिल्ली के चुनाव में एक और स्थिति बन सकती है. आम आदमी पार्टी को 10–20 फीसद वोट मिलती है, लेकिन सीटें नहीं मिलती और कांग्रेस पार्टी फिर से जीत जाती है. शीला दीक्षित फिर से मुख्यमंत्री बन जाती हैं, तब कांग्रेस की जीत का सेहरा आम आदमी पार्टी के सिर पर होगा. यह स्थिति आम आदमी पार्टी के लिए शर्मनाक होगी. लोग उस थ्योरी को सच मानने लगेंगे कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस की सेफ्टी वॉल्व है, जिसे बीजेपी को दूर रखने के लिए मैदान में उतारा गया है. हालांकि इस बात में सच्चाई नहीं है, लेकिन अरविंद केजरीवाल देश में किस–किस को समझाएंगे, पार्टी कार्यकर्ता अपने मुहल्लों में किसे मुंह दिखा पाएंगे, क्योंकि आप जिस सरकार के खिलाफ पिछले 2–3 साल से लड़ रहे हो, वही सरकार आपकी वजह से फिर से जीत गई. आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पार्टी छोड़ घर बैठ जाएंगे, क्योंकि ज्यादातर कार्यकर्ता कांग्रेस के भ्रष्टाचार से तंग आकर ही अन्ना के आंदोलन में आए थे, जो बाद में अरविंद केजरीवाल से जुड़े. आम आदमी पार्टी की इमेज एक वोट–कटुआ पार्टी की हो जाएगी, जिसे लोकसभा चुनाव में लोग गंभीरता से नहीं लेंगे और कांग्रेस को जिताने वाली पार्टी के रूप में देखेंगे.

दिल्ली विधानसभा चुनाव में एक और स्थिति पैदा हो सकती है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत जाती है. कांग्रेस हार जाती है. आम आदमी पार्टी को ज्यादा सीटें नहीं मिलती है. तब आम आदमी पार्टी का अस्तित्व निरर्थक हो जाएगा, क्योंकि इसे यही माना जाएगा कि इस पार्टी का चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ा. लोग यही कहेंगे कि यह तो पहले से ही तय था कि कांग्रेस इस बार चुनाव नहीं जीत सकती और बीजेपी को जीतना ही था. ऐसी स्थिति में आम आदमी पार्टी का लोकसभा चुनाव में शामिल होने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा. कहने का मतलब यह है कि आम आदमी पार्टी को अगर अपना अस्तित्व बचाना है, तो इसे दिल्ली विधानसभा चुनाव में किसी भी कीमत पर बहुमत लाना जरूरी है.

सच्चाई तो यही है कि दिल्ली के लिए यह गर्व की बात होगी, अगर अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बनते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति बनती दिखाई नहीं देती. अगर आम आदमी पार्टी चुनाव हार जाती है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि लोग भ्रष्टाचार और महंगाई से परेशान नहीं हैं. इसका मतलब यह भी नहीं है कि लोग व्यवस्था परिवर्तन नहीं चाहते हैं. समझने वाली बात यह है कि पिछले 67 सालों में राजनीतिक दलों ने चुनावी वातावरण इतना दूषित कर दिया है कि लोगों को राजनीतिक दलों से ही घृणा हो गई है. 2011 का जनलोकपाल आंदोलन सिर्फ अन्ना की वजह से इतना बड़ा बना था, क्योंकि लोग अन्ना में एक संत देखते हैं. लोगों को अन्ना का त्याग दिखाई देता है. अन्ना में सत्ता की लालसा नहीं है, यही बात भारत के लोगों के दिल में समा चुकी है. इसलिए जो समर्थन अन्ना को 2011 में मिला, वह 2013 में अरविंद केजरीवाल को नहीं मिल सकता है. भारत में लोग आंदोलन करने वाले का त्याग देखते हैं और चुनाव लड़ने वालों की आंखो में उन्हें सत्ता की भूख नजर आती है. देश की जनता भी इन दोनों में अंतर करना भली–भांति जानती है. बिना स्वार्थ के आंदोलन करने वालों को देश की जनता का हमेशा समर्थन मिला है, लोगों का प्यार मिला है, जो किसी भी राजनीतिक दलों के नसीब में नहीं है.■

manish@chauthiduniya.com

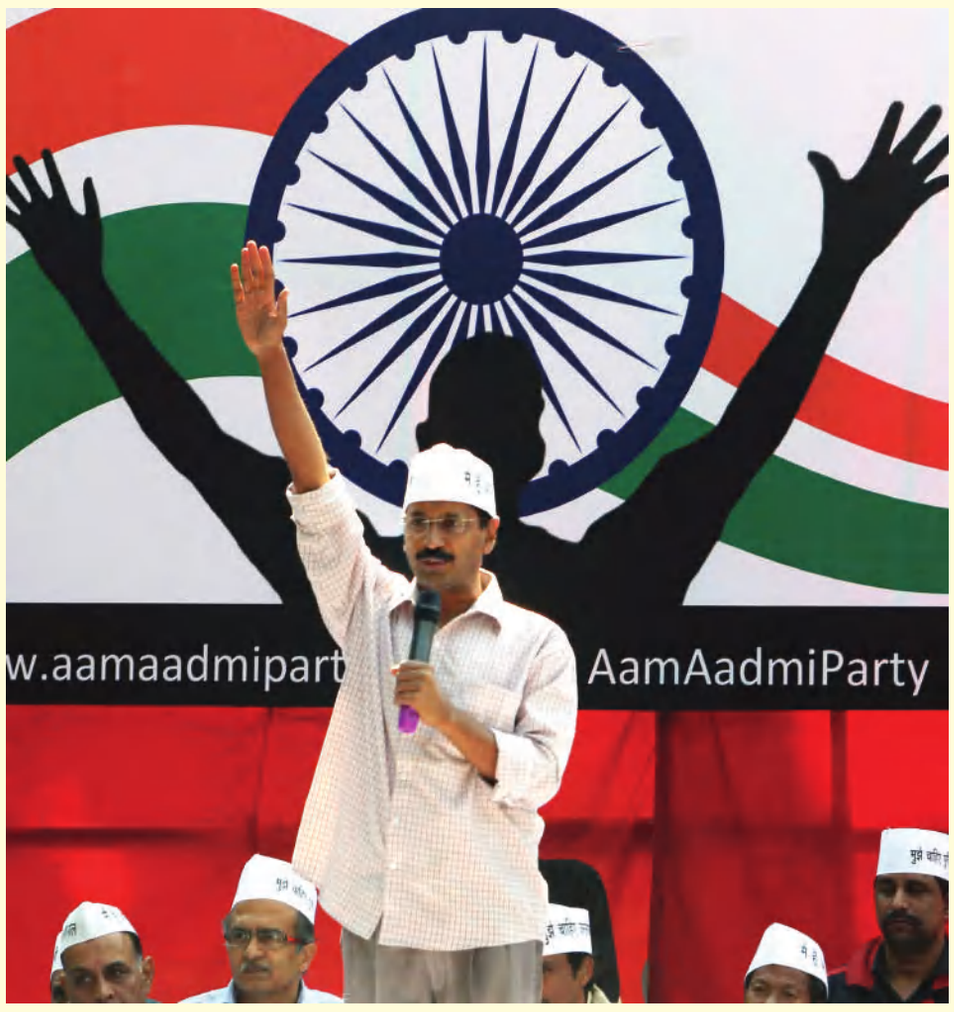

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

वर्ष 05 अंक 25
दिल्ली, 26 अगस्त–01 सितंबर 2013
RNI-DELHIN/2009/30467

संपादक
संतोष भारतीय

संपादक समन्वय
डॉ. मनीष कुमार

सहायक संपादक
सरोज कुमार सिंह (बिहार–झारखंड)
प्रथम तल, विराट कॉम्प्लेक्स के पीछे, सरदार पटेल पथ, कृष्णा अपार्टमेंट के नज़दीक, बोरिंग रोड, पटना–800013
फोन : 0612 2570092, 9431421901

ब्यूरो चीफ (लखनऊ)
अजय कुमार
जे–3/2 डालीबाग कॉलोनी, हजरतगंज, लखनऊ–226001
फोन : 0522–2204678, 9415005111

मैसर्स अंकुश पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक व प्रकाशक रामपाल सिंह भदौरिया द्वारा जागरण प्रकाशन लिमिटेड डी 210–211 सेक्टर 63 नोएडा उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं के– 2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001 से प्रकाशित

संपादकीय कार्यालय
के–2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001
कैंप कार्यालय एफ–2, सेक्टर –11, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश–201301

फोन न.
संपादकीय 0120–6451999
6450888
6452888
011–23418962
विज्ञापन व प्रसार +91–9266627379
फैक्स न. 0120–2544378

पृष्ठ–16+4 (बिहार–झारखंड, उत्तर प्रदेश–उत्तराखंड) हर शुक्रवार को प्रकाशित

चौथी दुनिया में छपे सभी लेख अथवा सामग्री पर चौथी दुनिया का कॉपीराइट है. बिना अनुमति के किसी लेख अथवा सामग्री के पुन: प्रकाशन पर क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी.

समस्त कानूनी विवादों का क्षेत्राधिकार दिल्ली न्यायालयों के अधीन होगा.

दिल्ली का बाबू

दिलीप चेरियन

रिटायरमेंट क्या है?

पंजाब और हरियाणा के आईएएस अफसरों के लिए रिटायरमेंट कोई चिंता का कारण नहीं होता, जैसा कि लोग कल्पना करते हैं. कुछ मामलों में ही उन्हें आने वाले कल की तरफ देखना होता है, क्योंकि बाबू लोग रिटायरमेंट के बाद कौन सा सरकारी काम मिल सकता है, इस पर पहले से नजर गड़ाए रखते हैं. दोनों राज्यों की सरकारें रिटायर्ड बाबुओं को आसान सी नौकरियां अता करने के मामले में बहुत उदार रही हैं. पंजाब में तमाम ऐसे बाबू हैं जिन्हें राज्य सूचना आयोग और राज्य सेवाधिकार आयोग में काम मिला हुआ है. पूर्व मुख्य सचिव रमेश इंदर सिंह फिलहाल पंजाब राज्य सूचना आयोग के प्रमुख हैं. उनके साथ रिटायर्ड आईएएस अधिकारी सतिंदर पाल सिंह, परवीन कुमार, बीसी ठाकुर और नरिंदरजीत सिंह सूचना आयुक्त हैं. सूत्रों का कहना है कि दस सदस्यीय आयोग में पांच पूर्व नौकरशाह हैं. इसी तरह एक और पूर्व मुख्य सचिव एससी अग्रवाल पंजाब सेवाधिकार आयोग के प्रमुख हैं. उनके साथ रिटायर्ड डीजीपी एसएम शर्मा और आइएएस इकबाल सिंह सिंधु हैं.

सूत्रों ने कहा, पडोसी हरियाणा में सूचना आयोग एक बार फिर से पूर्व बाबुओं के लिए रिटायरमेंट आवास में बदल गया. 2005 से अब तक हरियाणा सरकार ने 30 से ज्यादा आईएएस व आईपीएस अधिकारियों को या तो दोबारा नियुक्ति दी है या फिर छह महीने का सेवा विस्तार दिया है. ■

राजन का सौभाग्यशाली कमरा

विवेचक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर के रूप में मुख्य आर्थिक सलाहकार रघुराम राजन की नियुक्ति को पहले से तय मान रहे हैं. उनमें से किसी ने भी राजन के उस कमरे को श्रेय नहीं दिया जो उन्होंने वित्त मंत्रालय परिसर में लिया हुआ है. स्पष्टतया राजन का कमरा नंबर 132–ए वर्षों से उसमें रहने वालों के लिए सौभाग्यशाली साबित हुआ है. उसमें रहने वाले ज्यादातर लोगों की तरक्की हुई है. पिछले साल राजन के उस कमरे में आने से पहले उस कमरे में ओमिता पॉल रहती थीं, जिन्हें राष्ट्रपति का सचिव नियुक्त किया गया और वे राष्ट्रपति भवन पहुंच गईं. रघुराम राजन पहले ऐसे गैर–आइएएस अधिकारी होंगे जो रिजर्व बैंक के मुखिया होंगे. दिलचस्प है कि रघुराम का यह कमरा वित्त मंत्री पी चिदंबरम और आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव अरविंद मायाराम के बीचोबीच स्थित है. अरिविंद खुद भी रिजर्व बैंक के गवर्नर बनने की दौड में शामिल. लेकिन अब सवाल यह है कि राजन जल्द ही इस कमरे से शिफ्ट करेंगे, उसके बाद इस सौभाग्यशाली कमरे में कौन रहेगा जो इस सिलसिले को आगे बढ़ाएगा? ■

अधिकारी का जाना

यद्यपि 1979 बैच के अधिकारी शक्ति सिन्हा, जो कि वित्त विभाग के मुख्य सचिव पद पर तैनात हैं, दृढ़ता से कह रहे हैं कि उन्होंने सरकार से बाहर रहकर काम करने के लिए स्वेच्छा से रिटायरमेंट चुना है, लेकिन विवेचक उनके जाने को लेकर कुछ और मतलब निकाल रहे हैं. सिन्हा दिल्ली सरकार में वरिष्ठ आइएएस अधिकारी हैं और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के संयुक्त सचिव रह चुके हैं.

अफवाह यह है कि सिन्हा को मुख्य सचिव के पद के लिए दिल्ली सरकार की ओर से नजरअंदाज किया जा रहा था जिससे वे उकता गए थे. यह पद उनके बैचमेट डीएम स्पोलिया को मिल गया. यह भी कहा जा रहा है कि दिल्ली की बिजली वितरण कंपनियां जो कि दिल्ली सरकार की बहुत बडी रकम अपने पास रखती हैं, के बारे में सिन्हा की राय से सत्ता प्रतिष्ठान का इत्तेफाक नहीं था. इसलिए उन्होंने इससे अलग होना ठीक समझा. कारण जो भी हो, लेकिन चुनाव के ठीक कुछ महीने पहले एक सीनियर अधिकारी का जाना बाबू महकमे में हलचल मचा रहा है. ■

dilipcherian@gmail..com

साउथ ब्लॉक

नीरज वर्मा सड़क परिवहन एवं हाईवे के प्रमुख

असम मेघालय कैडर के 1994 बैच के आईएएस अधिकारी नीरज वर्मा सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के संयुक्त सचिव के पद पर नियुक्त किए जा सकते हैं. यह पद महाराष्ट्र कैडर की 1993 बैच की अधिकारी आभा शुक्ला के हटने के बाद से खाली है.

ईडी अधिकारियों का कार्यकाल बढ़ेगा

केंद्रीय सतर्कता आयोग की हालिया मीटिंग मेंप्रर्वतन निदेशालय के चार अधिकारियों का कार्यकाल बढ़ाने के मसले पर फैसला किया. केंद्रीय सतर्कता आयोग ने अनुज गोगिया (अतिरिक्त निदेशक, मुंबई), सुभाष अग्रवाल (उप निदेशक, बंगलोर क्षेत्रीय कार्यालय) और संजय भटनागर (संयुक्त निदेशक, जयपुर क्षेत्रीय कार्यालय) का कार्यकाल बढा दिया है, जबकि समीर बजाज (संयुक्त निदेशक, मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय) का मामला फिलहाल रोक लिया है.

राहुल भंडारी की मूल कैडर में वापसी

पूर्व रेल मंत्री पवन कुमार बंसल के निजी सचिव राहुल भंडारी, जिनकी सीबीआई जांच कर रही है, को उनके मूल कैडर में वापस भेज दिया गया है. वे पंजाब कैडर के 1997 बैच के अधिकारी हैं. सीबीआई ने हाल ही में रेलवे में पैसा लेकर अवैध नियुक्ति के मामले में उनकी भूमिका को लेकर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है.

अंजू शर्मा और जगदीश प्रसाद संयुक्त सचिव बने

गुजरात कैडर के 1991 बैच की अधिकारी अंजू शर्मा और जगदीश प्रसाद गुप्ता को संयुक्त सचिवों की सूची में शामिल किया गया है. अंजू फिलहाल गुजरात में महिला एवं बाल विकास विभाग में सचिव हैं और गुप्ता गांधीनगर में भू–राजस्व अधिकारी हैं.

प्रदीप कुमार जाएंगे रक्षा मंत्रालय

रक्षा मंत्रालय के निदेशक का पद शीघ्र भरा जाने वाला है. 1995 बैच के अधिकारी प्रदीप कुमार जल्द ही यहां बतौर निदेशक कार्यभार संभालेंगे. ■

चौथी दुनिया ब्यूरो feedback@chauthiduniya.com

जम्मू–कश्मीर में इस समय सांप्रदायिक दंगे से पैदा हुए हालात को नियंत्रित करने के लिए सकारात्मक कार्रवाई की आवश्यकता है. भड़काऊ बयानों और आरोपों से हालात अधिक ख़राब हो सकते हैं. नेताओं को चाहिए कि वे जम्मू–कश्मीर के साथ–साथ राज्य के हालात को बेहतर बनाने और हिंदू–मुस्लिमों के बीच पैदा हुई खाई पाटने के लिए प्रभावी भूमिका निभाएं.

किश्तवाड़ दंगा

कैसे पटेगी सांप्रदायिकता की खाई

जम्मू–कश्मीर के किश्तवाड़ में पिछले दिनों ईद के दिन निकले जुलूस के दौरान उपद्रव और नमाज़ पढ़ते लोगों पर पथराव के बाद दंगा भड़क उठा. एक स्थानीय घटना को तुरंत रोकने की बजाय अन्य इलाकों में फैलने दिया गया. सवाल यह है कि कैसे एक स्थानीय घटना पर काबू नहीं पाया जा सका और उसे अन्य इलाकों में फैलने दिया गया? क्या प्रशासन उपद्रवियों के सामने इतना पंगु है?

मोहम्मद हारून

जम्मू–कश्मीर एक बार फिर सांप्रदायिकता की आग की चपेट में है. इस बार मामला सांप्रदायिक दंगे का है, जिसकी शुरुआत मुसलमानों के पवित्र त्योहार ईद की सुबह से किश्तवाड़ में हुई. किश्तवाड़ समुद्र तल से 5360 फीट की ऊंचाई पर स्थित एक पहाड़ी क़स्बा है, जहां मुसलमानों और हिंदुओं की आबादी का अनुपात 52 और 48 प्रतिशत है. यहां ईद के दिन जुलूस निकाला गया और उसके बाद पथराव ने दंगे का रूप ले लिया. दंगे की शुरुआत एक साधारण मोटरसाइकिल दुर्घटना से हुई, लेकिन सच्चाई यह भी है कि कुछ शरारती तत्वों ने ईद की नमाज़ पढ़ रहे लोगों पर भी पथराव किया, जिससे नमाज में भगदड़ मच गई. यह मामूली–सा विवाद एक भयानक रूप धारण नहीं करता, अगर किश्तवाड़ की ग्रामीण सुरक्षा समितियों से जुड़े सशस्त्र सदस्य अपनी बंदूकें न तानते. मुस्लिम समुदाय ने बंदूकों की एक दुकान से हथियार लूट लिए और उन्हीं हथियारों से विरोधी पक्ष पर हमले भी किए. देर शाम तक दोनों समुदायों के दो लोग मारे गए और दोनों ही समुदायों के लोगों की करोड़ों रुपये की संपत्ति राख हो गई.

किश्तवाड़ में जो कुछ हुआ वह एक स्थानीय घटना थी. यदि प्रशासन इससे समय रहते निपट लेता तो दूसरे इलाकों में हिंसा नहीं फैलती. विडंबना है कि जिस समय यह उपद्रव हुआ, राज्य के गृह मंत्री सज्जाद अहमद किचलू भी वहीं पर थे. पुलिस के कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे, लेकिन उपद्रव शुरू हुआ और पूरा शहर आग की लपटों में जल उठा और उपद्रवियों को रोका नहीं जा सका. न सिर्फ दुकानों में जमकर आगजनी हुई, बल्कि जमकर लूटपाट और मारपीट हुई. पहले ही दिन करीब 150 दुकानों में आग लगा दी गई, 100 से ज्याद वाहनों में या तो तोड़फोड़ की गई या फिर उनमें आग लगा दी गई. बाद में सरकार ने ज़िला आयुक्त और एसएसपी को स्थिति पर नियंत्रण पाने में असमर्थ होने पर तुरंत तबादला कर दिया, लेकिन देर रात तक सांप्रदायिक दंगे की आग जम्मू के कई क्षेत्रों तक फैल चुकी थी. तब से दंगे और उपद्रव का सिलसिला जारी है.

आश्चर्य की बात यह है कि जम्मू-कश्मीर में 1989 से चरमपंथ जारी है और यह राज्य ढाई दशकों से हिंसात्मक घटनाओं की चपेट में है, लेकिन इससे पहले कभी भी इस तरह की हिंदू-मुस्लिम झड़पें नहीं हुईं. साल 2008 में पहली बार राज्य में हिंदू-मुस्लिम हिंसा हुई थी, लेकिन किसी को ज़िंदा नहीं जलाया गया और न ही दर्जनों दुकानें जलाई गईं.

हालात इतने ख़राब थे कि सरकार को जम्मू के 10 में से 8 ज़िलों में तुरंत कर्फ़्यू लगाना पड़ा और अन्य क्षेत्रों को पूर्ण रूप से फौजी छावनी में बदलना पड़ा. ख़बर लिखे जाने तक तीन लोग मारे जा चुके थे, सैंकड़ों लोग घायल हो चुके थे, दर्जनों दुकानें और गाड़ियां जलाई जा चुकी थीं और जम्मू के अधिकतर क्षेत्रों में कर्फ्यु जारी था. इसके साथ ही राज्य के गृह मंत्री से सरकार ने हालात पर क़ाबू न पाने के कारण इस्तीफ़ा ले लिया. दंगे के छठवें दिन भी किश्तवाड़ में कर्फ्यू लागू था और सेना लगी थी.

आश्चर्य की बात यह है कि जम्मू–कश्मीर में 1989 से चरमपंथ जारी है और यह राज्य ढाई दशकों से हिंसात्मक घटनाओं की चपेट में है, लेकिन इससे पहले कभी भी इस तरह की हिंदू–मुस्लिम झड़पें नहीं हुईं. साल 2008 में पहली बार राज्य में हिंदू–मुस्लिम हिंसा हुई थी, लेकिन किसी को ज़िंदा नहीं जलाया गया और न ही दर्जनों दुकानें जलाई गईं. फिर यह आज अचानक कैसे हुआ? मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की मानें, तो यह चुनावी राजनीति का खेल है. उन्होंने जम्मू में दंगे भड़कने के दूसरे दिन श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कड़े शब्दों में कहा कि कुछ राजनीतिक पार्टियां वोट बैंक की राजनीति के लिए हालात को बिगाड़ने की कोशिश कर रही हैं और मुझे लगता है कि यह 2008 जैसे हालात पैदा करने का षड्यंत्र है, ताकि उन्हें विधानसभा में वर्चस्व प्राप्त हो सके.

उन्होंने भाजपा की ओर इशारा करते हुए कहा कि मुझे मालूम है कि उन राजनीतिक पार्टियों के सदस्यों पर मेरी बातों का कोई असर नहीं होगा और मैं जानता हूं कि लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं, पर जनता को यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि 2008 के हालात से मौत और तबाही के अलावा कुछ हासिल नहीं हुआ. इसलिए मैं चाहता हूं कि राजनीतिक दल मानव हित पर अपने राजनीतिक हितों को तरजीह देना बंद करें और हिंसा के शोलों को न भड़काएं.

विश्लेषकों का कहना है कि भाजपा के वरिष्ठ नेता अरुण जेटली की ओर से दंगों के समय जम्मू में प्रवेश करना एक उत्तेजक क़दम था. जेटली को राज्य सरकार ने एयरपोर्ट से ही दिल्ली वापस भेज दिया. तारिक़ मीर के अनुसार, अरुण जेटली का जम्मू आना हालात को अधिक बिगाड़ने की एक कोशिश थी. मैं हैरान हूं कि जब जम्मू–कश्मीर में हिंसा की अन्य घटनाओं में लोग मारे जाते हैं, तो इस समय अरुण जेटली जैसे लोग यहां क्यों नहीं आते?

दरअसल, यहां आम राय यह है कि ग्रामीण सुरक्षा समीतियां हिंदू–मुसलमानों के बीच नफ़रत फैलाने का काम कर रही हैं. जम्मू में ये समीतियां 90 के दशक में चरमपंथ का मुक़ाबला करने के लिए गठित की गई थीं. ग्रामीण सुरक्षा समितियों के कुल 3287 सदस्यों में से 3174 का संबंध हिंदू समुदाय से है और हालिया घटित दंगों में भी कथित रूप से सुरक्षा समितियों के सदस्यों ने ही सक्रिय भूमिका निभाई. यही नहीं, किश्तवाड़ के पाडर क्षेत्र में एक व्यक्ति को पुलिस हिरासत से छीन कर उसकी हत्या कर दी गई, जिसका आरोप ग्रामीण सुरक्षा समिति के सदस्यों पर ही है. आश्चर्य की बात यह है कि किश्तवाड़ क्षेत्र में आज तक मुसलमानों और हिंदुओं के बीच कभी भी कोई ख़ूनी संघर्ष नहीं हुआ है.

गौरतलब है कि जम्मू–कश्मीर में कट्टरपंथी ताकतें हमेशा ही माहौल बिगाड़ने के प्रयास में रहती हैं. चुनाव के पहले ऐसी ताकतें खासतौर से सक्रिय हो जाती हैं. किश्तवाड़ में दंगा भड़कने के बाद जहां सभी दलों की ओर से शांति की कोशिश होनी चाहिए थी, वहीं पर उन्होंने इसके उलट व्यवहार किया गया. सभी दलों के नेताओं ने दूसरे को दोषी ठहराने वाले बयान दिए और स्थिति सुधारने की जगह आरोप–प्रत्यारोप का दौर चलता रहा. भाजपा, बजरंग दल और विहिप ने जम्मू क्षेत्र में तीन दिवसीय बंद का आ वान करते हुए जगह–जगह प्रदर्शन किया तो कश्मीर घाटी में हुर्रियत कान्फ्रेंस के कट्टरपंथी नेता सैयद अली शाह गिलानी और उदारवादी धड़े के नेता मीरवाइज उमर फारूक समेत सभी संगठनों ने बंद का आ वान किया. सभी तरफ से दूसरे समुदाय को दोषी ठहराने वाले बयान दिए गए. उधर, किश्तवाड़ में प्रशासन दंगाइयों को रोकने में नाकामयाब रहा. इस पहाड़ी क्षेत्र में दोनों समुदायों के लोग सदियों से सांप्रदायिक सौहार्द के साथ रहते आए हैं, लेकिन इस बार दोनों समुदायों के बीच एक गहरी खाई पैदा हो गई है, जिसे पाटना नामुमकिन नहीं, तो मुश्किल ज़रूर है. उल्लेखनीय है कि राज्य को क्षेत्रीय और धार्मिक बुनियादों पर बांटने का षड्यंत्र लंबे समय से जारी है और हालिया दंगे के दौरान शांतिप्रिय नागरिकों व सामाजिक कार्यकर्ताओं के बजाय सांप्रदायिकता को हवा देने वाले ही अधिक सक्रिय नज़र आए, जो चिंता का विषय है. दंगे पर वित्त मंत्री पी चिदंबरम के इस बयान पर भी घाटी में नेताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया दी, जिसमें उन्होंने कहा था कि इस बार 1990 की तरह लोगों को जबरन पलायन कराने की अनुमति नहीं दी जाएगी. चिदंबरम ने यह बयान जम्मू के सांप्रदायिक दंगे पर संसद में दिया था.

दरअसल, जम्मू–कश्मीर में इस समय सांप्रदायिक दंगे से पैदा हुए हालात को नियंत्रित करने के लिए सकारात्मक कार्रवाई की आवश्यकता है. भड़काऊ बयानों और आरोपों से हालात अधिक ख़राब हो सकते हैं. नेताओं को चाहिए कि वे जम्मू–कश्मीर के साथ–साथ राज्य के हालात को बेहतर बनाने और हिंदू–मुस्लिमों के बीच पैदा हुई खाई पाटने के लिए प्रभावी भूमिका निभाएं. ■

feedback@chauthiduniya.com

भारतीय राजनीति की इस तरह की गैर सोची–समझी कार्रवाईयों को लेकर आम नागरिक को यह जिज्ञासा हो सकती है कि यदि सरकार के कामकाज की मर्यादित आलोचना पर भी जेल हो सकती है, तो लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आजादी का क्या अर्थ है? यदि सत्ता में बैठे लोग कानून का मखौल उड़ाते हुए इस तरह की हरकतों को अंजाम देंगे, तो कानून का लागू किया जाना कौन सुनिश्चित करेगा?

इस सिस्टम में बोलना मना है...

यदि किसी देश में किसी नागरिक द्वारा अपनी सामान्य राय रखने पर उसे जेल भेज दिया जाए, तो यह न सिर्फ नागरिकों के मूल अधिकारों का उल्लंघन है, बल्कि यह प्रवृत्ति आने वाले समय में उस देश के लिए खतरे की घंटी है. फेसबुक अथवा इंटरनेट माध्यमों पर टिप्पणी को लेकर बंगाल में प्रोफेसर अंबिकेश महापात्र, कार्टूनिस्ट असीम त्रिवेदी और मुंबई में दो युवतियों की गिरफ्तारी के बाद अब दलित चिंतक कंवल भारती को गिरफ्तार किया जाना, बोलने की आजादी पर आने वाले इस संकट का एक और सबूत है.

कृष्णकांत

महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल के बाद अब उत्तर प्रदेश सरकार सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक पर आने वाली नागरिक टिप्पणियों से घबरा गई है. यह फिजूल की घबराहट ऐसी बौखलाहट में बदल गई कि एक दलित चिंतक कंवल भारती को सरकार की आलोचना में पोस्ट डालने पर गिरफ्तार कर लिया गया और अब उन पर रासुका लगाने तक की धमकी दी जा रही है. लेखक ने ऐसा क्या कह दिया कि गिरफ्तारी की नौबत आ गई, यह जानने के बाद कोई भी सिर्फ हैरान हो सकता है, क्योंकि लेखक को जिस–जिस टिप्पणी के लिए गिरफ्तार किया गया, उसमें सरकार की मात्र आलोचना भर थी. इस तरह की कार्रवाई का यह पहला मामला नहीं है. इसके पहले पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का कार्टून बनाकर मित्र को ईमेल भेजने वाले जाधवपुर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अंबिकेश महापात्र और उनके मित्र को जेल भेज दिया गया था. शिवसेना के पूर्व प्रमुख बाल ठाकरे की मौत के बाद मुंबई ठप हो जाने को लेकर एक युवती ने फेसबुक पर टिप्पणी की, तो उसे और उस पोस्ट को लाइक करने वाली एक अन्य युवती को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था. इसी तरह युवा कार्टूनिस्ट असीम त्रिवेदी को उनके कार्टूनों के आधार पर देशद्रोह के आरोप में जेल भेजा गया और उनकी वेबसाइट को बंद कर दिया गया.

इन सभी मामलों को देखकर तो यही लगता है कि इस लोकतांत्रिक मूल्यों वाले देश में सरकारें नागरिकों के मूलभूत अधिकार–बोलने की आजादी का गला घोंटने को लेकर प्रतियोगिता कर रही हैं. सहज जिज्ञासा हो सकती है कि इन टिप्पणियों में ऐसा क्या था कि सरकारें ऐसी कार्रवाई करने को मजबूर हुईं? इसका जवाब है कि उपर्युक्त सभी मामले कोर्ट में टिक नहीं सके, क्योंकि इन सभी टिप्पणियों में प्रशासन या सरकार की सामान्य आलोचना भर थी, जिसे लेकर ऐसी असहिष्णु कार्रवाइयां की गईं. आज जब दुनिया भर में सोशल साइटों और विभिन्न इंटरनेट माध्यमों पर नागरिक सक्रियताएं बढ़ रही हैं, लोग जागरूक हो रहे हैं, वे खुलकर सार्वजनिक मंचों से सरकारों की आलोचना करने लगे हैं, क्या इससे भारत में सत्ता पर काबिज लोग भयभीत हैं? इस तरह के हर मामले में प्रशासन की जबरदस्त फजीहत हुई, लेकिन यह सिलसिला थमता नहीं दिख रहा है. उस पर तुर्रा यह कि समय–समय पर सोशल मीडिया पर लगाम लगाने की बातें सरकारी महकमों में उठती रहती हैं. हालांकि, यह तब है, जब आज ज्यादातर नेता, मंत्री, यहां तक कि प्रधानमंत्री कार्यालय के भी आधिकारिक बयान ट्विटर पर जारी किए जाते हैं. हम सभी को यह पता है कि हम जिस तकनीकी युग में प्रवेश कर चुके हैं, वहां इंटरनेट और सोशल मीडिया पर नागरिकों की सक्रियता को अब रोका नहीं जा सकता. बावजूद इसके, सरकारें ऐसी हिमाकत भरी हरकतें कर रही हैं.

दलित चिंतक और लेखक कंवल भारती ने फेसबुक पर लिखा था–आरक्षण और दुर्गा शक्ति नागपाल, इन दोनों ही मुद्दों पर अखिलेश यादव की समाजवादी सरकार पूरी तरह फेल हो गई है. अखिलेश, शिवपाल यादव, आजम खान और मुलायम सिंह इन मुद्दों पर अपनी या अपनी सरकार की पीठ कितनी ही ठोंक लें, लेकिन जो हकीकत ये देख नहीं पा रहे हैं, (क्योंकि जनता से पूरी तरह कट गए हैं) वह यह है कि जनता में उनकी थू–थू हो रही है और लोकतंत्र के लिए जनता उन्हें नकारा समझ रही है. अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और बेलगाम मंत्री इंसान से हैवान बन गए हैं. ये अपने पतन की पटकथा खुद लिख रहे हैं. सत्ता के मद में अंधे हो गए इन लोगों को समझाने का मतलब है भैंस के आगे बीन बजाना.

उनकी दूसरी टिप्पणी थी–आपको तो यह ही नहीं पता कि रामपुर में रमजान सालों पुराना मदरसा बुलडोजर चलवाकर गिरा दिया गया और संचालक को विरोध करने पर जेल भेज दिया गया, जो अभी भी जेल में ही है. अखिलेश सरकार ने रामपुर में तो किसी भी अधिकारी को निलंबित नहीं किया. ऐसा इसलिए, क्योंकि रामपुर में आजम खान का राज चलता है, अखिलेश का नहीं. इन टिप्पणियों को लेकर किए गए एफआइआर में दूसरी टिप्पणी के अंतिम में एक अतिरिक्त वाक्य है–आजम खान रामपुर में कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि यह उनका क्षेत्र है और उन्हें खुदा भी नहीं रोक सकता है. इसे लेकर आजम खान के सचिव फसाहत अली खान ने रामपुर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई कि कंवल भारती ने रमजान माह में, आजम खान को खुदा भी नहीं रोक सकता, ऐसा कहकर खुदा की तौहीन की है. उनकी इस टिप्पणी से सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ सकता है. कंवल भारती पर दो वर्गों में वैमनस्य फैलाने के आरोप में धारा–153 ए और धार्मिक भावनाओं का अपमान करने के आरोप में धारा–295 ए लगाई गई. पुलिस ने छह अगस्त की सुबह उन्हें उनके घर से गिरफ्तार कर लिया. हालांकि उन्हें जब कोर्ट पेश किया गया, तो कोर्ट ने उन्हें जमानत देते हुए कहा कि फेसबुक पर टिप्पणी करना कोई अपराध नहीं है.

इस मसले पर लेखकों–कलाकारों के संगठन जन संस्कृति मंच की ओर से कहा गया कि भारती ने फेसबुक पर जो कुछ लिखा, उसे देखकर इस आरोप के फर्जीपन को समझा जा सकता है. जिस प्रदेश में दलितों पर भयावह अत्याचारों के खिलाफ प्राथमिकी तक दर्ज कराना दूभर हो, वहां जिस तत्परता के साथ भारती जैसे जुझारू दलित चिंतक के खिलाफ झूठे आरोप दर्ज कर कार्रवाई की गई. हाल के दिनों में, सोशल मीडिया पर टिप्पणी को लेकर कार्रवाई करने के कई मामले सामने आए हैं. सरकारें मानवाधिकार हनन और अभिव्यक्ति की आजादी का गला घोंटने में एक–दूसरे से होड़ ले रही हैं. उत्तर प्रदेश सरकार कंवल भारती से माफी मांगे और उन पर दर्ज मुकदमा वापस ले. अन्य संगठनों ने भी आंदोलन की धमकी देते हुए कंवल भारती के खिलाफ दर्ज मुकदमा वापस लेने की मांग की है.

इसके पहले मुंबई में युवतियों और असीम त्रिवेदी की गिरफ्तारी के मामले में भी कोर्ट ने गिरफ्तारी के आधार को ही बेबुनियाद बताकर उन्हें जमानत दी थी. इन दोनों मामलों में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश और प्रेस काउंसिल के अध्यक्ष मार्कंडेय काटजू ने तल्ख प्रतिक्रिया दी थी. युवतियों की गिरफ्तारी पर काटजू ने मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण को लिखा–हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, न कि किसी तानाशाही व्यवस्था में. हर व्यक्ति को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिली है. युवतियों ने मुंबई बंद का विरोध किया था, जो कोई अपराध नहीं है, बल्कि जिसने अपराध नहीं किया, उसे गिरफ्तार करना धारा 341 और 342 के तहत अपराध है. जिन पुलिसकर्मियों व अधिकारियों ने दोनों युवतियों की गिरफ्तारी की है, उन्हें निलंबित कर उनपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए. युवतियों आईटी एक्ट की धारा 66–ए के तहत गिरफ्तार किया गया था. इसके दुरुपयोग पर सवाल उठाती एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई इसके बाद सरकार ने दिशा–निर्देश जारी किया कि ग्रामीण क्षेत्र में पुलिस उपायुक्त और महानगरों में पुलिस महानिरीक्षक से नीचे रैंक के अधिकारी इस धारा के तहत गिरफ्तारी का आदेश नहीं दे सकते.

भारतीय राजनीति की इस तरह की गैर सोची–समझी कार्रवाइयों को लेकर आम नागरिक को यह जिज्ञासा हो सकती है कि यदि सरकार के कामकाज की मर्यादित आलोचना पर भी जेल हो सकती है, तो लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आजादी का क्या अर्थ है? यदि सत्ता में बैठे लोग कानून का मखौल उड़ाते हुए इस तरह की हरकतों को अंजाम देंगे, तो कानून का लागू किया जाना कौन सुनिश्चित करेगा? ■

feedback@chauthiduniya.com

व्यवस्था पर टिप्पणी के लिए वे मुझे आतंकी बताना चाहते हैं : कंवल भारती

आपने फेसबुक पर सरकार की आलोचना करते हुए टिप्पणी की थी. आप पर सांप्रदायिकता फैलाने का आरोप लगाकर आपको गिरफ्तार किया गया. इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है?

वह टिप्पणी किसी से छुपी नहीं है, जो मैंने सार्वजनिक तौर पर फेसबुक पर लिखी थी. उसके लिए वे मुझे आतंकी बताना चाहते हैं. मुझे तो कुछ मालूम ही नहीं था. छह तारीख को सुबह अचानक पुलिस आती है और कहती है कि आपके खिलाफ शिकायत है, आपको थाने चलना होगा. मैं बनियान और पजामे में था. उन्होंने मुझे कपड़ा तक नहीं पहनने दिया. न ही पुलिस ने मुझे यह सूचना दी कि वे किस आरोप में गिरफ्तार कर रहे हैं. बाद में जब मुझे कोर्ट में पेश किया गया, तो वहां पता चला कि मैंने जो फेसबुक पर टिप्पणी की थी, उसी को लेकर हमारे खिलाफ शिकायत की गई है. हालांकि, कोर्ट ने तुरंत जमानत दे दी और कहा कि फेसबुक पर टिप्पणी करना कोई अपराध नहीं है.

पुलिस आपका कम्प्यूटर भी ले गई है. आपने उसे वापस लेने के लिए अर्जी लगाई थी. वह मिल गया आपको?

अभी नहीं मिल सका. मेरी अर्जी के बाद कोर्ट ने रिपोर्ट मांगी तो पुलिस ने जवाब दिया कि उसे जांच के लिए लखनऊ भेज दिया है. मेरी समझ में नहीं आता कि मुकदमा किया फेसबुक से और ले गए कम्प्यूटर. कह रहे हैं कि उसकी हार्ड डिस्क चेक करेंगे. फेसबुक से उसकी हार्ड डिस्क में क्या आ सकता है? मेरे कम्प्यूटर में मेरे महत्वपूर्ण काम हैं. छह–सात किताबें हैं, 200 से 250 लेख हैं. वे कुछ पत्र–पत्रिकाओं में छपे हैं और कुछ छपने वाले हैं. वे वास्तव में यह देखना चाहते हैं कि हमने लिखा क्या–क्या है. वे उसे नष्ट कर सकते हैं.

मीडिया में रिपोर्ट आई कि आपको फोन करके रासुका लगाने की धमकी दी गई. क्या यह सही है?

मुझे व्यक्तिगत धमकी नहीं दी गई, लेकिन हमारे घर के आस–पास कई लोग हथियारों के साथ जब–तब घूमते दिख रहे हैं. वे मेरे परिवार को डराने के लिए ऐसा कर रहे हैं. रासुका लगाने को लेकर मुझे व्यक्तिगत तौर पर धमकी नहीं मिली, मेरे एक परिचित का फोन आया कि आजम खान के लोग पुलिस पर दबाव बना रहे हैं कि कंवल भारती पर रासुका लगाया जाए. उन्होंने थाने का घेराव किया और पुलिस से इस तरह की मांग की.

आप पर आरोप लगाया कि आपने कहा है– रामपुर में आजम का राज चलता है. उनको रोकने की मजाल तो खुदा में भी नहीं है. इससे खुदा की तौहीन हो गई है?

टिप्पणी आप सबने देखी होगी. मैंने कहा था कि रामपुर में सालों–साल पुराना मदरसा गिरवा दिया गया और वहां तो किसी पर कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि वहां आजम खां का राज चलता है. उनको रोकने की

मजाल तो खुदा में भी नहीं है, ऐसा कहने में कहां खुदा की तौहीन हो गई? यह तो एक मुहावरा है, जो आप आम बातचीत में इस्तेमाल करते हैं. खुदा की तौहीन तो मदरसा तुड़वाकर आजम ने की. वह समाजवादी चोले में लिपटा सांप्रदायिक आदमी है. उसका रवैया फासीवादी है. उसने 200 साल पुराना मदरसा तोड़वाया. यह पुरातत्व विभाग के नियमों का भी उल्लंघन है. आप सौ साल पुराने निर्माण को नहीं तोड़ सकते. मेरी बात से तो यहां के मुसलमान भी खुश हुए. सभी लोग खुश हुए.

आपकी टिप्पणी से ऐसा क्या खतरा पैदा हो गया कि उत्तर प्रदेश शासन को ऐसी कार्रवाई करनी पड़ी किया?

उनको मेरी टिप्पणी से नहीं, एक लेखक से खतरा है. इस पूरे प्रकरण में पूरी तरह आजम खान का हाथ है. अखिलेश यादव को हो सकता है कि शुरू में इस बारे में पता न रहा हो, लेकिन बाद में राष्ट्रीय मीडिया में खबरें आईं, तब भी कोई कार्रवाई नहीं हुई. पता नहीं सरकार की क्या मजबूरी है कि उसने आजम को ढो रही है. दरअसल, वे उसे मुसलमानों का नेता मानते हैं और मुसलमान वोट के लिए उसे इतना तवज्जो देते हैं, लेकिन वह मुसलमान नहीं है. वह मुसलमान होता, तो मदरसा नहीं तोड़ता.

क्या आजम खान से आपकी कोई निजी रंजिश है. वे ऐसा क्यों कर रहे हैं?

दरअसल, मदरसा गिराने की बात लिखकर मैंने आजम खान की दुखती रग पर हाथ रख दिया, इसलिए वे बौखला गए, लेकिन मेरे लिए यह आजम खान और कंवल भारती की लड़ाई नहीं है. यह लेखन की आजादी का मसला है. यह लेखकों और पत्रकारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मसला है. इसमें वे बुरी तरह पराजित होंगे.

इस पूरे प्रकरण में उत्तर प्रदेश सरकार की भूमिका को किस तरह देखते हैं? मामला सामने आने के बाद भी सरकार ने कोई संज्ञान नहीं लिया. क्या यह सब अखिलेश यादव की शह पर हो रहा है?

हां ऐसा माना जा सकता है, क्योंकि शुरू में तो सरकार आजम खान की हरकत से अनभिज्ञ रही होगी, लेकिन बाद में न उन्होंने मदरसा तोड़ने के मामले में जांच बिठाई, न ही मेरे मामले में कोई कार्रवाई की. सरकार आजम के दबाव में काम कर रही है.

ऐसे मामले पहले भी आ चुके हैं. मुंबई में दो युवतियों की गिरफ्तारी, बंगाल में जाधवपुर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अंबिकेश महापात्र की गिरफ्तारी और कार्टूनिस्ट असीम त्रिवेदी की गिरफ्तारी. इस प्रवृत्ति को किस रूप में देखते हैं आप?

देखिए, हमारे संविधान ने नागरिकों को बोलने का, अपनी बात कहने का मूलभूत अधिकार दिया है. हर कोई अपनी बात कह सकता है. अगर बोलने पर ही प्रतिबंध लगा दिया गया, तब तो देश से लोकतंत्र ही खत्म हो जाएगा. इससे तो फासीवाद आएगा. ■

आईएएस ही नहीं, दागी पीसीएस अफसरों को भी सपा सरकार ने गले लगा रखा है. पहले तो अखिलेश सरकार ने सीबीआई तक की जांचों में फंसे पीसीएस बादल चटर्जी, अनिल, राजकुमार, भवनाथ, अजय कुमार उपाध्याय, शहाबुद्दीन, भास्कर उपाध्याय, तनवीर जफर अली, चंद्रपॉल समेत करीब दो दर्जन अफसरों को आईएएस कैडर में प्रमोट किया. इसके बाद उन दागदार अफसरों को महत्वपूर्ण पदों पर तैनात भी कर दिया गया.

उत्तर प्रदेश शासन

जो भ्रष्ट है वही योग्य है

राज्य की राजधानी लखनऊ (मंडल) की कमान हो या समाज कल्याण आयुक्त की मलाईदार पोस्टिंग या फिर कानपुर के कमिश्नर का पद, लगभग हर जगह दागी ही काबिज हैं. बड़ा सवाल यह है कि दुर्गा नागपाल जैसे अधिकारी हासिये पर कर दिए जा रहे हैं और दागियों की तैनाती मलाईदार ओहदों पर हो रही है.

अजय कुमार

सपा सरकार जनता की कसौटी पर खरी नहीं उतर रही है. प्रदेश की जनता ने जिस विश्वास के साथ अखिलेश की ताजपोशी का रास्ता सशक्त किया था, वह सपना चकनाचूर हो गया है. समाजवादी पार्टी के मंत्री और नेता अमर्यादित भाषा बोल रहे हैं. बसपा, भाजपा, कांग्रेस जैसे विरोधियों के प्रति उनकी तल्खी तो समझ में आती है, लेकिन ईमानदार युवा नौकरशाहों, साहित्यकारों, समाजसेवियों, व्यापारियों के प्रति ही नहीं, आम जनता के प्रति भी उनकी अमानवीय सोच और बेरुखी अकल्पनीय लगती है. मंत्रियों की बदजुबानी सिर चढ़कर बोल रही है. सपा के पाले हुए गुंडों की दहशत है. कानून व्यवस्था गर्त में जा रही है. राज्य की जनता आए दिन होने वाले साम्प्रदायिक दंगों से थर्राई हुई है. समय-समय पर बसपा सुप्रीमो मायावती को तानाशाह का खिताब देने वाले सपाई अगर अपने गिरेबान में झांक कर देखें, तो उन्हें यह समझने में देर नहीं लगेगी कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और उनकी कैबिनेट के सहयोगी भी माया के नक्शे कदम पर चल रहे हैं. लोकतांत्रिक तरीके से उठने वाली आवाजें भी सपा नेताओं को सताने लगी हैं. तथ्यों से हट कर बात करने वाले सपाइयों में स्वार्थ की राजनीति तेजी से फल-फूल रही है. मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हों या सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव, महासचिव राम गोपाल यादव हों या फिर मंत्री आजम खां, शिवपाल जैसे पार्टी के कद्दावर नेता किसी को सपा के गिरते ग्राफ की चिंता नहीं है.

सच को झूठ और झूठ को सच साबित करने में महारथ हासिल किए सपाइयों को न तो मतदाताओं का भय है और न ही अदालतों का पहरा उनको सही राह दिखा पा रहा है. आंखें मूंद कर बैठे सपा नेता हकीकत को जाने बिना अपना गुणगान करते रहते हैं. समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता एवं जेल, खाद्य और रसद मंत्री राजेन्द्र चौधरी ने तो इस कृत्य में महारथ ही हासिल कर ली है. उनका तो एक सूत्रीय कार्यक्रम बन कर रह गया है झूठ का प्रचार. वह जब भी बोलते हैं, तो नश्तर से चुभते हैं. बार-बार एक ही बात दोहराना उनकी नियति बन गई है. ऐसा लगता है कि उनके द्वारा जारी प्रेस नोट में सिर्फ तारीख ही बदली जाती हो. अगर ऐसा न होता, तो वह बार-बार नहीं दोहराते जाते समाजवादी पार्टी सरकार की उपलब्धियों और जनता के बीच बढ़ती स्वीकार्यता से प्रदेश के विपक्षी दल इस तरह बैखलाए हुए हैं. वे अपना विवेक ही खो बैठे हैं. बसपा को जनता ने उसके पांच साल के कुशासन के फलस्वरूप सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया, जबकि कांग्रेस और भाजपा को तीसरे-चौथे क्रम में खड़े होने का प्रतियोगी बना दिया है. इन दलों का कोई भविष्य नहीं रह गया है.

जनता दोतरफा पिस रही है. नौकरशाही काम की जगह चापलूसी में ज्यादा समय बिता रही है. पिछले दो दशकों से उत्तर प्रदेश का काला इतिहास रहा है कि सत्ता पर जो भी दल काबिज होता है, अपने स्वार्थपूर्ति के लिए वह दागी और दबंग नौकरशाहों को अपनी गोद में बैठा लेता है. झूठे नौकरशाहों का बोलबाला होता है और ईमानदार अफसरों को प्रताड़ित होना पड़ता है. ईमानदार और कतर्व्यनिष्ठ अधिकारियों को आत्महत्या के लिए मजबूर किया जाता है. ऐसे अधिकारियों को वीआरएस थमाना और यूपी छोड़ने को मजबूर करना भी राजनीतिक हथकंडे का हिस्सा बन गया है.

राजीव कुमार

बादल चटर्जी

फतेह बहादुर सिंह

विजय शंकर पांडेय

राजीव कुमार

नीरा यादव

उत्तर प्रदेश का यह दुर्भाग्य ही है कि एक ईमानदार एसडीएम को सांप्रदायिक तनाव की आड़ लेकर निलबंन की तलवार से हासिये पर डाल दिया जाता है, तो राज्य की राजधानी लखनऊ (मंडल) की कमान एक ऐसे भ्रष्ट आईएएस संजीव शरण को थमा रखी है, जो अरबों के प्लॉट आवंटन घोटाले की सीबीआई जांच में फंसें है.

धन लक्ष्मी

राकेश बहादुर

संजीव शरण

मनोज सिंह

शरण के पास पर्यटन विभाग के प्रमुख सचिव और डीजी का भी कार्यभार है. इसी तरह प्लॉट आवंटन के कारण सीबीआई के शिकंजे में आए एक और दागी आईएएस अधिकारी राकेश बहादुर को समाज कल्याण आयुक्त की मलाइदार पोस्टिंग दी जाती है. नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेस-वे अथॉरिटी के चेयरमैन के अहम पद पर तैनात रमारमण लोकायुक्त जांच में फंसे हैं. रमण पर बसपा राज के दौरान फॉर्म हाउस घोटाले में भी संगीन आरोप हैं. मुख्यमंत्री के सचिव आईएएस अधिकारी आलोक कुमार पर सिडकुल घोटाले में गंभीर आरोप लगे थे और उसकी जांच भी हुई थी. आज की तारीख में वह अवैध खनन के मामले में न केवल आरोपों से घिरे हुए हैं, बल्कि अदालत ने उन्हें नोटिस भी भेज रखा है.

बसपा काल में तमाम घोटालों के लिए बदनाम रहे आईएएस महेश कुमार गुप्ता को कानपुर के कमिश्नर का रुतबा हासिल है. महेश सूचना भर्ती घोटाले में सीबीआई से चार्जशीटेड तक हो चुके हैं. मायावती सरकार के दौरान आबकारी आयुक्त के पद पर विराजमान होकर महेश गुप्ता ने शराब माफिया पोंटी चड्ढा को काफी मजबूती प्रदान की थी. माया के बाद सपा सरकार में भी महेश का कद कम नहीं हुआ है. आईएएस चंचल तिवारी ओर धनलक्ष्मी जैसे घोटालेबाज भ्रष्ट अफसर 4600 करोड़ के ट्रोनिका सिटी घोटाले की एसआईटी जांच में आरोपी हैं. सीबीआई और ईडी के पास भी इनका मामला पड़ा हुआ है. आईएएस धनलक्ष्मी के दिल्ली स्थित आवास से तो सीबीआई करीब सवा तीन करोड़ का काला धन बरामद भी कर चुकी है, लेकिन ईडी ने अभी तक धनलक्ष्मी के खिलाफ जांच नहीं शुरू की है. अखिलेश सरकार ने उन्हें जिलाधिकारी अमेठी बना रखा है. युवा सीएम ने भ्रष्ट आईएएस अफसर चंचल तिवारी को वाराणसी का कमिश्नर बना रखा है. चंचल के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई और ईडी की जांच चल रही है. सपा राज में दागी आईएएस राजीव कुमार (द्वितीय) को भी काफी ताकत मिली हुई है. सपा सरकार ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी राजीव को यूपी का प्रमुख सचिव (नियुक्ति) बना रखा है. उन्हीं के हस्ताक्षर से दुर्गा शक्ति नागपाल को निलंबित किया गया था. नोएडा प्लॉट आवंटन घोटाले में राजीव कुमार एक सजायाफता अधिकारी हैं. यह वही मामला है, जिसमें यूपी की पूर्व मुख्य सचिव नीरा यादव को जेल जाना पड़ा था. फिलहाल, उनकी अपील पर हाईकोर्ट ने उनकी सजा पर रोक लगा रखी है. प्रमुख सचिव नियुक्ति रहकर राजीव कुमार ने कई घोटालों को अंजाम दिया था. राजीव को अखिलेश सरकार ने अपनी कोर टीम में रख छोड़ा है.

आईएएस ही नहीं, दागी पीसीएस अफसरों को भी सपा सरकार ने गले लगा रखा है. पहले तो अखिलेश सरकार ने सीबीआई तक की जांचों में फंसे पीसीएस बादल चटर्जी, अनिल, राजकुमार, भवनाथ, अजय कुमार उपाध्याय, शहाबुद्दीन, भास्कर उपाध्याय, तनवीर जफर अली, चंद्रपॉल समेत करीब दो दर्जन अफसरों को आईएएस कैडर में प्रमोट किया. इसके बाद उन दागदार अफसरों को महत्वपूर्ण पदों पर तैनात भी कर दिया गया. ताजा उदाहरण लखनऊ के एसएसपी जे रवींद्र गोड़ का है, जिनके खिलाफ सीबीआई ने बरेली फर्जी मुठभेड़ मामले में अभियोजन मंजूरी मांग रखी है, लेकिन सरकार ने इस पुलिस अफसर को बचाने के खातिर अभी तक जांच की मंजूरी नहीं दी है. ऐसे में अक्षम पुलिस कप्तानों के जरिये पूरे प्रदेश की कानून व्यवस्था को बिगाड़ने के प्रयास भी हो रहे हैं. एक और भ्रष्ट आईएएस अफसर हैं मनोज कुमार सिंह, जिनके खिलाफ नियुक्ति घोटाले समेत तमाम गंभीर आरोप हैं, लेकिन सरकार ने इस भ्रष्ट अफसर को प्रमोट करके प्रमुख सचिव के पद पर मलाइदार तैनाती दे रखी है. आईएएस मनोज कुमार सिंह के खिलाफ सीबीआई ने पीलीभीत में संजय गांधी ट्रस्ट में अनियमितताओं के मामले में अभियोजन मंजूरी मांग रखी है. इसी तरह करोड़ों के मनरेगा घोटाले में फंसे आईएएस सच्चिदा नंद दुबे, हृदयेश कुमार, पीसीएस बी राम, राजबहादुर, समेत तमाम भ्रष्टों का बाल बांका तक नहीं हुआ. इतना ही नहीं, बसपा सरकार में भी तमाम घोटालों की जांचों में फंसे दागी आईएएस विजय शंकर पांडेय, फतेह बहादुर, नेतराम अनिल संत, समेत तमाम भ्रष्टों को महत्वपूर्ण पदों पर बैठाया गया है. बसपा राज में पुलिस भर्ती घोटाले में गिरफ्तार हो चुके कई आईएएस अधिकारियों पर भी सपा सरकार मेहरबानी बनाए हुए है.

उत्तर प्रदेश की अखिलेष सरकार भ्रष्टाचार के मामले में ढुलमुल रवैया अपना रही है. यह बात आम जनता और विपक्षी दलों के नेता ही नहीं कह रहे हैं. इस बात से सुप्रीम कोर्ट तक चिंतित है. इसीलिए पिछले दिनों उच्चतम न्यायालय को भ्रष्टाचार के लंबित मामलों का त्वरित निपटारा करने के लिए सीबीआई की अतिरिक्त विशेष अदालतें गठित करने का आदेश नये सिरे से जारी करना पड़ गया. सर्वोच्च अदालत इस बात से खफा है कि इसके पूर्व के आदेशों को अखिलेश सरकार ने गंभीरता से नहीं लिया. बहरहाल, सपा सरकार जिस बेढंगी चाल से आगे बढ़ रही है, उससे आम जनता के बीच यही संदेश जा रहा है कि राज्य सरकार भ्रष्टाचारियों को सजा दिलाने के मामले में गंभीर नहीं है. समाजवादी सरकार के मुखिया अखिलेश यादव अक्सर कहते हैं कि वह अपने घोषणा पत्र के सभी वायदों को जल्द से जल्द पूरा करेंगे, लेकिन बात जब भ्रष्ट नौकरशाहों और नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की आती है, तो उनकी सरकार काफी पीछे दिखती है. ऐसा लगता है कि अखिलेश यादव ने भ्रष्टाचार से समझौता कर लिया है. अगर ऐसा न होता, तो भ्रष्टाचार के दलदल में फंसे बाबू सिंह कुशवाहा सपा के करीब न आते और ईमानदार कर्तव्यनिष्ठ आईएएस दुर्गा नागपाल की यह दशा न होती. खैर, सपा सरकार की छवि लगातार गिरती जा रही है. यूपी में सत्ता के कई केन्द्र होने का नुकसान भी सरकार को उठाना पड़ रहा है. समय आ गया है कि युवा सीएम अपनी और सरकार की फजीहत से बचने के लिए वोट बैंक की राजनीति से ऊपर उठकर कुछ सख्त फैसले ले. युवा मुख्यमंत्री को अपनी इमेज सुधारने के लिए ब्यूरोक्रेसी और बेलगाम नेताओं, दोनों की ही लगाम खींच कर रखनी होगी. ■

जनता दोतरफा पिस रही है. नौकरशाही काम की जगह चापलूसी में ज्यादा समय बिता रही है. पिछले दो दशकों से उत्तर प्रदेश का काला इतिहास रहा है कि सत्ता पर जो भी दल काबिज होता है, अपने स्वार्थपूर्ति के लिए वह दागी और दबंग नौकरशाहों को अपनी गोद में बैठा लेता है. झूठे नौकरशाहों का बोलबाला होता है और ईमानदार अफसरों को प्रताड़ित होना पड़ता है.

feedback@chauthiduniya.com

पद्म पुरस्कारों को लेकर यह सवाल खड़ा होता है कि इन पुरस्कारों की सीमा में आम आदमी क्यों नहीं आता. यूनाइटेड नेशन ने देश की ऐसी कई शख्सियतों को सम्मानित किया है, जो प्रचार की आस से परे दूर–दराज के क्षेत्रों में सामाजिक उत्थान की भूमिका में हैं, लेकिन देश में उन्हें कोई पहचान नहीं है. हाल का उदाहरण लें, तो मेरठ की एक किशोरी रजिया सुल्ताना को अपने गांव के कुछ बच्चों को बाल मजदूरी से मुक्त कराकर शिक्षा के लिए भेजने जैसे सराहनीय काम को पहचान दिया, लेकिन देश में उसे कोई सराहना नहीं मिली.

एक बार फिर

पुरस्कारों में पारदर्शिता का प्रश्न

पद्म पुरस्कारों पर विवाद कोई नई बात नहीं है, लेकिन हर बार सवाल चयनित नामों को लेकर हुआ इस बार विवाद चयन की प्रक्रिया को सार्वजनिक करने को लेकर है. हालांकि इस बात को लेकर कोई बहस की गुंजाइश नहीं है कि प्रतिभा की पहचान का मामला सब्जेक्टिव होता है, जिसको लेकर कई मत हो सकते हैं, लेकिन अगर इस चुनाव की प्रक्रिया को सार्वजनिक बना दिया जाए और जिन्हें चुना जा रहा है, उनकी शख्सियत को लोगों से पहले ही साझा किया जाए, तो इसमें विवाद की गुंजाइश काफी कम हो सकती है. हालांकि सरकार ने सूचना आयुक्त के इस पत्र को ठंढे बस्ते में डालकर एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि इस देश में आम आदमी की रायशुमारी संभव नहीं है.

नीरज सिंह

पद्म पुरस्कार के पीछे का खेल एक बार फिर सुर्खियों में है, लेकिन सुर्खियां इस बार किसी पुरस्कृत की योग्यता को लेकर नहीं, बल्कि उसके चयन प्रक्रिया को सार्वजनिक करने की मांग को लेकर है. देश के मुख्य सूचना आयुक्त सत्यानंद मिश्र ने हाल ही में केंद्रीय गृहमंत्री को इस आशय का पत्र लिखा है कि कई वर्षों से देश की जनता इस बात को लेकर रोष जता रही है कि पद्म पुरस्कारों के नामित लोगों की सूची, उनके चयन की प्रक्रिया, उनके चयनित होने की योग्यता व उनसे जुड़ी अन्य जानकारियां उन्हें पुरस्कृत करने से पहले गृह मंत्रालय की वेबसाइट पर अपडेट कर आम जनता से साझा की जाए. बावजूद इसके, गृह मंत्रालय ने इस बाबत अभी तक कोई भी जानकारी अपनी बेवसाइट पर अपडेट नहीं की है.

मंत्रालय के इस कदम से एक बार फिर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि इस देश में आम आदमी को कुछ भी जानकारी देने की नीयत सरकार की नहीं है. सरकार ने कई बार यह साबित भी किया है. इस संदर्भ में हाल का उदाहरण सामने है. राजनीतिक पार्टियां खुद सूचना के अधिकार के दायरे में न आएं, इसके लिए विधेयक पास करने की तैयारी हो चुकी है.

वास्तव में इस जानकारी की मांग लंबे समय से उठ रही है कि जिन लोगों नाम पद्म पुरस्कारों के लिए नामित हो रहे हैं, आम जनता उनके बारे में जाने. दुनिया भर के सभी बड़े पुरस्कारों व सम्मान में यह सार्वजनिक सूचना दी जाती है. नोबेल पुरस्कारों के लिए नामित लोगों की सूचना तो तकरीबन एक वर्ष पहले ही दे दी जाती है, लेकिन भारत में सरकारें पद्म पुरस्कारों में नामित व्यक्तियों की सूचना हर बार यह कह कर देने से मना करती रही है कि इससे गोपनीयता का हनन होता है और इसी गोपनीयता के हनन को पर्दा बनाकर प्राय: ऐसे नाम भी सामने आते हैं, जो इन पुरस्कारों की प्रतिष्ठा को ही सवालों के घेरे में खड़ा कर देते हैं. 2013 के पद्मश्री के सम्मान की सूची में एक ऐसे व्यक्ति का नाम भी था, जो वेट लॉस क्लीनिक चलाते हैं और कई सारे वीवीआईपी और मंत्री–सांसद उनकी सेवाएं लेते हैं. मीडिया में उस वक्त खबरें आई थीं कि सात कैबिनेट मिनिस्टर व दस राज्य मंत्रियों ने उनके नाम का अनुमोदन किया था. इस तरह कई बार इन पुरस्कारों में ऐसे नाम शामिल हुए, जिनको लेकर कहा गया कि यह व्यावसायिक लाभ के लिए किया गया है और जिस तरह से इन पुरस्कारों का प्रयोग राजनीतिक लाभ के लिए किया जा रहा है, ऐसे में इस बात की संभावनाओं से इंकार नहीं किया जा सकता कि इस सूची में श्रीमान ओसामा बिन लादेन जी और हाफिज सईद साहब के नाम शामिल हो जाएं.

दूसरा मसला पुरस्कृत होने वाले नामों के चयन की प्रक्रिया और निर्णायक मंडल को लेकर है. सर्वोच्च न्यायालय ने बालाजी राघवन–एस.पी. आनंद बनाम भारत सरकार (1996 (1) एससीसी 361) प्रकरण पर अपने निर्णय में कई निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि पद्म पुरस्कार पाने के हकदार व्यक्तियों के चयन के लिए राष्ट्रीय चयन समिति गठित की जाए, जिसमें लोकसभा अध्यक्ष, भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके प्रतिनिधि, लोकसभा में विपक्ष के नेता आदि को शामिल किया जाना चाहिए. चूंकि इन पुरस्कारों का इस्तेमाल नेताओं ने अपने व्यापारिक हितों व व्यक्तिगत संबंधों को साधने में शुरू कर दिया, इसलिए इन सुझावों को नजरअंदाज किया जा रहा है. इस वर्ष की शुरुआत में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ में दायर एक याचिका में यह मांग भी की गई थी कि इन पुरस्कारों को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय को सर्वोच्च न्यायालय के सुझाव पर अमल करते हुए राष्ट्रीय चयन समिति का गठन तथा मात्रात्मक एवं गुणात्मक अर्हता निर्धारित करने का निर्देश देना चाहिए.

एक और मुद्दा, जिसे लेकर फिलहाल अभी तक बड़ी बहस नहीं शुरू हुई है, वह यह कि पद्म पुरस्कारों के लिए निर्धारित फॉर्म के एक कॉलम में धर्म व जाति (एससी/एसटी/ओबीसी/सामान्य) का जिक्र किया गया है. भारतीयता से जुड़े पुरस्कार में इस कॉलम के क्या मायने हैं, यह समझ से परे है और वह तब, जबकि भारतीय संविधान में उल्लेखित मूल अधिकारों में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद के प्रतिषेध की भावना निहित है. ऐसे पुरस्कार, जो राष्ट्रीयता के लिए दिए जा रहे हैं, उनमें धर्म व जाति की जानकारी लेना कहीं से भी उचित नहीं है.

पद्म पुरस्कारों को लेकर एक और सवाल खड़ा होता है कि इन पुरस्कारों की सीमा में आम आदमी क्यों नहीं आता. यूनाइटेड नेशन ने देश की ऐसी कई शख्सियतों को सम्मानित किया है, जो प्रचार की आस से परे दूर–दराज के क्षेत्रों में सामाजिक उत्थान की भूमिका में हैं, लेकिन देश में उन्हें कोई पहचान नहीं है. हाल ही का उदाहरण लें, तो मेरठ की एक किशोरी रजिया सुल्ताना को अपने गांव के कुछ बच्चों को बाल मजदूरी से मुक्त कराकर शिक्षा के लिए भेजने जैसे सराहनीय काम को पहचान देते हुए संयुक्त राष्ट्र ने सम्मानित किया और पहला मलाला अवॉर्ड देने की घोषणा की. भारत सरकार ने इस बच्ची की कोई सुध नहीं ली, न तो कभी सार्वजनिक मंचो से उसके इस प्रयास को कोई सराहना ही मिली. आपको याद होगा, पिछले वर्ष एक टेलीविजन चैनल को दिए गए साक्षात्कार में जब कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से यह सवाल किया गया कि किसे इस साल का इंडियन ऑफ द ईयर चुना जाना चाहिए, तो उनका जवाब था आम आदमी, लेकिन वह आदमी अब केवल भाषणों की शोभा बढ़ाने और गरीबी के आंकड़े पेश करने के लिए उदाहरण भर रह गया है. बुसान एशियाड में स्नूकर खेल में स्वर्ण पदक विजेता यासीन मर्चेंट ने पद्म पुरस्कारों में चयनित लोगों की योग्यता पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी को पत्र लिखकर और उसे सार्वजनिक करते हुए लिखा था कि न तो मेरी राजनीतिक पहुंच है और न पुरस्कार खरीदने की क्षमता है. इन सवालों का जवाब न तो सोनिया गांधी या राहुल गांधी के पास है और न ही किसी दूसरी सरकार के पास.

पद्म पुरस्कारों के चयन में पारदर्शिता लाने के लिए 1996 में उपराष्ट्रपति के पद पर रहते हुए के. आर. नारायणन ने एक उच्च स्तरीय प्रिव्यू कमेटी बनाई थी. और फिर 2004 में तो इन पुरस्कारों को लेकर इतना विवाद हुआ कि पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम को इस मामले में हस्तक्षेप करना पड़ा था. उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से इसमें अनियमितता दूर करने को कहा था, लेकिन हर बार की तरह मसला वही ढाक के तीन पात होकर रह गया था.

सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह पुरस्कार केवल राजनीतिक फायदे के लिए ही हैं या इनके कुछ सामाजिक मायने भी हैं. 2009 में भी श्रीनगर के एक शॉल व्यापारी को कला की कैटिगरी में पद्मश्री दिए जाने की कड़ी आलोचना हुई थी. 2011 इंडियन टौबेको कंपनी (आईटीसी) के अध्यक्ष वाईसी देवेश्वर को पद्म भूषण दिए जाने पर कुछ संस्थाओं ने गंभीर सवाल उठाया है. खासतौर से इससे नाराज तंबाकू विरोधी लॉबी का कहना था कि कंपनी भले ही दूसरे कई उत्पाद बनाने लगी हो, पर इसकी ज्यादातर कमाई तो सिगरेट बेचने से ही हो रही है. पद्मश्री गुलाम मोहम्मद मीर के बारे में बताया जा रहा है कि वे जम्मू–कश्मीर में पुलिस के मुखबिर थे.

पद्म पुरस्कारों को लेकर मंत्रालय से जुड़े सूत्र बताते हैं कि इसमें केवल ब्यूरोक्रेट्स की मनमानी चलती है. एक अनुमान के मुताबिक, सम्मानितों के तकरीबन 75 प्रतिशत नाम यहीं से तय कर लिए जाते हैं. बाद में इसी लिस्ट में कुछ नामों की श्रेणी बदल कर मसलन पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण के लिए जिन्हें नामित किया गया, उनमें थोड़ा बहुत फेरबदल कर के लिस्ट राष्ट्रपति भवन को भेज दी जाती है. यह बड़ी विडंबना है कि इस कमेटी के सदस्यों के चयन की योग्यताओं और प्रक्रिया के बारे में भी किसी को कुछ मालूम नहीं है. साफ है कि नौकरशाहों की इन पुरस्कारों में मनमानी इसलिए चल पाती है, क्योंकि सत्तारूढ़ दल के नेताओं ने इन्हें अपने खास लोगों को उपकृत करने का जरिया बना लिया है.

हालांकि इस बात को लेकर कोई बहस की गुंजाइश नहीं है कि प्रतिभा की पहचान का मामला सब्जेक्टिव होता है, जिसको लेकर कई मत हो सकते हैं, लेकिन अगर इस चुनाव की प्रक्रिया को सार्वजनिक बना दिया जाए और जिन्हें चुना जा रहा है, उनकी शख्सियत को लोगों से पहले ही साझा किया जाए, तो इसमें विवाद की गुंजाइश काफी कम हो सकती है. पद्म पुरस्कारों के चयन का तरीका बदलकर भी ऐसे किसी विवाद से बचा जा सकता है. नोबेल पुरस्कार की तरह इसे एक साल–ाना प्रक्रिया में बदल दिया जाए और जो नाम आएं, सभी मंत्रालय और राज्य सरकारों से विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लोगों के नाम मंगवा कर पूरे वर्ष भर उनका विश्लेषण किया जाए. इससे इन पुरस्कारों की चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी.

दरअसल, सूचना आयुक्त ने गृह मंत्रालय को जो पत्र लिखा है, वह केवल उनकी मांग नहीं है. उन्होंने पत्र में खुद लिखा है कि देश की जनता लंबे समय से आयोग को यह पत्र भेजकर मांग कर रही है कि इस पूरी प्रक्रिया को सार्वजनिक किया जाए, लेकिन जब इन पुरस्कारों को लेकर यह व्यवस्था तक नहीं है कि जिन्हें यह सम्मान दिया जा रहा है, उनको अग्रिम सूचना दी जाए या उनसे सहमति ली जाए कि क्या उनके बारे में आम लोगों को जानकारी देने का कोई तंत्र बनाया जाएगा. जब इन पुरस्कारों के आयोजकों में इतना शिष्टाचार नहीं है कि किसी वयोवृद्ध साहित्यकार को पद्म भूषण लेने के लिए राष्ट्रपति भवन में बुलाया जाए, लेकिन कार्यक्रम में अकेले न जा सकने के कारण उन्हें घुसने न दिया जाए, तो यह उम्मीद करना बेमानी ही है कि मंत्रालय यह सभी सूचनाएं आम जनता से साझा करेगा. मुख्य सूचना आयुक्त के इस पत्र को नजरअंदाज कर गृह मंत्रालय ने अपनी नीयत जता भी दी है. ■

feedback@chauthiduniya.com

सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह पुरस्कार केवल राजनीतिक फायदे के लिए ही हैं या इनके कुछ सामाजिक मायने भी हैं. 2009 में भी श्रीनगर के एक शॉल व्यापारी को कला की कैटिगरी में पद्मश्री दिए जाने की कड़ी आलोचना हुई थी. 2011 इंडियन टोबैको कंपनी (आईटीसी) के अध्यक्ष वाईसी देवेश्वर को पद्मभूषण दिए जाने पर कुछ संस्थाओं ने गंभीर सवाल उठाया है. खासतौर से इससे नाराज तंबाकू विरोधी लॉबी का कहना था कि कंपनी भले ही दूसरे कई उत्पाद बनाने लगी हो, पर इसकी ज्यादातर कमाई तो सिगरेट बेचने से ही हो रही है.

सत्यानंद मिश्र
मुख्य सूचना आयुक्त
Satyananda Mishra
Chief Information Commissioner

सत्यमेव जयते

कक्ष नं. 306, द्वितीय तल, अगस्त क्रांति भवन,
भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली – 110066
CENTRAL INFORMATION COMMISSION
ROOM NO. 306, 2ND FLOOR,
AUGUST KRANTI BHAWAN,
BHIKAJI CAMA PLACE, NEW DELHI-110066

D.O.No.431/CIC (SM)/2013 Dated : May 31, 2013

Dear Shri Shinde,

As you are aware, the Right to Information Act, 2005 was enacted with the main objective of providing effective access to information to the citizens of India and to bring in transparency and accountability in Government functioning.

2. Recently, with the conferment of Padma Awards, the Central Information Commission has been receiving various requests for disclosure of norms regarding list of nominations, selection procedure, eligibility criteria, and other such details concerning the selection of Padma awardees.

3. As you are aware, in pursuance of the objectives of the RTI Act, 2005, the constant endeavour of Government Departments and every public authority is to take steps to provide as much information suo-moto at regular intervals through various means of communication, including the internet, so, that the public have minimum resort to use of the Act to obtain information.

4. In view of the above mentioned facts, I therefore, request you to kindly issue instructions to your Ministry to post all relevant details of information regarding procedure for selection of Padma Awardees in your Departmental website at the earliest as well as the details of the nominations received for the Awards in 2012-13, minutes of the Selection Committee and the approval(s) of the various authorities.

With kind regards

Yours sincerely,

(Satyananda Mishra)

Shri Sushilkumar Shinde,
Hon'ble Minister of Home Affairs,
Ministry of Home Affairs,
North Block,
New Delhi-110001

> विवाद उभरने का तात्कालिक कारण मालिनी अवस्थी को ब्रांड एमबेस्डर बनाया जाना ही रहा. इसके विरोध में ख्याति प्राप्त भोजपुरी गायक भरत शर्मा व्यास और गायक सह अभिनेता मनोज तिवारी ने अकादमी के द्वारा दिये गये सम्मान को लौटाने की घोषणा की है.

अपनी मर्जी की मालिक भोजपुरी अकादमी

बिहार भोजपुरी अकादमी के अध्यक्ष हैं डॉ. प्रो रविकांत दुबे. इनका कार्यकाल अब खत्म होने वाला है, लेकिन अध्यक्ष जी जाते-जाते अपनी और बिहार सरकार की छीछालेदर करवा रहे हैं. वैसे विवाद से इनका पुराना रिश्ता है. फेसबुक प्रोफाइल को लेकर भी वह विवाद में रह चुके हैं. 2011 में भोजपुरी विकास मंच द्वारा उनके खिलाफ धरना भी दिया गया था और उन्हें बर्खास्त करने और उन पर न्यायिक जांच की मांग भी की जा चुकी है.

शशि सागर

बिहार भोजपुरी अकादमी ने मालिनी अवस्थी को अंतरराष्ट्रीय सांस्कृतिक राजदूत बनाया है. अकादमी ने जो रिलीज जारी किया है, इसमें कहा गया है कि आप उन्हें अकादमी का ब्रांड एम्बेस्डर भी कह सकते हैं. भोजपुरी का एक बड़ा वर्ग मालिनी अवस्थी को ब्रांड एम्बेस्डर बनाये जाने का विरोध कर रहा है. इससे पहले जुलाई महीने में अकादमी ने अंतरराष्ट्रीय भोजपुरी महोत्सव करवाया था. इस महोत्सव को लेकर भी कई तरह के विवाद सामने आये थे. आयोजन में बुलाये जाने वाले लोगों और जिन 21 लोगों को अकादमी ने सम्मानित किया था, उन पर सवाल किये जा रहे हैं. कार्यक्रम के दौरान ही लोग यह भी कह रहे थे कि अपने ही कार्यक्रम में खुद अध्यक्ष राज्यपाल के हाथों क्यों सम्मानित हो रहे हैं. चल रहे रंगारंग कार्यक्रम के दौरान दर्शक दिर्घा में बैठे लोग भी बार-बार यह कहते हुए पाये गये कि आखिर अकादमी ने भोजपुरी के इतने बड़े आयोजन में शारदा सिन्हा को क्यों नहीं बुलाया. आयोजन में चर्चित युवा गायिका देवी के नहीं होने पर भी लोग आश्चर्य जता रहे थे. सूत्र बताते हैं कि कार्यक्रम से पहले उन्होंने कार्यकारिणी की बैठक तक नहीं की. कार्यकारिणी को यह भी नहीं पता था कि किन-किन लोगों को सम्मानित किया जाना है.

वैसे विवाद उभरने का तात्कालिक कारण मालिनी अवस्थी को ब्रांड एमबेस्डर बनाया जाना ही रहा. इसके विरोध में ख्याति प्राप्त भोजपुरी गायक भरत शर्मा व्यास और गायक सह अभिनेता मनोज तिवारी ने अकादमी के द्वारा दिये गये सम्मान को लौटाने की घोषणा की है. पूरे प्रकरण पर बातचीत के दौरान भरत शर्मा बड़े ही सख्त लहजे में कहते हैं कि रविकांत दुबे जब से अकादमी के अध्यक्ष बने हैं, सत्यानाश ही कर रहें हैं भोजपुरी का. जब हमारे घर में शारदा सिन्हा जैसी भोजपुरी में सशक्त पहचान रखने वाली गायिका हैं तो, उन्हें मालिनी को बुलाने की क्या आवश्यकता पड़ गई. भरत शर्मा ने बताया कि जब मैंने सम्मान लौटाने की घोषणा की तो रविकांत दुबे ने फोन कर नारजगी जाहिर की और कहा कि मैं तो आपको सम्मानित ही नहीं करना चाह रहा था. एक तो सम्मानित भी किया और अब हमारे ही खिलाफ बोल भी रहे हैं. भोजपुरी समाज में इस बात को लेकर भी गुस्सा है कि आखिर क्यों रविकांत दुबे अपनी पसंद-नापसंद को बिहार के माथे पर थोप रहे हैं, लेकिन दुबे अपने पक्ष में तर्क गढ़ते हुए कहते हैं कि भोजपुरी अकादमी को एक महिला ब्रांड एम्बेस्डर की जरूरत थी. एक ऐसी महिला जो आचार-व्यवहार, पहनावे-ओढावे से सुसंस्कृत हो और अकादमी ने इस मापदंड पर मालिनी जी को खरा पाया. शारदा सिन्हा क्यों नहीं, इस सवाल पर दुबे कहते हैं कि शारदा जी आद-रणीय हैं, लेकिन अकादमी की भी अपनी सीमा है. यह भी कहते हैं कि मालिनी देश-विदेश का दौरा कर भोजपुरी का प्रचार-प्रसार करेंगी और शारदा जी से इस उम्र में यह सब नहीं हो सकेगा. आखिर कब तक शारदा जी को आप लोग ढोयेंगे. हैरत की बात यह है कि जहां रविकांत दुबे अपने निर्णय को सही ठहराते हैं, वहीं यह भी जानकारी मिलती है कि खुद रविकांत दुबे ने षारदा सिन्हा के घर फोन कर उनके पति से यह कह कर माफी भी मांगी है कि हमने निर्णय तो ले लिया है, लेकिन अगर दीदी (शारदा सिन्हा) को बुरा लगा तो उनसे माफी मांगते हैं.

यह पूछने पर कि मनोज तिवारी भी आपके निर्णय का विरोध कर रहे हैं, दुबे कहते हैं कि किस मनोज की बात करते हैं आप, वह हमारी सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है. वह यूपी में चुनाव लड़ा था, हार गया और अब इस फिराक में हैं कि बिहार से भाजपा उसे टिकट दे दे. इसलिए यह नौटंकी कर रहा है. अंत में दुबे दंभ के साथ यह कहना नहीं भूलते हैं कि हमसे पहले कौन अध्यक्ष था, उसने क्या कुछ किया था, किसी को मालूम भी है. यह पूछे जाने पर कि इन तीन सालों में अकादमी ने क्या प्रकाशन किया है, दुबे हत्थे से उखड़ते हुए फोन रख देते हैं कि हमें और भी बहुत काम है, लेकिन इन मसलों पर शारदा सिन्हा कहती हैं कि देखिये मालिनी जी अच्छी गायिका हैं. उन्होंने जो काम किया है वह काबिले तारीफ है, लेकिन अकादमी के क्रिया कलापों को देखकर दुख होता है कि सरकार ने अपने एक विभाग को खुला छोड़ दिया है कि वह जो मन है करे. आज जब सरकार बिहारी स्मिता को उभारने का काम कर रही है, ऐसे में किसी दूसरे राज्य से कलाकार को लाकर ब्रांड एम्बेस्डर बना देना कहां तक जायज है, बिहार की भोजपुरिया मांटी में कलाकारों की कोई कमी है क्या. एक बार भोजपुरिया समाज से उसकी इच्छा तो जान लेता अकादमी. वहीं अंतरराष्ट्रीय भोजपुरी विकास मंच के अध्यक्ष बीएन तिवारी उर्फ भाईजी भोजपुरिया कहते हैं कि शारदा जी पद्मश्री हो चुकी हैं. अकादमी की नजर में उनका कद ब्रांड एम्बेस्डर से कहीं ज्यादा ऊंचा है. यही वजह है कि अकादमी ने उनकी बजाय मालिनी जी को चुना है, लेकिन इन तमाम विवादों के बीच कुछ सवाल तो अकादमी के अध्यक्ष से जरूर पूछे जाने चाहिए. अकादमी को यह तो बताना ही चाहिए कि आखिर क्यों उसने अपने कार्यक्रम में भोजपुरी की कालजयी उपन्यास फुलसुंघी के लेखक पांडे कपिल को सम्मानित नहीं किया. दुनिया में भिखारी को स्थापित करने वाले और भिखारी पर पहला शोध करने वाले तैयब हुसैन पीड़ित भी उन्हें कभी नहीं याद आये. भोजपुरी साहित्य सम्मेलन नामक पत्रिका का प्रकाशन करने वाले ब्रजकिशोर को भी उन्होंने नहीं सम्मानित किया. इन तीन सालों में अकादमी ने भोजपुरी गायन की हस्ताक्षर रहीं विंध्यवासिनी को भी यादा नहीं किया. 1948 में आई फिल्म नदिया के पार के आठो गानों के गीतकार मोती बीए को भी इन सालों में कभी याद नहीं किया गया. 2011 में महेश्वराचार्य का देहांत हुआ था. उन्हीं की वजह से आज देश दुनिया भिखारी को जानती है. हैरत की बात यह है कि अकादमी को इतनी भी फुर्सत नहीं थी कि एक श्रद्धांजलि सभा आयोजित करती. सबसे अहम बात यह है कि यह भिखारी ठाकुर की 125वीं जयंती का साल चल रहा है. इन तीन सालों में न तो बिहार सरकार और न ही अकादमी ने इनके नाम पर कोई आयोजन कराना उचित समझा, जबकि बिहार केसरी श्री कृष्ण सिंह और बिहार विभूती अनुग्रह नारायण सिंह के 125वीं जयंती साल पर पूरे सूबे में कई आयोजन हुए और पूरा साल ही अमृत वर्ष घोषित कर दिया गया. अब यहां सवाल यह उठता है कि आखिर अकादमी ने इन तीन सालों में ऐसा क्या किया, जिससे भोजपुरी समाज फर्क से अपना माथा ऊंचा करे. ■

feedback@chauthiduniya.com

कमीशन की रिपोर्ट

अफसपा का हो रहा है गलत इस्तेमाल

मणिपुर में आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट (अफसपा) वर्षों से लागू है, जिसकी आड़ में सुरक्षा बल फर्जी मुठभेड़ों को अंजाम देते रहे हैं. अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी यह कह दिया है कि अफसपा का गलत इस्तेमाल हो रहा है. ऐसे में इस एक्ट का बने रहना कितना उचित है?

एस. बिजेन सिंह

भारत सरकार अपनी जनता की हिफाजत करने में पूरी तरह से नाकाम रही है. आए दिन भ्रष्टाचार और घोटालों से सरकार की किरकिरी होती रहती है. लगता ही नहीं कि भारत में कोई सरकार काम कर रही है, क्योंकि जनता के अधिकारों और उसके हितों का पूरा ख्याल सुप्रीम कोर्ट को रखना पड़ रहा है. जनता को भी इस बात का भान हो चुका है कि सरकार उसके लिए कुछ नहीं कर सकती, इसीलिए वह न्याय की आस में कोर्ट का दरवाजा खटखटाती है. समझ में नहीं आता कि इतने बड़े अमले और लाव-लश्कर के साथ सरकार कर क्या रही है. जब हर काम कोर्ट के दखल के बाद ही होगा, तो इस अकर्मण्य और अपाहिज सरकार का क्या काम.

कुछ ऐसा ही हाल है आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट (अफसपा)-1958 का, जिसकी सुनवाई अब सुप्रीम कोर्ट करने लगी है. गौरतलब है कि 15 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने छह मुठभेड़ों के मामले में एक फैसला सुनाया. सारे मुठभेड़ फर्जी थे. दो संस्थाओं एक्सट्रा जूडिशिएल एक्जीक्यूशन विक्टीम फेमिलीज एसोसिएशन (एएवीएफएएम) और ह्यूमन राइट्स एलर्ट ने एक पीटिशन सितंबर 2012 को सुप्रीम कोर्ट को दिया था. इस पीटिशन में लिखा था कि 1979 से 2012 तक मणिपुर में मुठभेड़ की 1528 घटनाएं हुई थीं, जिन पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई. उन संस्थाओं की मांग है कि इन मुठभेड़ों की जांच-पड़ताल सुप्रीम कोर्ट करे. पीटिशन के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने तीन लोगों का एक कमीशन बनाया था, जिसके चेयरमैन हैं सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस संतोष हेगड़े. इस कमेटी में पूर्व चीफ इलेक्शन कमिश्नर जी एम लिंगदोह और कर्नाटक के पूर्व डीजीपी अजय कुमार सिन्हा भी शामिल हैं. कमीशन ने पहले छह केस की जांच शुरू की थी. इंफाल क्लासिक होटल में 3 से 7 मार्च तक कमीशन की बैठक हुई थी. इसके बाद दिल्ली में 13 से 21 मार्च तक बैठक कर कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को 12 सप्ताह में अपनी रिपोर्ट दिया था.

बहरहाल, जिन छह लोगों पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, उनमें हैं-एमडी आजाद खान (4-3-2009), खुमबोंगमयुम ओरसोनजीत सिंह (16-3-2010), नामैराकपम गोविंद मैतै (4-4-2009) और नामैराकपम नोवो मैतै (4-4-2009), इलांगबम किरणजीत सिंह (24-4-2009), चोंगथाम उमाकांता (5-5-2009), अकोयजम प्रियोबर्ता (15-3-2009). इनमें आजाद खान स्कूली बच्चा है. आजाद को उसके मां-बाप के सामने उसके घर से घसिट कर ले जाकर गोली मारी गई. बच्चे की लाश के पास से पिस्टल भी मिला. मणिपुर पुलिस कमांडो और असम रायफल्स की तरफ से यह कहा गया कि वह आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त था. उसके पास से हथियार पिस्टल और ग्रेनेड आदि बरामद हुआ है. आपको जानकर ताज्जुब होगी कि जिस दिन इस बच्चे को मारा गया, उस दिन उसके स्कूल रजिस्टर में उसकी उपस्थिति दर्ज दिखाई गई है, जो एक बड़ा सवाल है. हैवानों की हद देखिए कि जब बच्चे का पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आया, तो पता चला कि उसे छह गोलियां मारी गई थीं.

कमीशन की रिपोर्ट के केंद्र में अफसपा ही है. अफसपा को हटाने के लिए जो जीवन रेड्डी कमेटी गठित की गई थी, उस रिपोर्ट को भी कमीशन ने सही ठहराया. अफसपा की आड़ में कई जगहों को अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया, ताकि वहां आर्मी का दखल हो सके. आए दिन हत्याओं की खबरें आती रहती हैं, जिसकी जितनी भर्त्सना की जाए, कम है. एसपी द्वारा कमांडो के कार्यों पर नजर रखी जानी चाहिए. जिला स्तर पर पुलिस कंप्लेंट कमेटी बनाना चाहिए. कमेटी में जन प्रतिनिधि की हिस्सेदारी होनी चाहिए. गैरकानूनी कामों पर सीआईडी को अपनी जिम्मेदारी लेनी होगी. लंबे अर्से से रख रहे अफसपा को हटाने की दिशा में काम होना चाहिए. मुठभेड़ में मारे गए लोगों की छानबिन पुलिस द्वारा अच्छी तरह की जानी चाहिए. एनकाउंटर में मारे गए लोगों का पोस्टमॉर्टम होने में काफी देरी हो जाती है, जिससे रिपोर्ट में छेड़-छाड़ का मौका मिल जाता है और महत्वपूर्ण सुराग गायब हो जाता है, इसलिए वीडियोग्राफी के साथ पोस्टमॉर्टम होना चाहिए. फोरेंसिक एनालिसिस होनी चाहिए, ताकि फिंगर प्रिंट का पता चल सके. सबसे अहम बात यह है कि पुलिस कमांडो द्वारा गोलीबारी में जो लोग मारे गए हैं, उसके जवाब में वह यह बयान देते हैं कि उन्होंने अपने डिफेंस में गोली चलाया है, यह उचित नहीं है. सच तो यह है कि अफसपा दूसरे देशों से रक्षा के लिए बनाया गया कानून है.

एनकाउंटर के मामले में उत्तर प्रदेश के बाद मणिपुर का दूसरा स्थान है. राज्य में कुल 60 असम रायफल्स कंपनी, 37 सीआरपीएफ कंपनी और 12 बीएसएफ कंपनी तैनात है. मणिपुर की जनता खासकर युवा, हिंसा से काफी हद तक प्रभावित है. वहां पटाखे की आवाज से भी लोगों को डर लगता है. भले ही वह बम-बारूद या गोलीबारी न हो. साधारण सी आवाज को सुनकर भी घरों में लोग छुप जाते हैं. हिंसा की वजह से यहां के नौजवान देश के बाकी हिस्सों से या दूसरे राज्यों से किसी भी क्षेत्र की प्रतिस्पर्धा में शामिल भी नहीं हो पाते. गोलीबारी, बम धमाका यहां के लिए आम बात है. एक समय ऐसा भी था, जब वहां का युवा घर से बाहर नहीं निकलता था. चारों तरफ डर का माहौल होता था. इंडियन आर्मी और मणिपुर पुलिस कमांडों दोनों का डर इन नौजवानों को हमेशा सताता रहता था. मुठभेड़ में न जाने कितनी महिलाओं का सुहाग उजड़ गया, जिनके लिए परिवार का बोझ ढोना बहुत मुश्किल हो जाता है. 2004 में थांगम मनोरमा को इंडियन आर्मी द्वारा घर से पकड़ लिया गया था. इंसानियत उस समय शर्मसार हो गई, जब पहले उसके साथ दुष्कर्म किया गया और बाद में उसको गोली मार दी गई. मनोरमा पर आरोप था कि वह आतंकवादी संगठन की सदस्य है. मनोरमा की घटना के विरोध में उस समय 10 महिलाओं ने असम रायफल्स के गेट पर नग्न प्रदर्शन किया था. भारत जैसे लोकतंत्र के लिए इससे शर्मनाक घटना भला और क्या हो सकती है. 23 जुलाई, 2009 को रवीना और संजीत को सरेआम सड़क पर मारा गया था. संजीत को पीपल्स लिबरेशन आर्मी का सदस्य बताया गया था. इरोम शर्मिला राज्य से अफसपा हटाने के लिए पिछले 12 सालों से भूख हड़ताल पर है, लेकिन बहरी सरकार के कानों तक अहिंसात्मक आंदोलन की आवाज आज तक नहीं पहुंची.

ह्यूमन राइट्स एलर्ट के एक्जीक्यूटिव डाइरेक्टर बब्लू लोइतोंगबम ने कहा है कि यह रिपोर्ट कमीशन ने 8 अप्रैल, 2013 को सुप्रीम कोर्ट में भेज दिया था और 15 जुलाई को पीड़ित के पीटिशनर को दिया गया. अगला हियरिंग 17 सितंबर को होगा. वह कहते हैं कि इतने दिनों से अफसपा लागू है, लेकिन स्थिति बद से बदतर हो गई है, ऐसे में अफसपा के लागू होने का मतलब नहीं समझ में आता. बब्लू कहते हैं कि यह रिपोर्ट कम से कम अफसपा को हटाने का एक अच्छा मौका है. इस रिपोर्ट से उम्मीद का दरवाजा खुला है, जिसे बंद नहीं होने देना चाहिए. ■

sbijensngh@gmail.com

> एनकाउंटर के मामले में उत्तर प्रदेश के बाद मणिपुर का दूसरा स्थान है. राज्य में कुल 60 असम रायफल्स कंपनी, 37 सीआरपीएफ कंपनी और 12 बीएसएफ कंपनी तैनात है. मणिपुर की जनता खासकर युवा, हिंसा से काफी हद तक प्रभावित है. वहां पटाखे की आवाज से भी लोगों को डर लगता है. भले ही वह बम-बारूद या गोलीबारी न हो.

www.kamalmorarka.com

कमल मोरारका

यह मायने नहीं रखता कि सरकार किसकी बन रही है. कोई भी सरकार सत्ता में आए, हमें संविधान में उल्लेखित सिद्धांतों पर चलना ही होगा. सरकार को गरीबों के हित में सोचना होगा. छात्रों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, महिलाओं व अल्पसंख्यकों के हितों के बारे में सोचना होगा. कॉर्पोरेट तरीके से चलकर यह हासिल नहीं हो पाएगा.

संविधान के रास्ते से भटकता देश

एक बार फिर देश ने स्वतंत्रता दिवस मनाया. हर बार की तरह इस बार भी अखबारों–पत्रिकाओं में स्वतंत्रता दिवस के संदर्भ में लेख लिखे गए और इस बात पर भी चर्चा हुई कि क्या मुल्क का विभाजन होना चाहिए था? क्या होता अगर भारत का विभाजन न हुआ होता?

इस मसले पर भारत की भूमिका और इसे लेकर जो भी बातचीत अंग्रेजों से हुई थी, वह देश के लिए रोचक हो सकती है, लेकिन आधुनिक संदर्भों में देखें, तो अब इस बहस का कोई औचित्य नहीं है कि विभाजन होना चाहिए था या नहीं. विभाजन अब इतिहास बन चुका है और यही हकीकत है. भारत और पाकिस्तान, दोनों ही मुल्कों को एक अच्छे पड़ोसी के तौर रहना होगा और दोनों देशों की अवाम को यह सोचना होगा कि उनके बीच संबंध और बेहतर कैसे बनें. वास्तव में स्वतंत्रता के मायने क्या हैं? यह हम सभी को, फिर चाहे वे राजनेता हों, अन्य लोग हों, औद्योगिक घरानों के मुखिया हों, या सिविल सोसाइटी के लोग हों, सभी को एक बार फिर से इस प्रश्न पर विचार करना चाहिए. क्या हम उसी राह पर चल रहे हैं जैसा कि संविधान में उल्लिखित है या 1952 से लेकर आज तक संविधान के सभी भाग को धीरे–धीरे विकृत कर रहे हैं. विकृत इस रूप में कि कागजों पर तो हम संविधान के मुताबिक चल रहे हैं, लेकिन हकीकत कुछ और है.

उदाहरण के लिए, संविधान में इस बात का उल्लेख है कि सरकार का चुनाव कैसे होता है और उसके कर्तव्य क्या हैं. सरकार की भूमिका क्या हो, यह भी स्पष्ट है कि चुनी हुई सरकार नीतियां बनाए, वह चाहे राजनीतिक हो, आर्थिक हो या सामाजिक, लेकिन उनका क्रियान्वयन प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से होना चाहिए. इनमें भारतीय प्रशासनिक सेवा व दूसरी सेवाओं के अधिकारी हैं, जो एक कठिन प्रक्रिया के बाद चयनित होते हैं. इन सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से कुशल लोगों का चयन होता है. इसलिए इन नीतियों के क्रियान्वयन के लिए ये अधिकारी सबसे बेहतर साबित हो सकते हैं, लेकिन क्या उनका सही इस्तेमाल हो रहा है? नहीं! दुर्भाग्य से जो भी राजनीतिक दल चुनकर आए, उन्होंने छोटे–छोटे मुद्दों पर ही अपनी रुचि दिखाई, न कि बड़े व जरूरी विषयों पर. कोई भी राजनीतिक दल उन आधारभूत विसंगतियों को बदलना नहीं चाहता, जो समूचे देश में व्याप्त हैं. उदाहरण के तौर पर, जब विभाजन हुआ, तो दुर्भाग्य से जिन्ना ने विभाजन धर्म के आधार पर किया और पाकिस्तान का निर्माण भारत में रह रहे मुस्लिमों के लिए हुआ, लेकिन उसी दिन से, जिस दिन से विभाजन हुआ, यह बात स्पष्ट हो गई थी कि भारत में उससे ज्यादा मुस्लिम रह गए, जितने कि विभाजन के बाद पाकिस्तान गए. यह क्या दर्शाता है? और जो मुस्लिम भारत में ही रह गए, उन्होंने यहीं पर रहने को क्यों तरजीह दी? क्योंकि महात्मा गांधी, जवाहर लाल नेहरु, सरदार पटेल, मौलाना आजाद ने देश की जनता को यह आश्वासन दिया था कि पाकिस्तान एक इस्लामिक राष्ट्र हो सकता है, लेकिन भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बना रहेगा और सरकार देश के नागरिकों के लिए धर्म को कभी आधार नहीं बनाएगी. धर्म एक व्यक्तिगत मसला है. इसका केवल इतना–सा मतलब है कि आप ईश्वर को बस किसी और नाम से याद कर रहे हैं. आप कहीं इसे भगवान कह सकते हैं, कहीं अल्लाह, कहीं जीजस क्राइस्ट, तो कहीं वाहे गुरु. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उन्हें किस नाम से बुला रहे हैं, लेकिन क्या हम उस भावना के साथ चल रहे हैं? अगर मैं मुसलमान होता (जो कि मैं नहीं हूं) और भारत में रह रहा होता, तो निराश होता, क्योंकि देश के महान नेताओं ने जो वादा किया था, उसे बाद की सरकारों ने निभाया नहीं. हां, यह सही है कि सबने हमें केवल वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया. इस देश की कुल आबादी का 15 प्रतिशत हिस्सा मुस्लिमों का है, लेकिन उनकी सहभागिता क्या है, यह बड़ा सवाल है. भारतीय प्रशासनिक सेवाओं में दो प्रतिशत, भारतीय पुलिस सेवा में दो प्रतिशत और कॉर्पोरेट जगत में तो बमुश्किल एक या दो प्रतिशत. फिर उन्हें क्या हासिल हुआ? साफ है कि मुसलमानों के साथ समानता का व्यवहार नहीं हुआ. उन्हें बराबर के अवसर नहीं मिले. उन्हें शिक्षा नहीं मिल पाई. ज्यादातर मुसलमान आज भी अनपढ़ हैं, अशिक्षित हैं. यह एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है. और कोढ़ में खाज जैसी स्थिति तो तब बन जाती है, जब देश की मुख्य विपक्षी पार्टी यह कहती है कि हमारी सरकार मुस्लिम तुष्टिकरण की नीति अपना रही और उन्हें ज्यादा अनुदान दे रही है. हालांकि यह वास्तविकता नहीं है. भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, एक समाजवादी और लोकतांत्रिक देश है. अब यह बेहद जरूरी है कि मौजूदा सरकार या 2014 के चुनावों के बाद चुनी जाने वाली नई सरकार संविधान में उल्लेखित नीति निर्देशक सिद्धांतों का पालन करे, जिसकी कि इस समय पूरी तरह से अनदेखी की जा रही है.

यह मायने नहीं रखता कि किसकी सरकार बन रही है. कोई भी सरकार सत्ता में आए, हमें संविधान में उल्लेखित सिद्धांतों पर चलना ही होगा. सरकार को गरीबों के हित में सोचना होगा. छात्रों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, महिलाओं व अल्पसंख्यकों के हितों के बारे में सोचना होगा. कॉर्पोरेट तरीके से चलकर यह हासिल नहीं हो पाएगा.

गरीबी के बारे में जो आंकड़े आ रहे हैं, वे मुझ जैसे व्यक्ति को शर्म से सिर झुकाने को मजबूर कर रहे हैं. मैंने कभी गरीबी नहीं देखी, लेकिन मेरी यह समझ में नहीं आता कि कोई यह कैसे कह सकता है कि पांच रुपये या 12 रुपये में पेट भरा जा सकता है. यह शर्मनाक है. आंकड़े महत्वपूर्ण नहीं है, जरूरी यह है कि हमें गरीबों के लिए जरूर कुछ करना चाहिए. कांग्रेस पार्टी ने मनरेगा और हालिया खाद्य सुरक्षा जैसे कार्यक्रमों की शुरुआत की है, लेकिन यह न तो व्यवस्थित हैं और न ही उन्हें सही ढंग से संचालित किया जा रहा है. इन योजनाओं के नाम पर बेशुमार पैसा खर्च हो रहा है. बेशक, यह योजनाएं सही दिशा में उठाया गया कदम है, लेकिन मनरेगा और खाद्य सुरक्षा विधेयक में जिस तरह पैसा बहाया जा रहा है, उसके लिए बड़े आर्थिक आधार की जरूरत है और इसके बिना इसे लागू नहीं किया जा सकता. योजना आयोग के पास प्रधानमंत्री के रूप में एक सबसे विश्वसनीय मुखिया है और प्रधानमंत्री के लिए यह सबसे जरूरी वक्त है कि वे एक व्यवहारिक नीति बनाएं. यह भी सोचना होगा कि हम किस तरह से सबसे निचले तबके या गरीब तबके को मध्यम वर्ग की श्रेणी में ले आएं. अमीर और अमीर हो रहे हैं, यह कोई समस्या नहीं है, लेकिन गरीब अभी भी वहीं है, जहां पहले था, जबकि देश के सकल घरेलू उत्पाद में भी बढ़ोत्तरी हो रही है.

देश का मध्यम वर्ग बेहतरी के रास्ते पर है और आपके इर्द–गिर्द मॉल, मोटर गाड़ी, अच्छी सड़कों व विदेशी ब्रान्ड की चमक–दमक है, लेकिन यह उस आदमी की किसी भी तरह से मदद नहीं कर सकतीं, जिसके पास जमीन नहीं है. भूमिहीन श्रमिक अभी भी भूमिहीन श्रमिक ही है और गांव का गरीब व्यक्ति अभी भी गरीब है. वह केवल टीवी पर उभरती हुई तस्वीरों के माध्यम से ही इस चमक को देख सकता है और वह उसके भीतर टीस पैदा करती हैं. इस दौर में संविधान के अनुपालन की बेहद जरूरत है. ■

feedback@chauthiduniya.com

शोषण मुक्त भारत की स्थापना

ठाकुर दास बंग

हम सब ऐसा करें और प्रथम कदम के तौर पर इस गांधी–जयन्ती से यानी 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक इस शोषण में से और गुलामी में से मुक्त होने के लिए मुक्ति सप्ताह देश भर में मनाएं. प्रथम दिन यानी 2 अक्टूबर को हम गांव–गांव में इकट्ठा होकर, उपवास कर, आत्म–शुद्धि करें, प्रभातफेरी निकालें और ग्राम–स्वराज्य की प्रतिज्ञा आम सभा में लें. तीसरे दिन शराब से मुक्त होने का, चौथे दिन कम्पोस्ट खाद के निर्माण का एवं सफाई का, पांचवे दिन गाय–बैलों को रक्षा का और पर्यावरण की सुरक्षा का दिन मनाएं. छठे दिन यानी 7 अक्टूबर को गांव के उद्योग–धन्धों को तथा गांव के स्वावलंबन का धक्का पहुंचाने वाले केंद्रित उद्योगों की वस्तुओं के बहिष्कार का संकल्प ग्राम वासी व्यक्तिगत एवं जहां संभव हो, वहां सामुदायिक रूप से लें. 1. कपड़ा, टेरीलीन, टेरीकॉट आदि कृत्रिम वस्त्रों का बहिष्कार का प्रारम्भ, 2. मिल का तेल, 3. मिल की चीनी, 4. केंद्रित उद्योग बने जूता–चप्पल, 5. मिल का साबुन तथा 6. रासायनिक खाद के बहिष्कार का तो 7 अक्टूबर को संकल्प लिया जाए और उनसे संबद्ध ग्रामोद्योगों के उत्पादन की योजना गांव–गांव में एवं क्षेत्र में बने. सप्ताह के अंतिम दिन यानी 8 अक्टूबर, 2013 को असहयोग आंदोलन–दिवस मनाया जाए. इस दिन गांव से बाहर का यानी शहरों से सारा लेन–देन, खरीद–बिक्री एवं व्यवहार बन्द रहे. ग्रामीण शोषण के खिलाफ संघर्ष प्रारम्भ करने के संकेत के तौर पर 8 अक्टूबर को एक दिन के लिए बाहर से सारी खरीद–बिक्री बन्द हो. कोई ग्राम वासी अपना माल शहरों को न बेचे और न उनसे माल खरीदे. शोषणकारी व्यवस्था को चेतावनी देने के लिए और अपने अन्दर आत्म शक्ति जगाने के लिए प्रतीक के तौर पर यह असहयोग–दिन है. बाद में उपयुक्त समय पर इससे अधिक दिनों का असहयोग किया जाना चाहिए और आखिर में आन्दोलन के अंतिम पर्व में मांग पूरी होने तक आन्दोलन चलना चाहिए.

दो अक्टूबर से ग्रामीण शोषण के विरुद्ध शुरू होने वाला यह आन्दोलन धर्मयुद्ध है. इसलिए ग्रामवासियों को उपवास द्वारा यानी आत्मशुद्धि द्वारा इस आन्दोलन का प्रारम्भ करना चाहिए. तुलसी–रामायण में प्रसंग आता है विभीषण की उस मनोदशा का, जब वह रावण की अपार शक्ति और रामचन्द्र जी की रथविहीन दुर्बलता को देखकर विजय के बारे में शंकायुक्त बन गया था. उन्होंने कहा भी, नाथ न रथ नहिं तन पद त्राना. केहि विधि जितब बीर बलवाना. केंद्रित अर्थ सत्ता की और उसकी सहायक राज्य सत्ता की अपार संगठित शक्ति को देखकर सामान्य ग्रामवासी के मन में विभीषण सरीखी शंका निर्माण हो सकती है. इस पर रामचन्द्र जी ने जो उत्तर दिया, वह भी ध्यान में रखा जाना चाहिए. उन्होंने कहा, सुनहु सखा कह कृपानिधाना, जेहिं जय होई सो स्यन्दन आना. सौरज धीरज तेहि रथ चाका. सत्य सील दृढ़ ध्वजा पताका इत्यादि. उन्होंने कहा कि हे सखा विभीषण, जिससे जय होता है, वह दूसरा रथ है. उसके पहिये पराक्रम और धीरज हैं और सत्य एवं शील उसकी ध्वाजा–पताका हैं. आगे वे कहते हैं, सखा धर्ममय अस रथ जाकें, जीतन कहं न कतहुं रिपु तांके. जिसके पास में यह धर्ममय रथ है उसको कोई जीत नहीं सकता. इस प्रकार इस धर्मयुद्ध में ग्रमीणों को भगवान का आश्वासन प्राप्त है, क्योंकि उनकी मांग न्याय संगत है. प्रसंग वश उनकी संख्या भी बहुत अधिक है और सारी आवश्कताओं को वे निर्मित करते हैं. इसलिए नि:शंक होकर हर ग्राम वासी को एवं इससे सहानुभूति रखने वाले नगर वासी को इस धर्मयुद्ध में हिस्सा लेकर शोषण मुक्त भारत की स्थापना करनी चाहिए. ■

दो अक्टूबर से ग्रामीण शोषण के विरुद्ध शुरू होने वाला यह आन्दोलन धर्मयुद्ध है. इसलिए ग्रामवासियों को उपवास द्वारा यानी आत्मशुद्धि द्वारा इस आन्दोलन का प्रारम्भ करना चाहिए. तुलसी–रामायण में प्रसंग आता है विभीषण की उस मनोदशा का, जब वह रावण की अपार शक्ति और रामचन्द्र जी की रथविहीन दुर्बलता को देखकर विजय के बारे में शंकायुक्त बन गया था.

feedback@chauthiduniya.com

पाठकों की दुनिया

भ्रष्टाचारी नेता

18 अगस्त का संस्करण अच्छा लगा. पहले पेज पर अन्ना हजारे का लेख पढ़ कर काफी खुशी हुई. चौथी दुनिया के माध्यम से अन्ना जी का लेख पढ़ने को मिला. यह बहुत अच्छी बात है कि चौथी दुनिया ने अपने समाचार पत्र में अन्ना जी का लेख प्रकाशित किया. आजादी की दूसरी लड़ाई हमें अन्ना जी के सात मिल कर लड़नी चाहिए. उन्होंने अपने लेख में बताया है कि हमारे नेता किस प्रकार लोकतंत्र को दागदार कर रहे हैं. यह सही है कि यदि देश को बदलना है, तो पहले गांवों को बदलना होगा, लेकिन राजनीतिक पार्टियां तो केवल गांवों के लोगों को ही वोट के लिए याद करती हैं. उसके बाद उनको गांवों की याद कहां आती है. वे तो केवल गांव के लोगों को जाति के आधार पर बांध रखे हैं. तभी तो पार्टियां अनेक जाति सभाएं करती फिरती हैं. अब समय आ गया है कि जनता अपने अधिकार का प्रयोग करे और जागे, अन्यथा नेता ऐसे ही हमें ठगते रहेंगे. ■ *–अमन, पटना*

सोशल मीडिया का कमाल

सियासी दुनिया पेज पर साइबर खिड़की के पीछे खड़ा मतदाता के नाम से प्रकाशित लेख पढ़ कर पता चलता है कि किस प्रकार राजनीतिक पार्टियां 2014 लोकसभा चुनाव सोशल मीडिया के सहारे लड़ना चाहती हैं. इसीलिए आज ज्यादा राजनीतिज्ञ अब सोशल नेटवर्किंग साइट पर ही अपनी छवि चमकाने में लगे हैं. वह चाहे नरेन्द्र मोदी हों या राहुल गांधी, दोनों ही सोशल नेटवर्किंग के सहारे अपनी छवि चमकाने में लगे हैं. नरेन्द्र मोदी को आज लोगों के बीच सबसे लोकप्रिय नेता बताया जाता है, यह सोशल मीडिया का ही कमाल है. आजकल नेता ट्विटर, फेसबुक, ब्लॉग के जरिये लोगों तक पहुंच बना रहे हैं. यह सही है कि यदि ठीक से इसका साथ मिला, तो कोई कुछ भी बन सकता है. इसीलिए कांग्रेस और भाजपा दोनों ही सोशल मीडिया पर पैठ बनाने की कोशिश में हैं. भाजपा तो कुछ ज्यादा ही सोशल मीडिया पर सक्रिय है. ■

–गरिमा, भागलपुर

चिटफंड कंपनियों को राजनीतिक संरक्षण

पश्चिम बंगाल में शारदा चिटफंड के मामले पर राज्य की मुख्यमंत्री ने निवेशकों को राहत प्रदान करने के लिए एक फंड कंपनी स्थापित करने की बात कही है. पहली नजर में यह बात बहुत काबिलेतारीफ दिखती है, लेकिन अगर इसकी तह में जाया जाए, तो उसकी हकीकत पता चलती है. सूत्रों की मानें, तो तृणमूल कांग्रेस के ज्यादातर कार्यकर्ता शारदा जैसी चिटफंड कंपनी के एजेंट हैं और उन लोगों ने उपरोक्त कंपनी के लिए रुपये जुटाने का काम किया है. पार्टी के दो सांसद इस कंपनी में ऊंचे पदों पर आसीन थे. ऐसे में जाहिर है कि ममता जी को जवाबदेही तो दिखानी ही थी. इसलिए उन्होंने आनन–फानन में 500 करोड़ रुपये का फंड बनाने की घोषणा कर दी. देखा जाय, तो जितने व्यापक पैमाने पर यह घोटाला हुआ है, उसे देखते हुए यह ऊंट के मुंह में जीरा जैसा प्रतीत होता है. बिहार में भी दशक पहले जेवीजी कंपनी ने निवेशकों का खरबों रुपया गायब कर दिया था. कहीं न कहीं सियासत की कुछ हस्तियां ऐसे घोटालेबाज कंपनियों के रहनुमा रहे हैं, तभी यह संभव है. गोल्डेन फॉरेस्ट इंडिया कंपनी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था. आखिर किसकी इजाजत से ऐसी कंपनियां बाजार में अपना वजूद खड़ा करती हैं. आखिर ऐसी कंपनियों पर लगाम लगाना किसकी जिम्मेदारी है? ■

–अशोक निर्मोही, दरभंगा

गरीबों से धोखा

कांग्रेस के नेता कहते हैं कि 12 और 5 रुपये में आप पेट भर खाना खा सकते हैं. कांग्रेस के प्रवक्ता राजबब्बर ने कहा कि आप मुंबई में 12 रुपये में पेट भर खाना खा सकते हैं. कांग्रेस नेता रासिद मसूद कहते हैं कि आप दिल्ली के जामा मस्जिद इलाके में पांच रुपये में भोजन कर सकते हैं. हद तो तब हो गई, जब यूपीए सरकार में केंद्रीय मंत्री फारुख अब्दुल्ला ने पत्रकारों से कहा कि कोई चाहे, तो 1 रुपये में भी खाना खा सकता है. प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को बताना चाहिए कि उसके नेता कितने रुपये में खाना खाते हैं. वसीम राशिद जी ने लिखा है कि यह केवल योजना आयोग के रिपोर्ट की चापलूसी करना ही है और यह एक उलूल–जुलूल बात है. योजना आयोग की रिपोर्ट गरीबों के खिलाफ केवल एक षडयन्त्र है, जिससे उन्हें गरीबी रेखा से पार दिखाया सा सके. इसका जवाब न ही यूपीए सरकार के पास है और न ही कांग्रेस के पास है. ■

–मनोज, समस्तीपुर

पाठक पूरे नाम, पता व फोन नंबर के साथ अपने स्वतंत्र विचार व प्रतिक्रियाएं इस पते पर भेजें:

चौथी दुनिया, एफ.2, सेक्टर-11, नोएडा (उत्तर प्रदेश) पिन-201301

ई-मेल पता : feedback@chauthiduniya.com

संतोष भारतीय

महाभारत के संकेत नजर आ रहे हैं

जब तोप मुक़ाबिल हो

संसदीय लोकतंत्र को प्रदूषित करना और उसका इस्तेमाल करना, जहां कांग्रेस की कुशलता है, वहीं संसद में बैठे राजनीतिक दलों को अपने रंग में रंग लेना कांग्रेस की सर्वोच्च उपलब्धि है, इसलिए निर्विवाद रूप से यह कहा जा सकता है कि संसदीय लोकतंत्र का अपने हित में इस्तेमाल करना और संसदीय लोकतंत्र को जनता के संदर्भ में अप्रासंगिक कर देना इस देश में एक नये महाभारत की भूमिका तैयार कर रहा है.

संसदीय प्रणाली का जैसा स्वरूप हमारे देश में है, उसका इस्तेमाल होशियार लोग अपने हित में जिस तरह करते हैं, वो अध्यनन के काबिल है. शास्त्रीय ढंग से देखें, तो संसदीय प्रणाली का इस्तेमाल जनता के दुख–दर्द के निवारण के लिए होना चाहिए और देश में व्याप्त किसी भी प्रकार की समस्या का निदान संसद से निकलना चाहिए, लेकिन हमारी संसद इस स्थिति से मीलों दूर है.

संसदीय जनतंत्र में विपक्ष का महत्वपूर्ण स्थान है. हालांकि सच्चे जनतंत्र में पक्ष और विपक्ष नहीं होना चाहिए. जनता के नुमाइंदे संसद में होने चाहिए और देश की संस्थाएं होनी चाहिए. दूसरे शब्दों में सच्चे जनतंत्र में संसद में बैठे सभी लोग पक्ष में भी हैं और विपक्ष में भी. वहां फैसला मुद्दों के आधार पर होना चाहिए, पर हमारे देश में तो विपक्ष है और विपक्ष भी संसदीय जनतंत्र का भरपूर मजाक उड़ा रहा है.

तुलनात्मक ढंग से देखें, तो संसदीय जनतंत्र का इस्तेमाल अपने पक्ष में करने की योग्यता कांग्रेस में ज्यादा है. कांग्रेस ने हमेशा संसदीय जनतंत्र का इस्तेमाल पार्टी के हित में किया है और जनता की समस्याओं को बिल्कुल परे रख दिया है. बीते दस वर्ष इस बात के गवाह हैं कि चाहे जितनी महंगाई बढ़ी हो, भ्रष्टाचार बढ़ा हो, जितनी बेरोजगारी बढ़ी हो, जनता का गुस्सा सड़क पर फूटने नहीं दिया. अगर महंगाई के सवाल को देखें, तो प्रधानमंत्री निहायत बेशर्मी से कहते हैं कि उनके पास कोई जादुई छड़ी नहीं है और पैसा पेड़ पर नहीं उगता. महंगाई आजादी के बाद के सारे मानक तोड़ गई और अब दर्द इतना बढ़ा है कि खुद ही दवा हो गया है. कोई भी महंगाई को लेकर सरकार पर आरोप नहीं लगा रहा है. संसद में तो सिर्फ महंगाई का जिक्र संदर्भ के तौर पर होता है. बेरोजगारी पर बेहयाई से झूठ बोला जा रहा है. कांग्रेस या सरकार कहीं पर भी बेरोजगारी का समाधान ढूंढती नजर नहीं आती. सरकार खुद ही नौकरियां खत्म कर रही है, लेकिन आभास यह दे रही है कि वह नौकरियां बढ़ा रही है. और भ्रष्टाचार के तो कहने की क्या! महीने के हिसाब से नहीं, हफ्ते के हिसाब से घोटाले सामने आए हैं. और घोटाले भी करोड़ों के नहीं, लाखों करोड़ के घोटाले सामने आ रहे हैं. संसद में इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं हो रही है और न ही भ्रष्टाचार की चरम सीमा पर पहुंचे घोटालों को लेकर कोई बहिष्कार हो रहा है. जिस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में सबसे ज्यादा घोटाले सामने आए हों, वह प्रधानमंत्री ईमानदार माना जा रहा है. जिस प्रधानमंत्री के ऊपर सीबीआई और सुप्रीम कोर्ट तक ने उंगली उठाई हो, उस प्रधानमंत्री को लेकर संसद खामोश है. इसका सारा श्रेय कांग्रेस को ही जाता है.

कांग्रेस को इस बात का भी श्रेय जाता है कि उसकी अगुवाई में चलने वाली सरकार के योजना आयोग ने निहायत बद्तमीजी के साथ शहरों में 34 और गांवों में 27 रुपये की आमदनी को जीवन जीने योग्य माना है. और उनके दो प्रवक्ता 12 रुपये और पांच रुपये में दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में भरपेट भोजन मिलने का दावा कर रहे हैं, लेकिन हमारी संसद में इसे लेकर कोई हलचल नहीं होती. कांग्रेस ने जनता को मिले एक मात्र हथियार सूचना के अधिकार को अपने हिसाब से मोड़ लिया. सरकार अपराधियों को संसद का रास्ता दिखाने पर आमादा है. किसानों के हितों को बिल्डरों के हाथों बेचा दिया, लेकिन संसद में कोई हलचल नहीं है.

संसद में विपक्ष के नाम पर भारतीय जनता पार्टी से शुरू होकर एक सांसद की सदस्यता रखने वाली पार्टी तक तकरीबन 20 पार्टियां हैं, पर सब संसद में खामोश हैं. ज्यादातर पार्टियां राज्यों में कहीं–कहीं सरकार का नेतृत्व कर रही हैं या सरकार में शामिल हैं. जो यहां कांग्रेस कर रही है, ये पार्टियां राज्यों में कर रही हैं. इसलिए संसद में वे जान–बूझकर आवाज नहीं उठा रही हैं. एक लाइन का विश्लेषण है कि ये सारी पार्टियां संसदीय व्यवस्था का इस्तेमाल केवल जनता को धोखा देने और उसे बरगलाने के लिए करती हैं. भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ इनमें सह–अस्तित्व के सिद्धांत पर समझौता हो चुका है. इस समझौते ने देश की जनता को निराशा के जंगल में भटकने पर मजबूर कर दिया है. निराशा का यह जंगल कई रास्ते दिखा रहा है. देश के लगभग सारे सीमांत प्रदेश निराशा के इस महापर्व में नक्सलवादियों को उभरने और फैलने का मनचाहा मैदान उपलब्ध करा रहे हैं. देश का एक तिहाई से ज्यादा हिस्सा नक्सलवादियों के प्रभाव क्षेत्र में है. इस हिस्से में न सड़क है, न रोजगार है, न रोटी है और न ही इज्जत है. जिन सड़कों का पैसा सरकार से जुड़े लोगों ने हड़प लिया, आज उन जगहों पर जाने में अर्धसैनिक बल घबराते हैं. भूले–भटके जब कहीं ये अर्धसैनिक बल इन इलाकों में जाते हैं और जब उन पर नक्सलवादियों के हमले होते हैं, तो उन हमलों की खबर भी कई दिनों बाद लोगों तक पहुंच पाती है. देश की एक तिहाई से ज्यादा जनता भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य की समस्याओं की वजह से नक्सलवादियों का मौन समर्थन कर रही है.

> मजे की बात यह है कि राजनीतिक दल अन्ना को असफल साबित करना चाहते हैं, लेकिन नक्सलवादी अन्ना के आंदोलन में एक बड़ी संभावना देख रहे हैं. उन्हें पूरा विश्वास है कि राजनीतिक दल अन्ना को असफल करेंगे ही करेंगे, जिससे बड़े पैमाने पर निराशा फैलेगी और उस समय जनता उनके समर्थन में खड़ी हो जाएगी.

इसका सीधा मतलब है कि संसदीय जनतंत्र का इस्तेमाल सारी राजनीतिक पार्टियां जनता के खिलाफ इस सीमा तक कर रही हैं कि उन्होंने विकल्प के तौर पर जान–बूझकर नक्सलवाद को सामने खड़ा कर दिया है. और इनकी इस बेवकूफी का फायदा नक्सलवादी सैद्धांतिक रूप से उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि संसदीय जनतंत्र कभी भी गरीब के साथ नहीं खड़ा हो सकता.

इन सब में गांधी गायब हो चुके हैं, क्योंकि गांधी का नाम लेने वाले खुद गांधी में विश्वास नहीं करते. इसलिए उन्होंने गांधी के विचारों का स्थान सार्वजनिक स्थानों पर लगी हुई मूर्तियों में मान लिया है.

अब यहीं बीच में भटकते हुए अन्ना हजारे आ जाते हैं. अन्ना हजारे ने घोषणा की है, वे दूसरी आजादी की लड़ाई लड़ेंगे. दूसरी आजादी की लड़ाई का मतलब संसद से सारे राजनीतिक दलों को निकाल फेंकेगे. अन्ना हजारे जहां एक तरफ संसदीय लोकतंत्र को राजनीतिक दलों के प्रदूषण से मुक्त करना चाहते हैं, वहीं वे साफ शब्दों में यह भी कह रहे हैं कि अगर जनता को विश्वास में लेकर विकास का काम तत्काल शुरू नहीं हुआ, तो यह देश नक्सलवादियों के सिद्धांत को गंभीरता से अपना लेगा.

जिस तरह हमारे संसदीय लोकतंत्र ने हिंदुस्तान के हर वर्ग के लोगों को तकलीफ दी है, निराशा दी है, उसके परिणामस्वरूप उभरने वाला गुस्सा हिंसक प्रतिक्रियाओं को जन्म दे सकता था, लेकिन अन्ना हजारे की वजह से अभी भी लोगों की आस्था अहिंसा में है. और शायद इसीलिए राजनीतिक दलों के लोग और भ्रष्ट सरकारी अफसर हिंसा के शिकार नहीं हो रहे हैं. वे चल–फिर रहे हैं, रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं और सिनेमा भी देख रहे हैं.

मजे की बात यह है कि राजनीतिक दल अन्ना को असफल साबित करना चाहते हैं, लेकिन नक्सलवादी अन्ना के आंदोलन में एक बड़ी संभावना देख रहे हैं. उन्हें पूरा विश्वास है कि राजनीतिक दल अन्ना को असफल करेंगे ही करेंगे, जिससे बड़े पैमाने पर निराशा फैलेगी और उस समय जनता उनके समर्थन में खड़ी हो जाएगी.

संसदीय लोकतंत्र को प्रदूषित करना और उसका इस्तेमाल करना, जहां कांग्रेस की कुशलता है, वहीं संसद में बैठे राजनीतिक दलों को अपने रंग में रंग लेना कांग्रेस की सर्वोच्च उपलब्धि है, इसलिए निर्विवाद रूप से यह कहा जा सकता है कि संसदीय लोकतंत्र का अपने हित में इस्तेमाल करना और संसदीय लोकतंत्र को जनता के संदर्भ में अप्रासंगिक कर देना इस देश में एक नये महाभारत की भूमिका तैयार कर रहा है, जिसमें एक तरफ कांग्रेस के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी सहित संसद में मौजूद सभी पार्टियां होंगी और दूसरी तरफ अन्ना हजारे के नेतृत्व में हिंदुस्तान की जनता और जनता के हितों के लिए लड़ने वाले नक्सलवादियों सहित तमाम संगठन होंगे. महाभारत के संकेत साफ नजर आ रहे हैं. ■

editor@chauthiduniya.com

मेघनाद देसाई

गरीबी मानसिक स्थिति है

बिस्मार्क ने कहा था कि जब तक किसी बात को आधिकारिक तौर पर नकार न दिया जाए, तब तक उसे सत्य नहीं माना जा सकता. जब भी कोई नेता कहे कि उसके बयान को तोड–मरोड कर पेश किया गया है, तभी यह माना जाए कि उसके बारे में सही खबर दी गई है. इसिलए हमें उस रिपोर्ट की सत्यता पर विश्वास कर सकते हैं जिसमें राहुल गांधी ने महीनों की चुप्पी तोडते हुए कहा है कि गरीबी मानसिक अवस्था है. और उनके उस बयान पर गौर किया जाए जिसे कि तथाकथित तौर पर तोड–मरोड कर पेश किया गया कि गरीबी केवल मानसिक अवस्था है इसलिए इसका खाद्यान्न, पैसे या दूसरी वस्तुओं से कोई लेना–देना नहीं है.

गरीबी वास्तव में है क्या, इसकी परिभाषा को लेकर, खासकर भारत में, बडा ही भ्रम है. और राहुल गांधी के बयान के संदर्भ में बात करें तो गरीबी को लेकर उन्होंने सबसे सटीक बात कही है. नेतागण मूर्ख बन गए जब उनके सामने हालिया गरीबी संबंधी आंकडा आया कि भारत में गरीबों की संख्या, जो कि 2004–05 में कुल जनसंख्या का 37.2 प्रतिशत थी, 2011–12 में घटकर मात्र 21.9 प्रतिशत रह गई है. यानी करीब चालीस करोड से घटकर 26 करोड रह गई है. यह एक बेहतरीन खबर हो सकती थी लेकिन इसे कांग्रेस के एक धडे ने इसकी जड ही काट दी. उन्होंने दावा किया कि यह चौंकाने वाला आंकडा है. गरीबी रेखा का पैमाना प्रति परिवार के लिए हर महीने 5000 रुपये होना चाहिए. कुछ और लोगों ने कहा कि ग्रामीण इलाकों में 27.2 रुपये प्रति व्यक्ति आय और शहरी इलाकों में 33.3 रुपये प्रति व्यक्ति आय का पैमाना पर्याप्त है. ढाबे पर कोई भी व्यक्ति 12 रुपये में खाना खा सकता है. जाहिर है कि यह कुछ अल्पहारी नेताओं के विचार हैं जो सिर्फ पाव–भाजी पर जीवनयापन करते होंगे.

एक सदी से अधिक समय से गरीबी रेखा की व्याख्या जीने के लिए जरूरी कैलोरी–2200 प्रति व्यक्ति के आधार पर की जाती रही है. आप गणित लगा सकते हैं कि इतनी कैलोरी जरूरी भोजन कितने पैसे में आएगा और वह आय गरीबी रेखा का पैमाना थी. यदि आपके पास इतना भी नहीं है तो आप गरीब थे. भारत में, पिछले 30 सालों से भोजन के अलावा हमने इसमें कुछ और चीजें जोडी हैं, जैसे–स्वास्थ्य, शिक्षा, उर्जा, परिवहन (तेंदुलकर समिति के मुताबिक) और इसके बाद मौजूदा पैमाना तय हुआ है.

विश्व बैंक का मानना है कि जो 1.25 डॉलर (करीब 76 रुपये) से कम कमाता हो, वह गरीब है. इसके मुताबिक, 33 प्रतिशत यानी 40 करोड लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं. गरीबी रेखा का पैमाना थोडा बढाइए और आप पाएंगे कि और अधिक लोग गरीब हैं. वाम धडे ऐसा मानने का फैशन है कि गरीबी उससे कहीं ज्यादा है, जितना यह पैमाना कहता है. खाद्य सुरक्षा बिल के तहत 67 प्रतिशत यानी 80 करोड से अधिक लोगों को सब्सिडी वाले मूल्य पर अनाज देने की योजना है.

इसिलए यह बताइए कि आपकी राजनीति क्या है और गरीबी रेखा का उपयुक्त पैमाना पा जाएंगे. गरीबी आपके दिमाग की एक प्रक्रिया है, जो कि आपका राजनीतिक विश्वास है. लेकिन यहां तक कि यह सब कुछ वर्तमान एक निवाला ज्यादा खाने तक ही सीमित है. हमारे सारे पैमाने यह सवाल नहीं उठाते कि कितने लोग गरीब हैं और क्यों हैं, और गरीबी से बाहर से लाने के लिए हम उनकी कैसे मदद कर सकते हैं. यह उन आकांक्षाओं की बात है जो गरीबों के पास है. उनके लिए शिक्षा पाने और अच्छे रोजगार के लिए कुशलता हासिल करने के लिए अवसरों के दरवाजे खोले जाएं. गरीबों पर भोजन लुटाने और सस्ते दामों में अनाज देने से गरीबी कम नहीं होने वाली है. यह सिर्फ नेताओं के लिए संतोष की बात हो सकती है.

खाद्य सुरक्षा बिल के आंकडों पर गौर कीजिए, जिसका बजट 1.25 लाख करोड का है. 80 करोड लोगों में हर व्यक्ति को 1500 रुपये सब्सिडी दी जानी है. यानी हर परिवार पर 7500 रुपये की सब्सिडी. यदि विश्व बैंक के पैमाने के आधार पर बात करें तो प्रति व्यक्ति इसका दोगुना–3000 होता है. यदि तेंदुलकर समिति के पैमाने पर बात करें तो प्रति व्यक्ति वितरण 4800 रुपये का होना चाहिए. गरीबी

को हटाने के लिए हम कितना कुछ कर सकते थे यदि हम सार्वजनिक वितरण प्रणाली की जगह हम परिवारों को आधार के जरिये सीधे पैसा पहुंचाते. सार्वजनिक वितरण प्रणाली में प्रणाली में 40 प्रतिशत अधिक यानी करीब 50,000 करोड रुपये ज्यादा बर्बाद होंगे.

इसलिए राहुल गांधी ठीक कह रहे हैं. गरीबी मानसिक अवस्था है. लेकिन गरीबों की नहीं, बल्कि राजनीतिज्ञों की. वे केवल गरीबी नापने के लिए पैमाना तलाशते हैं कि गरीबों को खिलाने के लिए कितने रुपये खर्च किए जा सकते हैं, लेकिन उन्हें कोई आशा नहीं देते. ऐसा इसिलए है क्योंकि इसके पीछे निर्वाचन क्षेत्र तक सीमित रखने, उन्हें कृतज्ञ रखने और माई–बाप कांग्रेस को वोट देने के लिए तैयार रखने का विचार काम करता है. राहुल अपनी पार्टी को इस बात के लिए प्रेरित कर सकते थे कि खाद्य सुरक्षा बिल को रद्दी की टोकरी में डाला जाए और 1.25 लाख करोड रुपये को रोजगार उत्पन्न करने के लिए खर्च किया जाए. लेकिन क्या उनकी मानसिक अवस्था ऐसी है? ■

feedback@chauthiduniya.com

> खाद्य सुरक्षा बिल के आंकड़ों पर गौर कीजिए, जिसका बजट 1.25 लाख करोड़ का है. 80 करोड़ लोगों में हर व्यक्ति को 1500 रुपये सब्सिडी दी जानी है. यानी हर परिवार पर 7500 रुपये की सब्सिडी. यदि विश्व बैंक के पैमाने के आधार पर बात करें, तो प्रति व्यक्ति इसका दोगुना–3000 होता है. यदि तेंदुलकर समिति के पैमाने पर बात करें, तो प्रति व्यक्ति वितरण 4800 रुपये होना चाहिए.

सूचना का अधिकार चौथी दुनिया की पहल

सूचना आयुक्त, सरकार और आरटीआई

चौथी दुनिया ब्यूरो

सूचना का अधिकार क़ानून (आरटीआई) स्वतंत्र भारत में बना पहला ऐसा क़ानून है, जिसे आम आदमी के जानने और जीने के अधिकार से जोड़कर देखा गया. इसने आम आदमी को सवाल पूछने की हिम्मत दी. शासन और प्रशासन में बैठे लोगों को पहली बार लगा कि कोई उनसे भी सवाल पूछ सकता है और यही बात इन लोगों को ठीक नहीं लगी. इसलिए इस क़ानून की भ्रूण हत्या की पूरी साज़िश रची जाने लगी. क़ानून बनने से पहले ही साल में कुछ ब्यूरोक्रेट्स की सलाह पर सरकार ने इस क़ानून में संशोधन कर फाइल नोटिंग जैसे महत्वपूर्ण प्रावधान को ख़त्म करने की कोशिश की. हालांकि यह कोशिश भी नाकाम रही. लेकिन एक मामले में सरकार सफल रही है, और वह है सूचना आयुक्त की नियुक्ति का मामला. सूचना आयुक्त का पद अपने जन्म से ही राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति के लिए बदनाम रहा है. सूचना आयुक्तों की नियुक्ति के लिए ज़िम्मेदार विभाग डीओपीटी के पास नियुक्ति के संबंध में कोई स्पष्ट नियम–क़ानून नहीं है. इसी का फ़ायदा उठाकर सरकार अपने विश्वस्त और वफ़ादार ब्यूरोक्रेट्स को सूचना आयुक्त बना देती है. उक्त विश्वस्त और वफ़ादार ब्यूरोक्रेट्स ऐसे होते हैं, जो किसी भी क़ीमत पर अपने आक़ाओं के हितों की अनदेखी नहीं कर सकते. हालांकि प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और एक कैबिनेट मंत्री की अगुवाई में एक चयन समिति है, जो सूचना आयुक्त के लिए आए नामों पर अंतिम मुहर लगाती है. सूचना क़ानून में पत्रकारों, बुद्धिजीवियों और एकेडमिक पृष्ठभूमि एवं सामाजिक सेवा से जुड़े लोगों को भी सूचना आयुक्त बनाया जा सकता है, लेकिन डीओपीटी की मनमानी का आलम यह है कि ज़्यादातर केंद्रीय सूचना आयुक्त पूर्व नौकरशाह हैं. अगर बात राज्य सूचना आयोग की करें तो वहां भी यही आलम है. डीओपीटी के लिए सामाजिक संगठनों, नेताओं, मुख्यमंत्रियों एवं सांसदों द्वारा की गई अनुशंसा का कोई अर्थ नहीं होता है. 2005 में पहली बार जब केंद्रीय सूचना आयुक्त की नियुक्ति की जानी थी, तब 15 लोगों ने इस पद के लिए आवेदन किया था. इन नामों में एक से बढ़कर एक समाजसेवी, अकादमिक पृष्ठभूमि के लोग थे, लेकिन जब चयन समिति के पास नाम भेजे गए तो उनमें इन 15 नामों में से एक भी शामिल नहीं था. डीओपीटी ने अपनी तरफ़ से 5 नाम चयन समिति के पास भेजे थे और उन्हीं 5 नामों पर समिति सहमत हो गई. ये नाम थे, वज़ाहत हबीबुल्लाह, पद्मा बालासुब्रह्मण्यम, ओ पी केजरीवाल, ए एन तिवारी, एम एम अंसारी. दिलचस्प रूप से इन नामों में से अधिकतर नाम ऐसे थे, जो पूर्व नौकरशाह थे. इसी तरह अगस्त 2008 में जब केंद्रीय सूचना आयोग में सूचना आयुक्त के चार पद ख़ाली हुए तो डीओपीटी ने अपनी तरफ़ से 6 नाम भेजे, जिनमें से चार नामों पर चयन समिति ने अपनी मुहर लगा दी. ज़ाहिर है, ऐसे सूचना आयुक्त (जो पूर्व में नौकरशाह रह चुके हैं) सरकार और प्रशासन में पारदर्शिता लाने की जगह अपनी पूरी वफ़ादारी अपने नियोक्ता (सरकार) के प्रति दिखाते हैं. इस संबंध में अगर अभी भी डीओपीटी कोई स्पष्ट दिशा–निर्देश नहीं बनाता है तो सूचना आयुक्त जैसा ज़िम्मेदार पद यूं ही राजनीतिक नियुक्ति का ज़रिया बनता रहेगा और आम आदमी को ताक़त देना देने वाला यह क़ानून दिनोदिन कमज़ोर होता जाएगा. ■

यदि आपने सूचना क़ानून का इस्तेमाल किया है और अगर कोई सूचना आपके पास है, जिसे आप हमारे साथ बांटना चाहते हैं, तो हमें वह सूचना निम्न पते पर भेजें. हम उसे प्रकाशित करेंगे. इसके अलावा सूचना का अधिकार क़ानून से संबंधित किसी भी सुझाव या परामर्श के लिए आप हमें ई–मेल कर सकते हैं या पत्र लिख सकते हैं. हमारा पता है:

चौथी दुनिया

एफ–2, सेक्टर–11, नोएडा (गौतमबुद्ध नगर) उत्तर प्रदेश, पिन –201301 ई–मेल : rti@chauthiduniya.com

आवेदन का प्रारूप

इंदिरा आवास योजना का विवरण

सेवा में,
लोक सूचना अधिकारी
(विभाग का नाम)
(विभाग का पता)

विषय : सूचना केअधिकार अधिनियम–2005 केतहत

आवेदन.

महोदय,

मेरा नाम.....है. मैं.....पंचायत के ..... गांव का निवासी हूं. मेरे पास रहने के लिए घर नहीं है. इसके बावजूद अभी तक मुझे इंदिरा आवास योजना के तहत घर आवंटित नहीं किया गया है. इस संबंध में सूचना के अधिकार के तहत निम्नलिखित सूचनाएं दें:

1. सरकार के रिकॉर्ड के अनुसार, क्या मैं इंदिरा आवास योजना का हक़दार हूं? यदि नहीं तो क्यों?

2. यदि हां, तो अब तक मुझे इंदिरा आवास योजना का आवंटन क्यों नहीं किया गया है? मुझे इंदिरा आवास योजना का लाभ मिले यह सुनिश्चित करने की ज़िम्मेदारी किन अधिकारियों/कर्मचारियों की है? उनका नाम एवं पद बताएं.

3. मेरे ग्राम पंचायत में पिछले पांच वर्षों में कुल कितने लोगों को इस योजना के तहत घर आवंटित किए गए हैं? उनकी सूची निम्नलिखित विवरण के साथ उपलब्ध कराएं:

क. लाभार्थी का नाम

ख. आवंटन की तारीख़

ग. किस आधार पर आवंटित किया गया

घ. जिस ग्राम सभा में लाभार्थी का चयन किया गया उस ग्राम सभा की उपस्थिति रजिस्टर की प्रमाणित प्रति दें.

4. क्या उपरोक्त सभी आवंटन बी पी एल सूची के आधार पर किए गए हैं? उपरोक्त पंचायत की बी पी एल सूची की प्रमाणित प्रति दें.

5. इंदिरा आवास योजना के आवंटन से संबंधित सभी शासनादेशों/निर्देशों/नियमों की प्रमाणित प्रति दें.

मैं आवेदन फीस के रूप में 10 रुपये अलग से जमा कर रहा/रही हूं.

या

मैं बी पी एल कार्ड धारी हूं, इसलिए सभी देय शुल्कों से मुक्त हूं. मेरा बी पी एल कार्ड नं.....है.

यदि मांगी गई सूचना आपके विभाग/कार्यालय से संबंधित नहीं हो तो सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा–6 (3) का संज्ञान लेते हुए मेरा आवेदन संबंधित लोक सूचना अधिकारी को पांच दिनों के समयावधि के अंतर्गत हस्तांतरित करें. साथ ही अधिनियम के प्रावधानों के तहत सूचना उपलब्ध कराते समय प्रथम अपील अधिकारी का नाम एवं पता अवश्य बताएं.

भवदीय

नाम :
पता :
फोन नं :
संलग्नक :
(यदि कुछ हो)

राशिफल

आचार्य चंद्रशेखर

मेष (21 मार्च से 20 अप्रैल)

इस सप्ताह आप क्रोध वाली स्थिति से बचें. आपके सगे सम्बन्धी और मित्रों का पूर्ण सहयोग मिलता रहेगा, लेकिन मानसिक तनाव को नियंत्रण में रखें. पूंजी निवेश परिस्थितियों को ध्यान में रख कर करें. भावुक होकर कोई संपत्ति खरीदने का निर्णय न लें. नौकरीपेशा और व्यापारी वर्ग अपने कार्य स्थल पर साथ कार्य करने वाले लोगों पर ध्यान रखें.

वृष (21 अप्रैल से 20 मई)

इस सप्ताह आपके प्रति लोगों का व्यवहार सौहार्द्रपूर्ण और सहयोगात्मक होगा. इस सप्ताह आपके मान–सम्मान बढ़ने का प्रबल योग रहेगा. स्वास्थ्य की छोटी–मोटी समस्या बनी रहेगी. किसी को कर्ज देने से पहले मंथन जरूर कर लें. नौकरीपेशा लोगों की जिंदगी में भाग्य से ज्यादा कर्म का महत्व बना रहेगा. कोशिश करें कि अधिकारी का कोपभाजन न बनें.

मिथुन (21 मई से 20 जून)

इस सप्ताह अपनी महत्वाकांक्षा को नियंत्रण में रखें और अपने धुन में कार्य करते चलें. फल की चिंता न करें. आप अपनी प्रगति की बातें सब जगह जाकर न बोलें. उससे आपके अन्दर ही अन्दर शत्रु बनेंगे. कुल मिलाकर आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने पर आप प्रभावी और फायदे में रहेंगे.

कर्क (21 जून से 20 जुलाई)

इस सप्ताह आपके अधिक मेहनत के बावजूद सफलता थोड़ी मुश्किल से मिलेगी. स्वास्थ्य की दृष्टि से थोड़ी परेशानी महसूस हो सकती है. मित्र–बंधू आपको सहयोग करेंगे और आपसी सम्बन्ध काफी सौहार्द्रपूर्ण रहेगा. आपसी लेन–देन में थोड़ी सतर्कता बरतें. खरीद–बिक्री की योजनाएं बन सकती हैं.

सिंह (21 जुलाई से 20 अगस्त)

इस सप्ताह वाद–विवाद से बचें और बिना मतलब के उलझन से परहेज करें. आर्थिक मामलों में अत्यधिक सोच–विचार कर कोई निर्णय लें. माता–पिता का पूर्ण आशीर्वाद मिलेगा. विद्यार्थी अपनी पढ़ाई में ध्यान थोड़ी कम लगाएंगे. सामाजिक मान–सम्मान बढ़ेगा. दामपत्य जीवन में सुख बढ़ेगा.

कन्या (21 अगस्त से 20 सितंबर)

इस सप्ताह आपके लिए उन्नति वाला सप्ताह होगा और आपका आत्म बल बढ़ेगा. पारिवारिक और मांगलिक कार्य सम्पन्न होने के संकेत अच्छे हैं. स्वास्थ्य में थोड़ा उतार–चढ़ाव महसूस करेंगे. विद्यार्थी वर्ग अच्छा प्रदर्शन करेंगे. बुजुर्ग का स्वास्थ्य चिंता का कारण बनेगा. संपत्ति के क्रय से सम्बन्धी कोई सकारात्मक निर्णय लेंगे.

तुला (21 सितंबर से 20 अक्टूबर)

इस सप्ताह आप निर्णय अपने मन से लें. किसी से प्रभावित होकर जल्दबाजी में कोई कार्य न करें. आर्थिक रूप से थोड़ा उतार–चढ़ाव रहेगा. कुछ नया खरीद सकते हैं. भाई–बहनों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा. वाहन खरीदने की योजना बनेगी. विद्यार्थी के लिए औसत समय रहेगा. मेहनत करने की जरूरत है.

वृश्चिक (21 अक्टूबर से 20 नवंबर)

इस सप्ताह आप भाग्य से ज्यादा कर्म पर भरोसा करेंगे. आपको अपने कार्य क्षेत्र में ज्यादा प्रतिष्ठा मिलेगी. पारिवारिक सदस्य का बर्ताव आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा. भावनात्मक रूप से आप ज्यादा मजबूत होंगे. आपके आस–पास के लोग आपको स्नेह की दृष्टि से देखेंगे. आपको अपने व्यस्त कार्यों से आराम का मौका निकालना चाहिए. स्वास्थ्य का ध्यान रखें.

धनु (21 नवंबर से 20 दिसंबर)

इस सप्ताह आपके अपने मित्र–बंधुओं से अच्छे सम्बन्ध रहेंगे. इस सप्ताह आप अपने आत्मविश्वास की वजह से बहुत सारे कार्यों को कर लेने की स्थिति में रहेंगे. कार्यों के दबाव से थोड़ी बैचैनी रहेगी. आर्थिक रूप से आप अच्छा करेंगे. बहुत ज्यादा विश्वास करके कोई कार्य न करें. यात्रा से आपको लाभ मिलेगा. स्वास्थ्य हलके उतार–चढ़ाव के साथ अच्छा रहेगा.

मकर (21 दिसंबर से 20 जनवरी)

इस सप्ताह आप ज्यादा खुश रहेंगे और उत्साह बढ़ा रहेगा. आपका रुझान अध्यात्मिक और धार्मिक कार्यों पर ज्यादा रहेगा. आप इस वक़्त समझौतावादी रहेंगे. व्यापारियों के व्यापार को लेकर बहुत पैनी नजर रहेगी. नौकरीपेशा लोग उन्नति की राह पर रहेंगे. परिवार और समाज के लोग आपको बहुत स्नेह देंगे.

कुंभ (21 जनवरी से 20 फरवरी)

इस सप्ताह आप अपने चिड़चिड़े स्वभाव से बचें. आप इस सप्ताह अपने मूड में बहुत उतार–चढ़ाव देखेंगे. आपके खर्चे बढ़ने की सम्भावना है. इस सप्ताह आपके लिए परिवार का महत्व बहुत ज्यादा रहेगा. भाग–दौड़ के बावजूद, आप अपने पारिवारिक प्रबंधन को बहुत अच्छी तरह से निभाएंगे. स्वास्थ्य का ध्यान रखें. कानूनी मामलों से बचें.

मीन (21 फरवरी से 20 मार्च)

पूरे सप्ताह आप भाग्यशाली रहेंगे. बाधाओं के बावजूद, धन का आगमन होता रहेगा. पारिवारिक वातावरण सुखद रहेगा. किसी मित्र की वजह से आपको कार्यों में सफलता मिलेगी. बिना वजह की भाग–दौड़ अत्यधिक होगी. कुछ बिगड़े कार्य बनेंगे. आपके पैसे मनोरंजन और सुख–साधन पर खर्च होगा.

ज़रा हट के

ज्यादा पढ़ाई से मानसिक बीमारी का खतरा

ज़िंदगी को संवारना हो, तो पढ़ाई बहुत ही जरूरी है, लेकिन अगर कोई इतना अधिक पढ़ाई करने लगे कि उसका दिमाग ही काम करना बंद कर दे, तो आप क्या करेंगे. जी हां, पढ़ाई भी एक हद तक ही करनी चाहिए, यह बात एक रिसर्च में सामने आई है. अब तक ऐसा माना जाता रहा है कि कम शिक्षा के कारण कठिनाई से आजीविका कमा सकने वाले लोगों में मस्तिष्क की बीमारी होने का खतरा ज्यादा रहता है, लेकिन वैज्ञानिकों ने एक नए शोध के बाद पाया कि अत्यधिक शिक्षा के कारण भी मानसिक बीमारी का खतरा हो सकता है. शोधकर्ताओं का कहना है कि शोध में शामिल ऐसे लोगों, जिनकी शिक्षा उनकी नौकरियों की अपेक्षा कहीं अधिक है, उनमें मानसिक तनाव जैसी बीमारी होने का खतरा अधिक पाया गया. यह शोध 21 यूरोपीय देशों के 16,600 नौकरीपेशा लोगों के बीच किया गया. शोध में शामिल व्यक्तियों की उम्र 25 से 60 के बीच थी.

वेबसाइट लाइवसाइंस डॉट कॉम ने शोधकर्ता और बेल्जियम के घेंट विश्वविद्यालय के समाजिक विज्ञान के प्राचार्य पीट ब्रेके के हवाले से कहा कि अतिशिक्षित लोगों में मानसिक तनाव का खतरा अधिक होने का मुख्य कारण यह है कि उन्हें अपनी नौकरियों से वैसी चुनौती नहीं मिलती, जिसके लिए उन्हें सीखे गए अपने सभी कौशलों का इस्तेमाल करना पड़े. ■

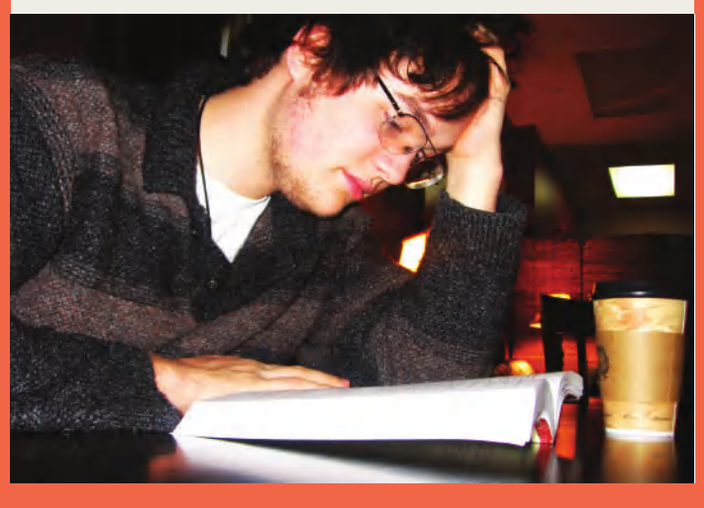

बीवी को छोड़ कुत्ते को बचाया

लगता है कुत्ते की कीमत इंसान से ज्यादा हो गई है. यह बात हम यूं ही नहीं कह रहे हैं, बल्कि एक वाकये ने यह साबित कर दिया है. यह अजीबोगरीब वाकया पूर्वी लंदन का है. अपनी पत्नी और पालतू कुत्ते के साथ समंदर की सैर पर गए ग्राहम एनली नाम का एक शख्स डूबने लगा. ऐसे हाल में उसने पहले अपने कुत्ते को बचाने की कोशिश की. बचाने के दौरान बाद में बीवी का नंबर आया. नेशनल सी रेस्क्यू संस्थान के ज्यॉफ मैकग्रेगर मे बताया कि जानकारी मिलने पर पूर्वी लंदन के तटीय इलाके में इस परिवार को बचाया गया. एनली छुट्टी मनाने के लिए अपने याट से लंदन से मेडागास्कर जा रहे थे. याट के पाल फंस जाने से वे लोग डूबने लगे. ■

सबसे वजनी बच्चे का जन्म

सामान्य तौर पर जन्म के समय बच्चों का वजन ढाई से चार किलोग्राम के बीच होता है, लेकिन एक महिला ने जिस बच्चे को जन्म दिया है, उसके वजन का जब आपको पता चलेगा, तो आप दांतों तले अंगुली दबा लेंगे. यह संभव हुआ है ब्रिटेन में. एक ब्रिटिश महिला ने अब तक के सबसे वजनी बच्चे को स्पेन में जन्म दिया है. नवजात का वजन छह किलो 200 ग्राम है. बच्ची की मां का नाम मैक्सिम मरीन है, जिसने एलीकेट के मरीना सेल्यूड अस्पताल में बगैर ऑपरेशन के बच्ची को जन्म दिया. मरीन बच्ची के जन्म पर बहुत खुश हैं और कहती हैं कि मुझे पता है कि मेरी बच्ची का वजन ज्यादा है, लेकिन यह वजन असामान्य नहीं है. जच्चा–बच्चा दोनों स्वस्थ हैं. अस्पताल के स्त्री एवं प्रसुति विभाग के मुख्य चिकित्सक जेवियर रायस ने कहा कि 40 साल के करियर में मैंने ऐसा कोई मामला नहीं देखा, जब इतना वजनी बच्चा सामान्य ढंग से जन्मा हो. हम सभी काफी खुश हैं. ■

चौथी दुनिया ब्यूरो

रक्षा मंत्री ने बयान देने से पहले एक बार भी नहीं सोचा कि वह जो बयान दे रहे हैं, उसे ढाल के रूप में पाकिस्तान आने वाले समय में इस्तेमाल कर सकता है. यहां एक बड़ा सवाल उठता है कि यदि पाकिस्तान की जमीन से आतंकवादियों ने हमारे सैनिकों पर गोलियां चलाई होतीं, तो क्या पाकिस्तान इसके लिए दोषी नहीं होता, अगर दोषी होता, तो क्या उसे माफ कर दिया जाता?

उबल रहा है भारतीय जनमत

पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब आखिर कब

आए दिन पाकिस्तान हमारे सैनिकों को मारता है. देशभक्ति का ढोंग रचने वाली केंद्र सरकार इसके बावजूद बयानबाजी में मशगूल है. लोगों का गुस्सा कब ज्वालामुखी बनकर फूट जाए, कहा नहीं जा सकता. आखिर हम कब पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देंगे. भारत के प्रधानमंत्री को पाकिस्तान को एक कठोर संदेश देना चाहिए कि बहुत हो गया, अब भारत और अधिक बर्दाश्त नहीं करेगा, लेकिन ऐसा होगा, कहना मुश्किल है.

राजीव रंजन

पिछले दिनों भारत–पाक नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तानी सैनिकों ने पांच भारतीय सैनिकों को गोली मार दी. इस घटना के बाद भारत के रक्षा मंत्री ने पहले यह बयान दिया कि भारतीय सैनिकों को आतंकवादियों ने मारा है. फिर रक्षा मंत्री अपने बयान से पलटे और कहा कि भारतीय सैनिकों को पाकिस्तानी सैनिकों ने मारा है. भारतीय सैनिकों को आतंकवादियों ने मारा हो या पाकिस्तानी सैनिकों ने, इस मुद्दे पर बहस से ज्यादा जरूरी है, इस मुद्दे पर बहस करना कि पाकिस्तान की सरजमीं से गोली चली क्यों? सच पूछा जाए, तो रक्षा मंत्री आतंकवादी और पाकिस्तानी सैनिक के जिस विवाद में पड़े रहे, इससे किसी भारतीय को कोई मतलब नहीं. आज हर हिंदुस्तानी सवाल कर रहा है, तो यह कि पाकिस्तान की तरफ से गोली चली क्यों? पाकिस्तान की इस घटिया करतूत से हर हिंदुस्तानी का खून खौल उठा है. हमारे सैनिक मारे गए हैं और गोली पाकिस्तान की तरफ से चली है. इस बात को केंद्र में रखकर ही रक्षा मंत्री को बयान देना चाहिए था.

रक्षा मंत्री ने बयान देने से पहले एक बार भी नहीं सोचा कि वह जो बयान दे रहे हैं, उसे ढाल के रूप में पाकिस्तान आने वाले समय में इस्तेमाल कर सकता है. यहां एक बड़ा सवाल उठता है कि पाकिस्तान की जमीन से आतंकवादियों ने हमारे सैनिकों पर गोलियां चलाई होतीं, तो क्या पाकिस्तान इसके लिए दोषी नहीं होता, अगर दोषी होता, तो क्या उसे माफ कर दिया जाता? अगर नहीं, तो रक्षा मंत्री ने यह बयान क्यों दिया कि गोली आतंकवादियों ने चलाई थी. दूसरी बड़ी चिंता इस बयान को लेकर लाजिमी है कि पाकिस्तान, रक्षा मंत्री एंटनी के इस बयान को भविष्य में ढाल के तौर पर प्रयोग कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान ने एंटनी के बयान में वह लूप होल खोज लिया है, जिसके सहारे वह भारतीय सीमा में गोलीबारी की घटना को अंजाम देकर यह कह सकता है कि गोली हमारे सैनिकों ने नहीं, बल्कि आतंकवादियों ने चलाई. हम यह बात यूं ही नहीं कह रहे. इतिहास गवाह है कि पाकिस्तान ने बंटवारे के दौर से लेकर करगिल तक कबीलाई या आतंकवादी के रूप में ही घुसपैठ की है. रक्षा मंत्री साहब हमारे लोगों की जानें चली गईं, कितने बच्चे अनाथ हो गए, कितनों की मांग के सिंदूर उजड़ गए, कितने घरों के सहारे छिन गए और आप अभी तक यही सुनिश्चित करने में लगे हैं कि गोली किसने चलाई. जरूरत है यह जानने की कि आखिर पाकिस्तान की धरती से गोली चली क्यों. जब तक इन सवालों का जवाब पाकिस्तान से नहीं मांगा जाएगा, ठिगने कद का पाकिस्तान कभी सरबजीत को मारेगा, तो कभी हमारे सैनिकों का सिर कलम करेगा. सीज फायर के मायने सिर्फ भारत के लिए है, पाकिस्तान को इसकी कोई परवाह नहीं है. अगर परवाह होती, तो पिछले एक साल में पाकिस्तान लगभग 160 बार सीज फायर का उल्लंघन नहीं करता. रक्षा मंत्री साहब आपके कंधों पर देश की रक्षा का भार है. आप कुछ ऐसा ठोस कदम उठाएं, जिससे लगे कि उठाया गया कदम किसी रक्षा मंत्री का है. जनता में पाकिस्तान नियोजित हिंसा से भारी आक्रोश है. आखिर आपके सब्र का घड़ा कब भरेगा. आखिर कब तक पाकिस्तान हमारे छाती पर चढ़ कर उत्पात मचाता रहेगा. सोशल साइट्स पर जनता का आक्रोश साफ देखने को मिल रहा है, जहां लोग यह कहते देखे और सुने गए कि एंटनी पाकिस्तान के रक्षा मंत्री हैं. जब–जब चुनाव सिर पर आता है, यूपीए सरकार पाकिस्तान का राग अलापना शुरू कर देती है. ऐसा कर वह यह सिद्ध करना चाहती है कि वह सच्ची राष्ट्रभक्त है. उसे इस देश की सबसे ज्यादा चिंता है, जबकि सच्चाई यह है कि सरकार यह सब कर भ्रष्टाचार के आरोपों के चौतरफा हमले से बचना चाहती है. आम चुनाव सिर पर है, इसलिए भी वह पाकिस्तान का राग छेड़ कर अपना उल्लू सीधा करना चाहती है, लेकिन चुनाव अपनी जगह पर है और देश हित अपनी जगह पर. भला किस भारतीय को पाकिस्तान द्वारा भारतीय सैनिकों की लगातार की जा रही हत्याओं, गोलीबारी को लेकर भारत सरकार की नीतियों पर ऐतराज नहीं होगा. सरकार पाकिस्तान के मसले पर दो टूक निर्णय इसलिए नहीं ले पाती, क्योंकि वह इस मसले पर गंभीर नहीं है. सरकार सोच रही है कि इस बार वह क्या करे, जिससे जनता का वोट उसे हासिल हो सके. इसीलिए उसने अभी से ही पाकिस्तान का राग अलापना शुरू कर दिया है.

अब सवाल यह उठता है कि कौन हैं नवाज शरीफ और पाकिस्तान में उनकी बात कौन और कितना सुनता है? यह वही नवाज शरीफ हैं, जिन्होंने चुनाव के समय भारत से मधुर संबंध की बात बार–बार दोहराई थी. नवाज की बात पर भारत में लोगों ने विश्वास भी किया, लेकिन उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद भी आतंकवादियों की घुसपैठ रुकी नहीं. सत्ता में आते ही नवाज ने कहा था कि अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत–पाकिस्तान संबंध बहाली के लिए जो कदम उठाए थे, उसको आगे बढ़ाना है, लेकिन उनके आने के बाद से घुसपैठ की घटना और बढ़ गई है. उन्होंने यह भी कहा था कि करगिल युद्ध मुशर्रफ के कारण हुआ, लेकिन उन्हें यह पता होना चाहिए कि आज कोई मुशर्रफ नहीं हैं. नवाज शरीफ दोहरी चाल चल रहे हैं या कह सकते हैं कि वह दूसरे के कंधों पर बंदूक रख कर गोली चला रहे हैं. और वह कंधा है पाकिस्तानी आर्मी का. भला नवाज से ज्यादा अच्छी तरह से इस बात को कौन जानता है कि पाकिस्तान के शासन में वहां की आर्मी का क्या स्थान है. आज मुशर्रफ नहीं हैं, तो क्या हुआ, कयानी तो हैं. एक बार फिर से नवाज शरीफ पाकिस्तान के पीएम हैं, लेकिन लाख टके का प्रश्न यह है कि क्या नवाज शरीफ जनरल कयानी और उनके सहयोगियों को बुलाकर कड़ी फटकार लगाएंगे और पूछेंगे कि पाकिस्तानी फौज की टुकड़ी ने यह घृणित कार्य कैसे किया? सच तो यह है कि नवाज शरीफ की इतनी हिम्मत ही नहीं होगी कि जनरल कयानी और उनके सहयोगियों से इस बारे में कोई पूछताछ करें. आखिर लौट कर तो उन्हें पाकिस्तान ही जाना है.

सितम्बर महीने में संयुक्त राष्ट्र की आम बैठक होने वाली है. इस बैठक में भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ मिलेंगे. हो सकता है कि ये दोनों नेता भारत-पाकिस्तान रिश्तों के बारे में बातें करें, लेकिन भारत की जनता इस बार पाकिस्तान से किसी भी तरह की बात करने का विरोध कर रही है. बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत का पाकिस्तान से बात करना उचित है.

अब बात करते हैं पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की. आईएसआई को भारत विरोधी गतिविधियों को जारी रखने के लिए पाकिस्तान सरकार का पूरा संरक्षण प्राप्त है और ऐसे में उसके लिए यह जरूरी हो जाता है कि वह भारत विरोधी कुछ ऐसी गतिविधियों को अंजाम दे, जिससे पाकिस्तान सरकार को लगे कि वह बैठी नहीं है, खुफिया तंत्र होने के नाते वह सूचनाएं सरकार तक पहुंचा रही है, भले ही वह सूचनाएं मनगढ़ंत ही क्यों न हों. आखिर पाक सरकार को भी तो यह लगना चाहिए कि आईएसआई अपने कार्यों को ठीक ढंग से अंजाम दे रही है. तभी तो इस खुफिया एजेंसी को पैसा और हर तरह की सुविधाएं मुहैया करवाई जाएंगी, जो वह चाहती है, लेकिन भारत सरकार को पाक सरकार से बात कर शीघ्र हल निकालना होगा, ताकि आईएसआई भारत विरोधी गतिविधियों को जल्द से जल्द बंद करे.

दुनिया जानती है कि पाकिस्तान की सत्ता पर शुरू से ही वहां की मिलिट्री हावी है. जब भी मौका मिला, मिलिट्री ने पूरे लोकतंत्र की गर्दन ही मरोड़ दी. पाक मिलिट्री कभी नहीं चाहती है कि भारत–पाक के बीच अमन–चैन कायम हो, क्योंकि जब शांति स्थापित हो जाएगी, तो रक्षा मदों का बजट आवंटन कम हो जाएगा और पाक मिलिट्री के पास करने के लिए कुछ नहीं रह जाएगा. दूसरी ओर देखा जाए, तो पाक मिलिट्री अपनी भारत विरोधी हरकतों के कारण पाक सरकार के आंखों का तारा बनी रहना चाहती है और इस तरह से वह पाकिस्तान की राजनीति में सीधा तौर पर हस्तक्षेप करती है और कहीं न कहीं वह किंग मेकर की भूमिका में विराजमान रहती है. सरकार को पाकिस्तानी मिलिट्री से निपटने के लिए भारतीय सेना को इस बात की पूरी छूट देनी चाहिए कि अगर पाक आर्मी कुछ गलत करती है, तो भारतीय सेना उसी के लहजे में उसे जवाब दे. जब जक सेना को इस बात की पूरी छूट नहीं दी जाती, पाकिस्तान सरकार, वहां की आर्मी, आईएसआई और कतिपय आतंकवादी संगठनों का गठजोड़ नहीं टूटेगा और भारत इनके भंवर जाल से निकल नहीं पाएगा.

सितम्बर महीने में संयुक्त राष्ट्र की आम बैठक होने वाली है. इस बैठक में भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ मिलेंगे. हो सकता है कि ये दोनों नेता भारत–पाकिस्तान रिश्तों के बारे में बातें करें, लेकिन भारत की जनता इस बार पाकिस्तान से किसी भी तरह की बात करने का विरोध कर रही है. बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत का पाकिस्तान से बात करना उचित है. पूरे देश में भारतीय सैनिकों की हत्या के बाद तूफान खड़ा हो गया है. जनता की मांग है कि जब पाकिस्तान की फौज बेरहमी से हमारे शांति प्रिय जवानों की हत्या कर रही है, ऐसे में हमारी सरकार पाकिस्तान से क्या बातें करेगी और इन बातों से क्या लाभ होगा. जनता का सवाल एक हद तक जायज भी है, क्योंकि वार्ताएं पहले भी होती रही हैं, लेकिन समस्या का निदान होने की बजाए, समस्या बढ़ती ही गई. भारत को सुपर पावर अमेरिका से सबक लेनी चाहिए. अमेरिका अपने विरोधी देश को अपनी मौन से अपने होने का एहसास करा देता है. एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में अमेरिका के राष्ट्रपति ओबामा मास्को जाएंगे, लेकिन वह पुतिन से मुलाकात नहीं करेंगे, क्योंकि पुतिन ने अमेरिका के एक जासूस को अमेरिका के लाख विरोध के बावजूद अपने देश में पनाह दी है. क्या भारत भी संयुक्त राष्ट्र की आम बैठक में पाकिस्तान से बात करने से इंकार कर सकता है. अगर भारत अमेरिका का उदाहरण लेकर ऐसा करता है, तो यह संकेत जाएगा कि भारत बहुत दिनों तक इस तरह की गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेगा. आप हमारे जवानों की हत्या करें और हम शांति वार्ता का स्वागत करें, यह असंभव है.

आम जनता को भी भारत का यह रवैया समझ में नहीं आ रहा है. जनता सोचती है कि आखिर बात क्या है. हम पाकिस्तान को क्यों इतना शह दे रहे हैं? क्यों नहीं हमारी सरकार इस छोटे से देश को दो टूक जवाब देती है? कहीं हम पाकिस्तान से डर तो नहीं रहे हैं? अगर नहीं, तो वक्त की जरूरत यह है कि पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जाए. इस सिलसिले में भारत सरकार क्या निर्णय लेगी, कहा नहीं जा सकता, लेकिन एक बात तो तय है कि भारत में जनमत पाकिस्तान के खिलाफ उबल रहा है. सरकार को कुछ न कुछ कठोर कदम उठाना ही होगा. अन्यथा लोगों का गुस्सा कभी भी ज्वालामुखी बनकर फूट सकता है. और कुछ नहीं, तो भारत के प्रधानमंत्री को पाकिस्तान को एक कठोर सन्देश देना ही चाहिए कि बहुत हो गया अब भारत और अधिक बर्दाश्त नहीं करेगा. ■

कैसे निकले हल

भारत एक बड़ी शक्ति है, लेकिन हमारे देश के नेताओं ने अपनी सोच और नीतियों के द्वारा इस देश को अकर्मण्य बना दिया है. न तो वे अपने देश के साथ न्याय कर पा रहे हैं, न ही विदेशों में अपने देश की साख बचा पा रहे हैं. भारत और पाकिस्तान को उन सारी समस्याओं पर विचार-विमर्श करनी चाहिए, जिसे लेकर आए दिन तनाव की स्थिति पैदा होती रहती है. साथ में यह भी तय करना चाहिए कि दोनों देश आपसी विवाद को लेकर तीसरे किसी देश का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करेंगे. ऐसा नहीं कि दोनों देशों के बीच विचार-विमर्श नहीं होता. होता है, लेकिन उस पर अमल नहीं होता. इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है समस्याओं के निदान के लिए दृढ़ इच्छाशक्ति का अभाव. दोनों देशों के नेताओं का ढुलमुल रवैया भी इन समस्याओं के लिए उतना ही जिम्मेदार है. यही कारण है कि आज तक दोनों देशों के बीच किसी भी समस्या का निदान ठीक ढंग से संभव नहीं हो सका. आज जरूरत है ऐसे नेताओं की, जो इन सारी समस्याओं को लेकर साथ बैठें और तुरंत हल निकालें, क्योंकि अब तक की लंबी-लंबी शीर्ष स्तरीय वार्ताओं से कुछ हासिल नहीं हुआ.

feedback@chauthiduniya.com

साई

आस्था

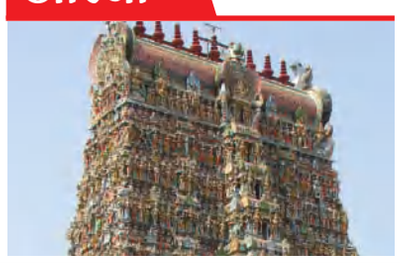

एक बार

साधु को प्यास लगी. वह नदी की धारा के निकट गया और ज्यों ही चौपाए की भांति झुक कर पानी पीने को हुआ कि उसके पैर उखड़ गए और वह पानी में बहने लगा, पर मुट्ठियां उसने तब भी नहीं खोलीं. पानी में डूबते–उतराते वह बेहाल हो गया और चट्टानों से टकराने के कारण उसका बदन लहू–लुहान हो गया.

साईं बाबा : श्रद्धा का अटूट नाम

चौथी दुनिया ब्यूरो feedback@chauthiduniya.com

श्री शिरडी बाबा को सबका मालिक एक मानकर पूजा जाता है. आज विश्व में कोई भी ऐसा देश, धर्म, जाति या वर्ग नहीं है, जिसमें श्री शिरडी साई बाबा के भक्त न हों. वे महान आध्यात्मिक विभूति थे. वे कब और कहां पैदा हुए, इसके बारे में कोई पुख्ता साक्ष्य नहीं हैं. संभवत: 1838 में ने जन्मे थे और अस्सी वर्ष की आयु में उन्होंने महाराष्ट्र के शिरडी नामक ग्राम में अपना शरीर त्यागा था. लोगों का मानना है कि वह ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे. हालांकि उन्होंने किसी को भी अपने परिवार, जाति या धर्म के बारे में नहीं बताया. उनका जीवन बेहद सादा था. वह भौतिकता से कोसों दूर रह कर साधारण जीवन जीते थे.

वे शेलू ग्राम के एक ब्राह्मण संत गुरु वेंकुशा के आश्रम में 12 वर्ष रहे थे. 1854 में अपने गुरु के आदेश व आशीर्वाद के साथ शिरडी ग्राम पहुंचे थे. वहां लगभग दो माह रहने के बाद वह अचानक वहां से चले गए और पुन: तीन वर्ष बाद 1858 में चांदभाई पाटिल (मुस्लिम जागीरदार) के भतीजे की बारात के साथ बैलगाड़ी में बैठकर शिरडी आए थे और फिर वहीं बस गए थे. वहां उन्होंने एक पुरानी त्यागी हुई वीरान मस्जिद को अपना स्थान बनाया और उसे द्वारिका माई का नाम दिया था.

वे हमेशा अल्लाह मालिक है, कहते रहते थे और सभी से, चाहे वह मानव हो या पशु–पक्षी, प्रेम और भाईचारे का व्यवहार करने का उपदेश देते थे. उन्हें संस्कृत, ऊर्दू, अरबी, मराठी, हिंदी और तमिल की जानकारी थी. वह शिरडी ग्राम के केवल पांच विशेष परिवारों से ही रोज दिन में दो बार भिक्षा मांगकर लाते थे. कुत्ते, बिल्लियां और पक्षी नि:संकोच आकर उनके भोजन का कुछ हिस्सा खा लेते थे. भोजन का जो हिस्सा बच जाता था, उसे वह अपने भक्तों के साथ मिल–बांट कर खा लेते थे. कहा जाता है कि वह त्रिकालदर्शी थे और लोगों के भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में जानते थे. लोग अपने कष्टों और समस्याओं के निदान के लिए बाबा के पास जाते थे और वहां से पूर्णत: संतुष्ट होकर लौटते थे. उन्होंने जिसको आशीर्वाद दिया, वह अवश्य ही फलीभूत हुआ. उनमें आजकल के संतों की तरह दिखावा नहीं था. उन्होंने लोगों के कल्याण के लिए कई चमत्कार किए थे. उनके चमत्कारों तथा भक्तों पर अनुग्रह की ख्याति धीरे–धीरे संपूर्ण विश्व में फैल गई. उनके इन सद्गुणों के कारण ही उन्हें विश्व गुरु स्वीकार किया गया है. लोगों का मानना है कि जो नित्य प्रति उनके नाम का स्मरण और पूजन करता है और उनकी कथाओं और लीलाओं का प्रेम पूर्वक मनन करता है, ऐसे भक्तों में सांसारिक वासनाएं और अज्ञान रूपी प्रवृतियां नहीं ठहर सकती हैं. ऐसे भक्तों को वह मृत्यु से बचा लेते हैं. उनकी कथाओं को श्रद्धा पूर्वक सुना जाए, मनन किया जाए, तो सुख और संतोष की प्राप्ति आसानी से संभव है. इससे श्रोताओं के चित्त को शांति प्राप्त हो जाएगी. केवल साई–साई के उच्चारण मात्र से ही भक्तों के सारे पाप नष्ट हो जाएंगे.

सभी ने ऐसा उपदेश दिया है कि प्रत्येक प्राणी की आत्मा एक सी है, आत्मा, परमात्मा की चिंगारी है, जो परमात्मा से ही निकली है और पुन: उन्हीं में लौट कर विलीन हो जाती है, लेकिन श्री शिरडी साई बाबा ही ऐसे एकमात्र अवतार पुरुष हुए हैं, जिन्होंने यह प्रयोग कई बार कर के दिखलाया था कि कैसे प्रत्येक प्राणी की आत्मा एक सी है. साई सद्चरित्र और बाबा पर लिखी गई कई पुस्तकों में ऐसी कई रोमांचकारी घटनाओं का वर्णन मिलता है, जिनसे ऐसा स्पष्ट होता है.

एक बार की बात है. भक्त के बुलावे पर श्री शिरडी साई बाबा उसके घर खाने गए, लेकिन वह कुत्ते के रूप में, निश्चित समय से पूर्व ही भोजन करने के लिए उसके पास पहुंचे. भक्त ने उस समय उस कुत्ते पर जलती हुई लकड़ी मारी और उसे भगा दिया. जब बाबा उसके घर खाने नहीं पहुंचे, तो भक्त ने बाबा की द्वारिका माई मस्जिद में आकर उलाहना दिया कि बाबा आप निमंत्रण स्वीकार करके भी नहीं आए? बाबा ने उत्तर दिया, मैं तो कुत्ते के रूप में तुम्हारे घर भोजन करने आया था, लेकिन तुमने तो जलती हुई चूल्हे की लकड़ी से मार कर मुझे भगा दिया. ■

चौथी दुनिया
एफ–2, सेक्टर–11, नोएडा (गौतमबुद्ध नगर), उत्तर प्रदेश, पिन–201301
ई–मेल feedback@ chauthiduniya.com

साई भक्तों!

आप भी चौथी दुनिया को साई से जुड़ा लेख या संस्मरण भेज सकते हैं. मसलन, साई से आप कब और कैसे जुड़े. साई की कृपा आपको कब से मिलनी शुरू हुई. आप साई को क्यों पूजते हैं. कैसे बने आप साई भक्त. साई बाबा का जीवन और चरित्र आपको किस तरह से प्रेरित करता है. साई बाबा के बारे में अनेक किंवदंतियां हैं, क्या आपके पास भी कुछ कहने के लिए है? अगर हां, तो केवल 500 शब्दों में अपनी बात कहने की कोशिश करें और नीचे दिए गए पते पर भेजें.

आस्था

रामेश्वरम की महिमा

धर्मेन्द्र कुमार सिंह

रामेश्वरम हिंदुओं का प्रसिद्ध तीर्थस्थल है. यह तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित है. इस मंदिर में स्थापित शिवलिंग बारह ज्योतिर्लिंगों में से एक है. रामेश्वरम मंदिर की दो मान्यताएं हैं. पहली यह कि जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम सीता को रावण से छुड़ाने के लिए लंका जा रहे थे, तब उन्हें रास्ते में प्यास लगी. जब वह पानी पीने लगे, तभी उनको याद आया कि उन्होंने भगवान शंकर का दर्शन नहीं किया है. ऐसे में वह कैसे जल ग्रहण कर सकते हैं. तब राम ने विजय प्राप्ति के लिए समुद्र किनारे बालू का शिवलिंग स्थापित करके पूजन किया था, क्योंकि भगवान राम जानते थे कि रावण भी शिव का भक्त है और उसे हरा पाना कठिन काम है. इसलिए भगवान राम ने शिव जी की प्राथना की और भगवान शिव प्रसन्न होकर माता पार्वती के साथ प्रकट हुए और भगवान राम को विजयी होने का आशीर्वाद दिया. भगवान राम ने शिवजी से लोक कल्याण के लिए उसी स्थान पर शिवलिंग के रूप में सदा के लिए निवास करने लिए कहा, जिसे भगवान शंकर ने स्वीकार कर लिया. वही शिवलिंग मंदिर में स्थापित है. दूसरी मान्यता है कि जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, रावण का वध करके अयोध्या लौट रहे थे, तब उन्होंने गन्धमादन पर्वत पर विश्राम किया. वहां उनसे ऋषियों ने कहा कि उनके द्वारा पुलस्त्य कुल का विनाश हुआ है, जिससे उन्हें ब्रह्म हत्या का दोष लगा है. भगवान राम ने पाप से मुक्त होने के लिए उनसे उपाय पूछा, तब ऋषियों ने कहा कि आप शिवलिंग की स्थापना कर पूजा करेंगे तो सभी पापों से मुक्त हो जाएंगे. रामजी ने हनुमान जी को आदेश दिया कि आप कैलाश पर्वत से शिवलिंग लेकर आइए.

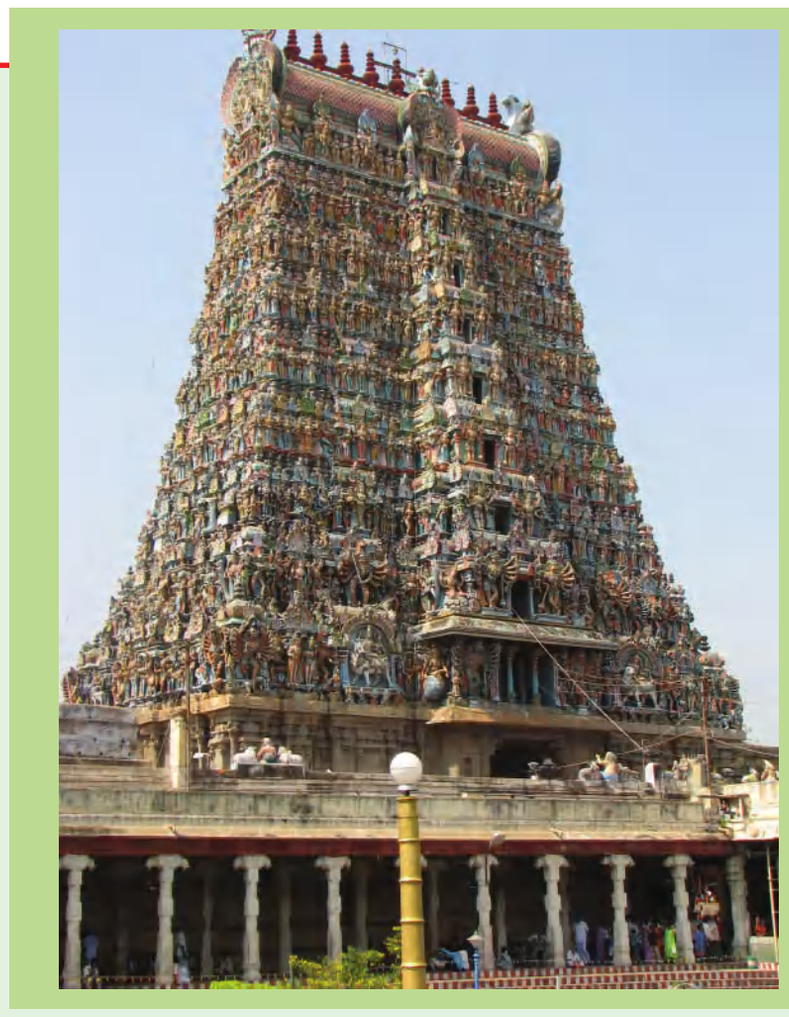

वहां हुनमान को शिव का दर्शन नहीं हुआ, तो उन्होंने तपस्या की. उसके बाद शिव का दर्शन प्राप्त हुआ, तब भगवान शंकर ने उन्हें शिवलिंग दिया, जिसे वह लेकर आए. उन्हें आने में देर होने के कारण भगवान राम ने माता जानकी द्वारा बनाए गए बालू के शिवलिंग का पूजन किया, क्योंकि पूजा करने का समय हो गया था और हनुमान द्वारा लाए गए शिवलिंग को भी वहीं समीप में स्थापित कर दिया गया और राम ने उस शिवलिंग का हनुमदीश्वर नाम रखा. रामेश्वरम और हनुमदीश्वर शिवलिंग की प्रशंसा भगवान राम ने स्वयं की है. मंदिर में इसके अतिरिक्त भी बहुत सारी सुन्दर शिव प्रतिमाएं स्थापित हैं और नन्दी की भी एक बहुत विशाल और आकर्षित मूर्ति लगाई गई है. शिव और पार्वती की प्रतिमाओं की प्रत्येक वर्ष शोभा यात्रा निकाली जाती है. इस अवसर पर सोने और चांदी के वाहनों पर भगवान शिव और पार्वती को बैठाकर उनकी सवारी निकाली जाती है. वार्षिकोत्सव के मौके पर ज्योतिर्लिंग को श्वेत उत्तरीय और चांदी के त्रिपुंड से सजाया जाता है. ज्योतिर्लिंग पर गंगा जल चढ़ाने का विशेष महत्व है. यदि आपके पास गंगा जल नहीं है, तो वहां के पुजारी दक्षिणा लेकर आपको गंगा जल देते हैं. वहां सुबह 4 बजे से 6 बजे के बीच मणि दर्शन कराया जाता है और मणि दर्शन में स्फटिक के शिवलिंग का दर्शन कराया जाता है. मंदिर के अन्दर विशालाक्षी देवी के गर्भ गृह के पास नौ ज्योतिर्लिंग हैं. बताया जाता है कि उनकी स्थापना विभीषण द्वारा कराई गई थी. रामेश्वरम के दर्शन मात्र से ब्रह्म हत्या जैसे पाप दूर हो जाते हैं. यहां दर्शन के लिए प्रत्येक वर्ष देश–विदेश से लाखों लोग आते हैं. रामेश्वरम का मंदिर अपने आप में एक अद्भुत सुंदरता संजोए हुए है. रामेश्वर का मंदिर निर्माण कला और शिल्प कला की सुंदरता का प्रतीक है. रामेश्वरम मंदिर का गलियारा विश्व का सबसे लंबा गलियारा है. रामेश्वरम एक शंख के आकार का द्वीप है और यह चारों तरफ से बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर से घिरा हुआ है.

कैसे पहुंचें – यह स्थान दक्षिण में समुद्र के किनारे स्थित है. यह हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी का संगम है. यहां जाने के लिए आप रेल और हवाई मार्ग का प्रयोग कर सकते हैं. इसके लिए सबसे पहले आपको चेन्नई जाना पड़ेगा. उसके बाद चेन्नई से आप दक्षिण रेलवे से रामेश्वरम जा सकते हैं. देश के विभिन्न हिस्सों से आप टूरिस्ट बसों के माध्यम से भी यहां पहुंच सकते हैं. ■

feedback@chauthiduniya.com

दर्शनीय

रामेश्वरम मंदिर के अन्दर शिव के अलावा और भी बहुत सारे मंदिर हैं. इसमें 22 कुएं हैं. यहां नंदी मंडप है, जो 22 फीट लंबा, 12 फीट चौड़ा और 17 फीट ऊंचा है. यह देखने में काफी आकर्षक लगता है. यहां पार्वती मंदिर, हनुमान मंदिर, सेतु माधव, राम सेतु और सीता कुंड जैसे दर्शनीय मंदिर और अन्य स्थल हैं, जो श्रद्धालुओं को अपनी ओर बरबस ही खींच लेते हैं.

पार्वती मंदिर – रामेश्वरम मंदिर में पार्वती की भी दो मुर्तियां हैं, जो अलग–अलग स्थापित हैं. ये पर्वतवर्द्धिनी और विशालाक्षी के नाम से जानी जाती हैं. यहां हनुमान का भी मंदिर है. इस मंदिर में बना गलियारा विश्व में सबसे बड़ा गलियारा है, जिसके खम्भे पर अलग कलाकृतियां बनाई गई हैं.

हनुमान मंदिर – रामेश्वरम मंदिर के पूर्व द्वार पर हनुमान का मंदिर है, जिसमें उनकी विशाल प्रतिमा स्थापित है. हनुमान की मूर्ति देखते से लगता है कि मानो वह साक्षात खड़े हैं. मूर्ति देखकर लोग भाव–विभोर हो जाते हैं. यहां श्रद्धालुओं की भारी भीड़ हनुमान की प्रतिमा देखने आती है.

सेतु माधव – वैसे तो रामेश्वरम भगवान शिव का मंदिर है, लेकिन शिवमंदिर के अंदर बहुत सारे मंदिर हैं, जो दर्शनीय हैं. उन्हीं में से एक सेतु माधव का मंदिर प्रमुख है, जिसमें भगवान विष्णु कि मूर्ति स्थापित है. यह देखने में मनभावन लगती है. कहा जाता है कि जो भी भक्त अपनी मुरादें लेकर यहां आते हैं, वे निराश नहीं लौटते.

सीता कुंड – मंदिर के पूर्वी द्वार पर सीता कुंड है. माना जाता है कि सीता ने अपना सतीत्व सिद्ध करने के लिए यहीं आग में प्रवेश किया था. सीता के आग में प्रवेश करते ही आग बुझ गई और कुंड में जल उमड़ पड़ा. वही कुंड अब सीता कुंड कहलाता है. यहीं पर हनुमान कुंड में पत्थरों को तैरते हुए भी देखा जा सकता है.

राम सेतु – यह वही रामसेतु है, जिसका निर्माण भगवान राम द्वारा लंका पर आक्रमण के समय किया था. मान्यता है कि भगवान राम द्वारा बार–बार प्रार्थना करने पर भी समुद्र ने रास्ता नहीं दिया. भगवान राम ने जैसे ही धनुष चढ़ाया तो समुद्र प्रकट हुआ. भगवान राम के क्रोध से डर कर समुद्र ने भगवान राम से कहा कि आप पत्थरों पर राम लिख कर सागर में फेंकिए, पत्थर तैरने लगेंगे. वही पुल आज राम सेतु के नाम से जाना जाता है.

एक बार

साधु को आत्मज्ञान

एक साधु था. वह नदी के किनारे कुटिया बनाकर रहता था. सांसारिक बंधनों को तिलांजलि देकर वह एकाग्र भाव से ईश्वर की आराधना में डूबा रहता था. एक दिन अचानक उसके मन में विचार आया कि जब भगवान सबका पालन करता है तो आदमी को कर्म क्यों करना चाहिए. वैसे भी आदमी के कोई काम करने पर उसके अंदर कर्त्तापन का अहंकार पैदा होता है और अहंकार कैसा भी हो, व्यक्ति को नीचे गिराता है.

यह सोचकर उसने अपने दोनों हाथों की मुट्ठियां बंद कर लीं और अपने को पूर्णतया प्रभु की मर्जी पर छोड़ दिया. वह नदी के किनारे चट्टान पर जा बैठा और प्रभु के ध्यान में लीन हो गया. कुछ दिन बीत गए. आस–पास के लोगों ने देखा कि साधु ने इतने दिनों से न कुछ खाया है, न पिया है. यह देख कर लोग उसके लिए

खाना लाए, पर वह खाता कैसे? उसकी मुट्ठियां जो बंधी थीं. लोगों ने इस कठिनाई को समझ कर उसे स्वयं खाना खिला दिया. साधु को प्यास लगी. वह नदी की धारा के निकट गया और ज्यों ही चौपाए की भांति झुक कर पानी पीने को हुआ कि उसके पैर उखड़ गए और वह पानी में बहने लगा, पर मुट्ठियां उसने तब भी नहीं खोलीं. पानी में डूबते–उतराते वह बेहाल हो गया और चट्टानों से टकराने के कारण उसका बदन लहू–लुहान हो गया. उसकी चेतना जाती रही. होश आया, तो उसने पाया कि वह नदी के किनारे पड़ा है. शरीर इतना कमजोर हो गया था कि उसके लिए आंखें खोलना भी कठिन हो गया. तभी कहीं से आवाज आई–अरे मूर्ख, तू बड़ा अज्ञानी है. तूने कर्म से मुंह मोड़ लिया, लेकिन यह नहीं सोचा कि अगर ईश्वर की यही इच्छा थी कि आदमी कुछ भी काम न करे तो उसने उसे दो हाथ क्यों दिए? हाथ कर्म करने के लिए हैं और जो उनका इस्तेमाल नहीं करता, वह चोरी करता है. साधु को अपनी भूल का एहसास हुआ. उसने मुट्ठियां खोल दीं और उस दिन से पहले की तरह कर्म में लीन होकर जीवन व्यतीत करने लगा. ■

शिक्षा : कर्म ही जीवन है

चौथी दुनिया ब्यूरो feedback@chauthiduniya.com

साहित्य

> ओरहान पामुक ने अपने एक साक्षात्कार में कहा था कि पाबंदियों के दौर में जो बात मैं तुर्की में रहते हुए चाह कर भी नहीं बोल सका था, वह बात कहने के लिए मैंने अपने नायक गालिब का सहारा लिया. हालांकि, द ब्लैक बुक के नायक की जुबानी कहें, तो किसी कहानी के मूल को ढूंढ पाना उतना ही मुश्किल है, जितना कि जीवन के मूल को ढूंढना.

कविता का मजबूत कोना

कविताओं में क्रांति, यथार्थ, सामाजिक विषमताओं, स्त्री विमर्श, दलित विमर्श आदि का इतना ओवरडोज हो गया कि वह आम पाठकों से दूर होती चली गई. कविता का रस तत्व यथार्थ की बंजर जमीन पर सूख गया. जरूरत है कि इस बात पर गंभीरता पूर्वक विचार हो कि कविता की लोकप्रियता कम क्यों हो रही है. सच पूछिए, तो लेखक ही बहुत हद तक इसके लिए जिम्मेदार हैं.

अनंत विजय

आज हिंदी में एक अनुमान के मुताबिक, 500 से ज्यादा कवि लगातार कविताएं लिख रहे हैं. छप भी रहे हैं. उसमें बुरी कविताओं की बहुतायत है. हिंदी में बुरी और स्तरहीन कविताओं के शोरगुल में अच्छी कविताएं कहीं गुम सी हो गई हैं. बुरी और स्तरहीन कविताओं के हो–हल्ले में सबसे बड़ा योगदान साहित्यिक पत्रिकाओं या तथाकथित लघु पत्रिकाओं के संपादकों की समझ का भी है. साहित्यक या लघु पत्रिकाओं के संपादकों ने स्तरहीन कविताओं को छाप–छाप कर अच्छी कविताओं को ओझल कर दिया है. आज हालात ये हो गए हैं कि हिंदी के प्रकाशक कविता संग्रह छापने से कन्नी काटने लगे हैं. मैं दर्जनों स्थापित कवियों को जानता हूं, जिन्हें अपना संग्रह छपवाने के लिए संघर्ष करना पड़ा है. प्रकाशकों की रुचि पाठकों के मूड का पता देती है या फिर यूं कह सकते हैं कि प्रकाशक जिस विधा की ओर ज्यादा भागते हैं, उससे इस बात का संकेत मिलता है कि पाठक इन दिनों क्या पढ़ रहे हैं. आजकल कविता संग्रह तो छपने ही कम हो गए हैं. कुछ स्थापित कवियों को छोड़ दें, तो ज्यादातर कविता संग्रह कवि खुद के श्रम से छपवाता है. हमें इस बात की पड़ताल करनी चाहिए कि इसकी वजह क्या है. क्या कविता पाठकों से दूर हो गई. क्या विचारधारा विशेष के तहत लिखी गई कविताओं और विचारधारा के बाहर की कविताओं के नोटिस नहीं लेने की वजह से ऐसा हुआ. मुझे लगता है कि कविताओं में क्रांति, यथार्थ, सामाजिक विषमताओं, स्त्री विमर्श, दलित विमर्श आदि का इतना ओवरडोज हो गया कि वह आम पाठकों से दूर होती चली गई. मुझे लगता है कि कविता का रस तत्व यथार्थ की बंजर जमीन पर सूख गया. मेरे सारे तर्क बेहद कमजोर हो सकते हैं, लेकिन मैं विनम्रता पूर्वक यह सवाल उठा रहा हूं कि इस बात पर गंभीरता पूर्वक विचार हो कि कविता की लोकप्रियता कम क्यों हो रही है. मैं यहां जान–बूझकर लोकप्रियता शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, क्योंकि जन और लोक की बात करने वाले लेखक ही बहुत हद तक इसके लिए जिम्मेदार हैं. लेखक संघों ने जिस तरह से कवियों को अपने पाले में खींचा और उसको बढ़ाया, उससे भी कविता को नुकसान हुआ. पार्टी लाइन पर कविताएं लिखी जाने लगीं. लेखक संघों के प्रभाव में कई कवि लागातर स्तालिन और ज्दानेव की संकीर्णतावादी राजनीतिक लाइन पर चलते रहे. यह मानते हुए कि पार्टी लाइन न कभी जन विरोधी हो सकती है और न ही सत्साहित्य विरोधी. जब लेखक संघों का दौर था, तब उसी दौर में मुक्तिबोध ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव को एक पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि कलात्मक कृतियों को महत्व देना ही होगा और गैर कलात्मक प्रगतिशील लेखन की आलोचना करनी ही होगी, फिर उसका लेखक चाहे कितना ख्यात और प्रसिद्ध क्यों न हो. मुक्तिबोध के मुताबिक छिछली, जार्गन ग्रस्त, रूढ़ और अवसरवादी आलोचना ही सबसे ज्यादा ही प्रगतिशील आंदोलन की पिछले दशकों में हुई क्षति के लिए उत्तरदायी है. ऐसा नहीं है कि हमारे सभी कवि ऐसा ही लिखते रहे. केदार, नागार्जुन और मुक्तिबोध गहरे राजनीतिक सरोकार वाले कवि हैं. केदार ने आंदोलनात्मक राजनीतिक कविताएं लिखीं, लेकिन लोक जीवन, प्रेम और प्रकृति की विलक्षण कविताएं भी लिखीं. केदारनाथ सिंह और रघुवीर सहाय ने भी. दोनों लोकप्रिय भी हुए, लेकिन जो खुद को नक्सलबाड़ी की संतानें कहा करते थे,

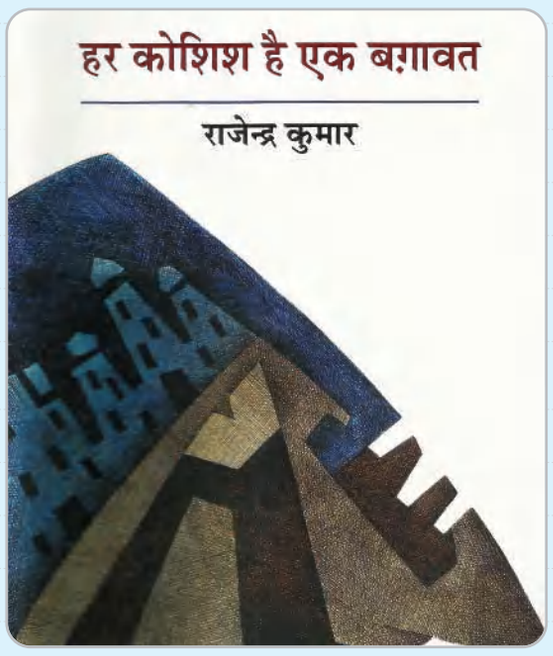

वे उस दौर के साथ ही ओझल हो गए. वजह पर विमर्श होना चाहिए. आज हिंदी को एक निरपेक्ष प्रगतिशीलता की दरकार है, जिससे कविता का स्वर्णिम दौर फिर से वापस लौट सके.

अभी–अभी एक दिन डाक से मुझे वरिष्ठ कवि, आलोचक और लंबे समय से साहित्यिक पत्रिका अभिप्राय का संपादन कर रहे राजेन्द्र कुमार का कविता संग्रह मिला. अंतिका प्रकाशन से बेहद सुरुचिपूर्ण तरीके से यह संग्रह प्रकाशित है. इस संग्रह को पढ़ने के बाद पता चला कि यह राजेन्द्र कुमार जी का दूसरा कविता संग्रह है. उनका पहला संग्रह 1978 में छपा था. लगभग पैंतीस वर्षों बाद भी राजेन्द्र कुमार की कविताओं का संकलन शैलेय जी ने किया है. इस संकलन के बारे में लिखते हुए शैलेय कहते हैं कि इस कविता संग्रह के रूप में राजेन्द्र कुमार की कविताओं को संकलित करना उस काव्य खनिज का उत्खनन करने जैसा रहा, जो अन्यथा उनकी डायरियों और विभिन्न पत्र–पत्रिकाओं के पन्नों में ही दबा पड़ा रह जाता. शैलेय ठीक ही कह रहे हैं. राजेन्द्र कुमार ने प्रचुर मात्रा में लेखन किया है, लेकिन उनका मूल्यांकन ठीक से नहीं हो पाया है. लेखन में केंद्र पर रहने के बावजूद, राजेन्द्र कुमार का लेखन अब तक साहित्यिक परिधि पर है. इस पर भी साहित्य के कर्ता–धर्ताओं को गंभीरता से विचार करना चाहिए.

राजेन्द्र कुमार का नया कविता संग्रह हर कोशिश है एक बगावत, उनके लगभग पचास वर्षों के लंबे काल खंड में लिखी गई साठ कविताओं का संकलन है. राजेन्द्र कुमार के नये कविता संग्रह हर कोशिश है एक बगावत को पढ़ने के बाद लगा कि राजेन्द्र जी का अनुभव संसार और रेंज बहुत व्यापक है, लेकिन उनकी कविताओं में समाज और आस–पास का परिवेश और उस दौर में घट रही प्रमुख घटनाएं बेहद प्रमुखता से आती हैं. वहां चिड़िया है, फाटक है, सरकारी दफ्तर है, सड़कों का बनना है, मूंगफली के छिलके हैं, आतंकी और आतंकवादी हैं . इन सारे विषयों को कवि ने अपनी कविताओं में समेटा है. 2008 की उनकी दो कविताएं आतंकी और आतंकवादी विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं. आतंकी कविता में कवि आतंकवाद की ओर प्रवृत्त होने और अपने होने को सिद्ध करने की ललक के तौर पर देखते हैं. वहीं, आतंकवादी कविता में कवि शुरू में तो उनको हमारी तरह का ही मानते हैं–वे सब भी हमारी ही तरह थे/अलग से कुछ भी नहीं, कुदरती तौर पर. इन लाइनों में कुदरती तौर पर, शब्द पर गौर किया जाना चाहिए. इसके अलावा इस कविता में कवि ने जो बिंब चुने हैं, वे भी बेहतर हैं. जैसे एक जगह वह कहते हैं कि हवा भी उनके लिए आवाज थी, कोई छुअन नहीं/कि रोओं में सिहरन बन व्यापे/वह सिर्फ कानों में सरसराती रही/और उन्हें लगा कि उन्हें ही तय करना है–/दुनिया में क्या पाक है और क्या नापाक. दोनों कविता में कवि अपनी भावनाओं को व्यक्त करते वक्त बेहद सावधान रहता है और इस बात को लेकर सतर्क भी कि कविताओं से आतंकवाद का महिमामंडन न हो. जैसे आतंकवादी कविता के अंत में वह कहता है–और वो जंग, जिसमें सबकी हार ही हार है/जीत किसी की भी नहीं/उसे वे जेहाद कहते हैं. इसमें दो पंक्तियों पर ध्यान दिया जाना चाहिए. सबकी हार ही हार है और जीत किसी की भी नहीं. यानी कवि जोर देकर कह रहा है कि आतंकवाद से किसी का भी भला नहीं है.

इस संग्रह को मोटे तौर पर तीन हिस्सों में बांटा गया है. पहले हिस्से–हर कोशिश है एक बगावत के अलावा, दो हिस्सों में कविता के सवाल और कविता के किरदार हैं. एक बेहद दिलचस्प कविता है–अमरकांत, गर तुम क्रिकेटर होते. इसमें अपने साथी को क्रिकेटर के तौर पर देखना और उसी बहाने तंज करना, यह राजेन्द्र कुमार की कविताओं को एक नया आयाम तो देता ही है, एक अलग स्तर पर भी ले जाता है. कविता के किरदार का रेंज बड़ा तो है ही, विशेष भी है. उसमें बहादुरशाह जफर भी हैं, तो ओसामा बिन लादेन भी हैं. भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा हैं, तो अज्ञेय भी हैं. वहीं छन्नन और मनसब मियां भी हैं. राजेन्द्र कुमार के इस कविता संग्रह को पढ़ने के बाद मुझे पर्याप्त आनंद आया और लगा कि इतने घटाटोप भरे कविता समय में भी हिंदी कविता कुछ हाथों में सुरक्षित है. इस बात की जरूरत है कि कविता के आलोचक अच्छी कविताओं को चिन्हित करें और बुरी कविताओं को बहुत ही मजबूती के साथ खारिज करें, लिखित और मौखिक दोनों स्तर पर. ■

(लेखक IBN7 से जुड़े हैं)

anant.ibn@gmail.com

कविता

आधुनिकता और नारी

राजीव रंजन

कल तक थीं परदे के भीतर
था स्वभाव उनके लज्जा का
आज हैं परदे से बाहर
निर्लजता का सबक लिए
स्वतंत्रता का गलत अर्थ लगा कर
अपने अस्तित्व को भुला कर
आधुनिकता के बाढ़ में
फैशन की आड़ में
देह का अश्लील प्रदर्शन
संकेत है यह वर्त्तमान का
सोच से भी परे था जो
नारी का यह रूप
सब कुछ लुटा दिया है तूने
नहीं रहा तुझ पर विश्वास
संभल जाओ वक्त है अभी
धिक्कारते हैं, तुम्हें लोग सभी
भुला दिया तूने अपनी पहचान
क्या थी, क्या हो गई
लौट जाओ मर्यादा के भीतर
वर्त्तमान को छोड़ दो
होगा तभी तेरा सम्मान
ऐ जगत की नारियों

किताब मिली

पुस्तक	लेखक
तारे धरती पर आकाश में हम	आशीष भारती
प्रकाशक	**मूल्य**
समय प्रकाशन	150 रुपए

आशीष भारती की पुस्तक तारे धरती पर आकाश में हम, समय प्रकाशन से आई है. इस पुस्तक में लेखक ने ब्रह्मांड, इसकी व्युत्पत्ति, आत्मा, परमात्मा, प्रेम, दुख–सुख जैसे विषयों पर शास्त्रों का सहारा लेकर लेखनी चलाई है. विभिन्न आध्यात्मिक विषयों, जिन पर बहुत कुछ लिखे जाने के बाद भी उनके रहस्य अभी तक अनसुलझे हैं, लेखक ने अपने नजरिये से प्रकाश डालने की कोशिश की है.

लेखक और प्रकाशक इस कॉलम के लिए अपनी किताबें हमें भेज सकते हैं.
चौथी दुनिया
एफ–2, सेक्टर–11, नोएडा–201301
ई–मेल: feedback@chauthiduniya.com

समीक्षा

स्थानीयता का अंतरराष्ट्रीय आख्यान

चौथी दुनिया ब्यूरो

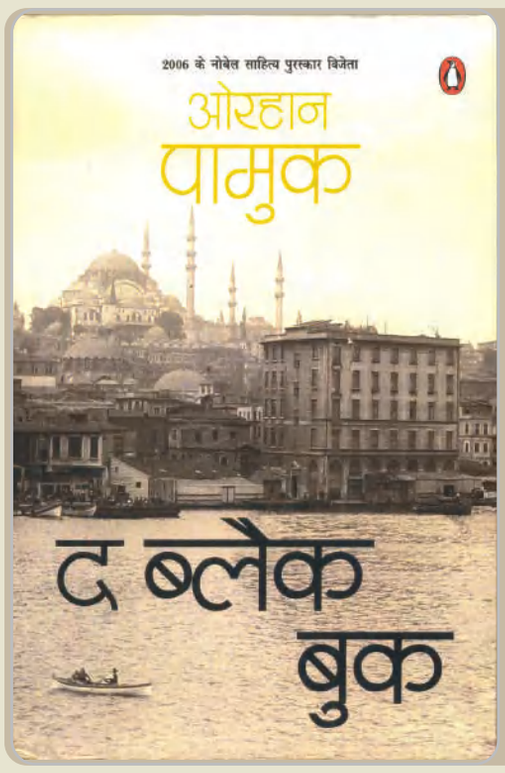

समीक्ष्य पुस्तक : द ब्लैक बुक

लेखक : ओरहान पामुक

अनुवादक : नवेद अकबर

प्रकाशक : पेंगुइन बुक्स

नोबेल पुरस्कार विजेता लेखक ओरहान पामुक को पढ़ना, लेखनी की जादुई दुनिया की सैर करना है. तुर्की मूल के लेखक ओरहान पामुक स्थानीयता का अंतरराष्ट्रीय आख्यान प्रस्तुत करने वाले ऐसे ख्याति प्राप्त रचनाकार हैं जो एक देश और जनता के संघर्षों को जुबान देते हैं. उन्होंने अपनी रचनाओं में उनके पैतृक नगर इस्तांबुल के यथार्थ का ऐसा काल्पनिक मुहावरा रचा कि वह पूरब और पश्चिम की सभ्यताओं के बीच टकराव का वैश्विक दस्तावेज बन गया. माई नेम इज रेड, इस्तांबुल, म्यूजियम ऑफ इनोसेंस और द व्हॉइट कॉसल जैसी मशहूर किताबों के लेखक ओरहान पामुक का जासूसी उपन्यास द ब्लैक बुक पेंगुइन बुक्स प्रकाशन ने हिंदी में छापा है. 36 अध्यायों वाले इस जासूसी उपन्यास का अनुवाद किया है नवेद अकबर ने. हालांकि, ओरहान पामुक ने यह उपन्यास 1985 में लिखना शुरू किया था, जो 1990 में ही प्रकाशित हुआ था. अंग्रेजी में इसका पहला संस्करण 1994 में प्रकाशित हुआ.

जासूसी उपन्यास द ब्लैक बुक 1980 में तुर्की में बगावत के पहले की कहानी है. यह वह समय है, जब तुर्की कड़े संघर्षों के दौर से गुजर रहा था. समीक्षकों का मत है कि ओरहान पामुक पहले लेखक हैं, जिन्होंने 19वीं सदी के रियलिज्म यानी यथार्थवाद को पहली बार अपनी रचनाओं में उतारा.

द ब्लैक बुक की कहानी बहुत साधारण सी है. उपन्यास में गालिब नाम का एक युवक है, जिसकी पत्नी रूया उसे छोड़कर कहीं चली जाती है. गालिब अपनी लापता पत्नी को इस्तांबुल की गलियों में ढूंढता फिर रहा है. पत्नी की तलाश के बहाने गालिब इस ऐतिहासिक शहर की परतें उघाड़ता है. पामुक गालिब की जुबानी इस्तांबुल में व्याप्त अंतर्विरोध, शक्तिशाली समूहों, व्याप्त आडंबर और द्वैध, नकली व भद्दी किस्म की आधुनिकता का चित्रण करते हैं. अध्याय चार–अलादीन की दुकान में नायक जब शहर के अंतर्विरोध बयान कर रहा होता है, तो यह प्रसंग उल्लेखनीय है–तूफान गुजर जाने के बाद सपनों के लिए एक नया पागलपन पैदा हो जाएगा और सब लोग छोटी–छोटी पुस्तिकाएं खरीदने के लिए कतारें लगाने लगेंगे, जिनमें सपनों के मायने बताने का दावा किया जाता है. शहर में एक अमेरिकी फिल्म आएगी और हर लड़का काला चश्मा लगाना चाहेगा. अखबारों में कुछ और आएगा और सारी महिलाएं लिप ग्लॉस लेना चाहेंगी या सारे पुरुष वो गोल टोपियां पहनना चाहेंगे, जिनसे वो इमामों जैसे दिखने लगेंगे, लेकिन ज्यादातर शहर भर में हैजे की तरह फैलने वाले ये पागलपन बिना किसी कारण के उठते महसूस होंगे. वरना क्या कारण हो सकता है कि हजारों, बल्कि दसियों हजार लोग अचानक फैसला कर लें कि उनके कमरे आदि एक ही जैसी लकड़ी की नाव से सजाए जाएं. कैसे कोई समझ सकता है कि क्यों हर मां और बच्चा, मर्द और औरत, बूढ़े और जवान, अचानक एकदम यूरोपीय चेहरे पर एक बहते आंसू वाले उस मासूम बच्चे की तस्वीर की इच्छा करने लगते हैं? या क्यों अचानक ये चेहरा आपको शहर की हर दीवार और दरवाजे से झांकता दिखाई देने लगता है...? उपन्यास का मुख्य कथानक तुर्की की जनता पर पहचान के संकट को व्याख्यायित करता हुआ आगे बढ़ता है.

ओरहान पामुक ने अपने एक साक्षात्कार में कहा था कि पाबंदियों के दौर में जो बात मैं तुर्की में रहते हुए चाह कर भी नहीं बोल सका था, वह बात कहने के लिए मैंने अपने नायक गालिब का सहारा लिया. एक नागरिक के तौर पर जो ओरहान पामुक खुद नहीं बोल सके, वह उन्होंने अपनी रचना के नायक के मुंह से कहलवाया. हालांकि, द ब्लैक बुक के नायक की जुबानी कहें, तो किसी कहानी के मूल को ढूंढ पाना उतना ही मुश्किल है, जितना कि जीवन के मूल को ढूंढना.

ओरहान पामुक का द ब्लैक बुक जासूसी उपन्यास को एक आयाम देने वाली रचना है. इसकी कहानी काफी मजेदार है, जो आपको लंबे समय तक न सिर्फ याद रह सकती है, बल्कि आपको आठवें दशक के तुर्की के बारे में बहुत कुछ बता सकती है. यह किताब पढ़ते हुए एक बात जो खटकती है, वह है इसका अनुवाद. यह अच्छा है, लेकिन और बेहतर हो सकता था. अनुवादक ने हिंदी के वाक्यों को बहुत जगह अंग्रेजी वाक्य विन्यास में गढ़ने की कोशिश की है, जो न सिर्फ कहीं–कहीं कहानी के प्रवाह में बाधक साबित होता है, बल्कि कहानी समझने के लिए पाठक से अतिरिक्त मेहनत करवाता है. हालांकि, कहानी की रोचकता के सामने यह बात बहुत मामूली है. ■

feedback@chauthiduniya.com

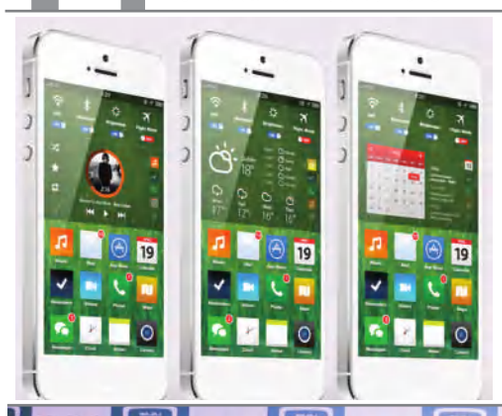

आईओएस 7 लोकेशन फीचर: मैप पर बने सर्कल्स के जरिये यह फीचर बताता है कि यूजर किसी जगह पर कितनी बार गया और वहां कितना समय बिताया. वैसे इस फीचर को लेकर थोड़ा विवाद और खतरा भी है.

बजाज की आरई 60

काफी समय से लोगों के बीच चर्चित बजाज की आरई60 जल्द ही बाजार में आने को तैयार है. नये समाचार के अनुसार कंपनी अक्टूबर तक आरई 60 को लाने की तैयारी कर रही है. केवल बजाज अपनी इस क्वाड-रिसाइकल कार की सरकार से क्लियरेंस का इंतजार कर रही है. क्वाड-रिसाइकल उस कार को कहते हैं जो ऑटोरिक्शा से बड़ी और एंट्री लेवल कार वाले सेगमेंट में आती हो. भारत में उतारने के साथ ही बजाज अपनी इस नई कार को विदेशों में एक्सपोर्ट भी करेगी. कंपनी का इरादा आरई60 को व्यावसायिक वाहन के तौर पर पेश करना है. यह कस्बों और गावों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट और सामान ले जाने के लिए भी इस्तेमाल की जा सके. कंपनी केवल इसको पास करने के लिए सरकार का इंतजार कर रही है.कानून मंत्रालय और सड़क परिवहन मंत्रालय से इस नई कार को लेकर विमर्श चल रहा है. अभी तक यह तय नहीं किया जा सका है कि यह कार किस कैटेगरी में रखी जाएगी. आरई की अधिकतम स्पीड 70 किमी प्रतिघंटा है और इसकी कीमत 1,30,000 से 1,40,000 तक होगी. इस कार में ड्राइवर को लेकर चार लोग आराम से बैठ सकते हैं. इस कार में दो लोगों के साथ 500 किलोग्राम तक भार रखा जा सकता है. कंपनी को आशा है कि पब्लिक ट्रासपोर्ट की जगह इस कार को सामान लाने-ले जाने के लिए प्रयोग किया जा सकेगा. इस कार में 200 सीसी के सिंगल इंजन का इस्तेमाल किया गया है. जो 20बीएचपी की ताकत देता है. इसकी माइलेज क्षमता इसकी यूएसपी है. कंपनी का कहना है कि यह कार 35 किमी प्रति लीटर तक की माइलेज देगी. जो व्यवसायिक वाहन के लिए काफी अच्छा है. ■

ऐप्स की बदौलत अब आम लोगों की सहायता में और तेजी आएगी.

मोबाइल एप्लीकेशन: बनाए आपकी जिंदगी को आसान

उद्योग समाधान के लिए बनी संस्था सैप ने तीन ऐसे एप्लीकेशन बनाए हैं, जो सरकार के अलग-अलग विभागों की मदद करेंगे.

सैप ने सरकारी विभागों की क्षमताओं में इजाफा होगा. इन ऐप्स की बदौलत अब आम लोगों को सूचनाएं मुहैया कराने में और तेजी आएगी.

ये तीन ऐप्स हैं रक्षक, ट्रैको हेल्थ और द मिल्क कॉपरेटिव. इन ऐप्स की बदौलत क्राइम, स्वास्थ्य और मिल्क कॉपरेटिव सोसाइटी जैसे मुद्दों पर आम लोगों की सहायता और सटीक आंकड़ों में मदद मिलेगी.

ऐप्स रखे आपकी सेहत का ख्याल

1 रक्षक 2.0

रक्षक 2.0 एक ऐसा ऐप्लीकेशन है जो क्राइम के आंकड़ों के लिए बनाई गई है. इसकी मदद से तमाम राज्यों में हुए अपराधों का पूरा डाटा रखा जा सकेगा. इसी डाटा की बदौलत सरकारी एजेंसियों को अपराध से लड़ने में मदद मिलेगी. अब आसानी से एक क्लिक में जाना जा सकेगा कि किस राज्य में कितनी और किस किस्म की वारदातें हुईं हैं. इन्हीं डाटा की बदौलत ऐंजेसियां अपनी नीतियां बनाएंगी और उसमें बदलाव कर पाएंगीं. इससे उनकी कार्यक्षमताओं में भी तेजी आएगी.

2 ट्रैको हेल्थ एप्लीकेशन

इसकी बदौलत स्वास्थ्य से संबंधित सारे आंकड़ों की जानकारी रखी जा सकेगी. इसकी बदौलत बीमारियों के आंकड़े आदि रखना और आसान हो जाएगा. इससे आसानी से क्षेत्र की समस्याओं को समझा जा सकता है और इस पर कार्रवाई भी की जा सकती है. इसका सीधा फायदा आम आदमी को मिलेगा.

3 मिल्क कॉपरेटिव ऐप्स

इस नढ ऐप्स की बदौलत दूध के आंकड़ों से लेकर उसके प्रबंधन और वितरण तक की जानकारी रखी जा सकेगी. ये सोसायटी के कामों में तेजी के साथ सटीक आंकड़े भी देगा. इन आकंड़ों की बदौलत फिलहाल की स्थिति को समझा जा सकेगा. ये सभी सरकारी ऐंजेसियों की मदद कर पाएंगे. इनकी बदौलत सेवाएं मुहैया कराने में आसानी होगी.

जल्द आ रहा है लूमिया 925

भारत के लिए नोकिया की वेबसाइट पर यह स्मार्टफोन मकमिंग सूनफ्के लेबल के साथ दिख रहा है. फ्लिपकार्ट का कहना है कि अगस्त के आखिरी हफ्ते में नोकिया लूमिया 925 के रिलीज होने की उम्मीद है. मेटल डिजाइन के साथ ही इस स्मार्टफोन में प्योरव्यू कैमरा टेक्नॉलजी है.

नोकिया ने भारत में अपनी लूमिया 925 को लेकर कोई घोषणा नहीं की है, लेकिन आप ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट फ्लिपकार्ट के जरिए स्मार्टफोन की प्री-बुकिंग 33,999 रुपये में कर सकते हैं. भारत के लिए नोकिया की वेबसाइट पर यह स्मार्टफोन मकमिंग सूनफ के लेबल के साथ दिख रहा है. फ्लिपकार्ट का कहना है कि अगस्त के आखिरी हफ्ते में नोकिया लूमिया 925 के रिलीज होने की उम्मीद है. मेटल डिजाइन के साथ ही इस स्मार्टफोन में प्योरव्यू कैमरा टेक्नोलॉजी है. कंपनी की मानें तो इस टेक्नोलॉजी के कारण फोटो और वीडियो बहुत क्लियर और शॉर्प आएंगे. इस फोन में 1280-768 रिजॉल्यूशन वाला 4.5 इंच का एमोलेड वीएक्सजीए डिस्प्ले है. इसे ग्लव्स पहन कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं. इस फोन में 1.5 गीगाहट्र्ज ड्यूल-कोर स्नैपड्रैगन प्रोसेसर है और यह विंडोज़ फोन 8 ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है. इस फोन में प्योरव्यू 8.7 मेगापिक्सल के कैमरे के साथ ही, इसमें ऑप्टिकल इमेज स्टैबिलाइजेशन, ऑटोफोकस, हाई पावर ड्यूल एलईडी फ्लैश, 1080पी एचडी वीडियो रिकॉर्डिंग भी है. 1.2 मेगापिक्सल वाइड ऐंगल का फ्रंट कैमरा भी है. इस फोन में 2000 एमएच की बैटरी है. इस फोन को वायरलेस से भी कर सकते हैं. फोन में 1 जीबी की रैम के साथ ही 16 जीबी की स्टोरेज है. ■

मोटोरोला का नेक्सस 5

अब तक अटकलें लगाई जाती रही हैं कि गूगल के नये नेक्सस स्मार्टफोन को एलजी बनाएगी, लेकिन टेलर विंबर्ली ने इससे अलग जानकारी दी है कि इसे मोटोरोला बनाएगी. टेलर ने मोटो एक्स के लॉन्च से पहले कई भरोसेमंद रिपोर्ट्र्स लीक की थीं. टेलर ने अपने गूगल प्लस पर लिखा है कि मोटोरोला चौथी तिमाही में नया नेक्सस स्मार्टफोन रिलीज करेगी और यह मोटो एक्स नहीं है. इससे पहले माना जाता रहा है कि नया नेक्सस स्मार्टफोन एलजी बनाएगी और यह इसी हफ्ते लॉन्च हुए एलजी जी2 के आधार पर होगा. हालांकि फोन चाहे जो कंपनी बनाए, लेकिन यह तय माना जा रहा है कि गूगल के इस अगले स्मार्टफोन में ऐंड्रॉयड 5 की लाइम पाई ऑपरेटिंग सिस्टम होगा. ■

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

बेहतरीन है बजाज पल्सर 300

स्पोर्ट्र्स बाइक के शौकीनों को बजाज का नया मॉडल बजाज पल्सर 300 जरूर पसंद आएगा. इस बाइक की विशेषता यह है कि यह काफी स्लिम तो है ही, साथ ही इसमें सेफ्टी और आरामदायक फीचर्स भी हैं. भारतीय बाजार में स्पोर्ट्र्स बाइक की मांग को देखते हुए बजाज ने यह बेहतरीन मॉडल उतारा है. इस जानदार बाइक का दाम एक लाख से सवा लाख के बीच रखा गया है ■

एप्पल के आईओएस 7 में होगा फ्रीक्वेंट लोकेशंस फीचर

फ्रीक्वेंट लोकेशंस का उद्देश्य भले ही यूजर्स को जरूरी जानकारी उपलब्ध कराने के साथ-साथ अपने मैपिंग ऐप को बेहतर बनाना हो लेकिन इससे यह भी साबित होता है कि आप पर किसी नजर लगातार है.

एप्पल ने इस हफ्ते आईओएस 7 बीटा का नया वर्जन जारी किया है. इस नए वर्जन में फ्रीक्वेंट लोकेशंस का एक नया फीचर दिया गया है जो यूजर्स को एक मैप के जरिये उनकी पसंदीदा और मोस्ट विजिटेड जगहों की जानकारी देता है. मैप पर बने सर्कल्स के जरिये यह फीचर बताता है कि यूजर किसी जगह पर कितनी बार गया और वहां कितना समय बिताया. वैसे इस फीचर को लेकर थोड़ा विवाद और खतरा भी है. फ्रीक्वेंट लोकेशंस का उद्देश्य भले ही यूजर्स को जरूरी जानकारी उपलब्ध कराने के साथ-साथ अपने मैपिंग ऐप को बेहतर बनाना हो लेकिन इससे यह भी साबित होता है कि आप पर किसी नजर लगातार है. यह फीचर आपसे जुड़ी अहम जानकारी इकट्ठा करता है और उसे साझा करता रहता है.

ऐसे में इसे इस्तेमाल न करने वाले यूजर्स इस आसानी से बंद कर सकते हैं. इसके लिए आपको सेंटिंग्स ऐप्स में जाकर प्राइवेसी पर जाना होगा. इसमें लोकशंस सर्विसेज के जरिये सिस्टम सर्विसेज और फिर फ्रीक्वेंट लोकेशंस तक पहुंचा जा सकता है. यहां पहुंचकर आप इसे ऑफ कर सकते हैं. फिलहाल यह फीचर सिर्फ आईओएस 7 बीटा पर है जो सिर्फ डेवेलपर्स के लिए है. ऐप्पल का आईओएस 7 जल्द ही आम यूजर्स के लिए भी लॉन्च होने वाला है.■

विज्ञापन हेतु संपर्क करें : email : advt@chauthiduniya.com

> क्रिकेट में चीटिंग एक वायरस की तरह घर कर गई है, जिसने पहले तो गेंदबाजों को अपने आगोश में लिया. जब वहां लंबे समय तक बात नहीं बनी, तो उसने अपना दूसरा शिकार बल्लेबाजों को बनाया. बल्लेबाज बल्ले में टेंपरिंग करने लगे. आईसीसी के नियमों के अनुसार, सामान्य तौर पर बल्ले का आकार और प्रकार निश्चित है.

अब बल्ले से छेड़छाड़ !

क्रिकेट को भारत में धर्म के तौर पर देखा जाता है, लेकिन जब से इस खेल में व्यावसायिकता ने जगह बनाई है तब से मैदान के भीतर और बाहर यह खेल केवल खेल नहीं रह गया है. अब खिलाड़ी केवल बॉल और बल्ले के साथ उन चालबाजियों के साथ मैदान में उतर रहे हैं जो जेंटलमेंस गेम कहे जाने वाले इस खेल की प्रतिष्ठा के लिए तो खतरा हैं ही, खिलाड़ियों की विश्वसनीयता को भी कठघरे में खड़ा कर रही हैं.

नवीन चौहान

क्रिकेट में चीटिंग का पुराना इतिहास है. बॉल टेंपरिंग, मैच फिक्सिंग, स्पॉट फिक्सिंग से बात अब बैट टेंपरिंग तक पहुंच चुकी है. जेंटलमैन गेम कहलाने वाले इस खेल के खिलाड़ी महज थोड़े से फायदे के लिए स्पिरिट ऑफ गेम या कहें कि खेल भावना को कहीं पीछे छोड़ चुके हैं. पहले इस खेल में गेंदबाजों द्वारा गेंद से छेड़छाड़ करना एक सामान्य सी बात थी, जिसमें गेंदबाज गेंद की चमक को बरकरार रखने के लिए वेसलीन, जेली जैसी चीजों का उपयोग करते थे, लेकिन पाकिस्तानी गेंदबाज बॉल टेंपरिंग को एक नये आयाम तक ले गए. गेंदबाज रिवर्स स्विंग पाने के लिए पुरानी गेंद की सीम को उभारने के लिए नाखून या कोलड्रिंक के ढक्कन का इस्तेमाल करते थे. मौका मिलने पर वे दातों का उपयोग करने से भी नहीं चूकते थे. मिसाल के तौर पर पाकिस्तान के पूर्व कप्तान इमरान खान ने एक लेख में माना था कि उन्होंने एक मैच में गेंद को स्विंग करने में अतरिक्त मदद पाने के लिए कोल्डड्रिंक्स की बोतल के ढक्कन से गेंद को स्क्रैच किया था. ऐसी अनैतिकता इस तथाकथित भद्र पुरुषों के खेल में समय-समय पर उजागर होती रही है. तकनीकी बाध्यता की वजह से अधिकांश मौकों पर गेंद से छेड़छाड़ करने वाला खिलाड़ी पकड़ा नहीं जाता था, लेकिन नई तकनीक के आ जाने से गेंद के साथ छेड़छाड़ करने वाले पकड़े जाने लगे और इस छेड़छाड़ को आईसीसी ने अपराध घोषित किया और खिलाड़ियों को इस आरोप में मैच से बाहर भी बैठना पड़ा.

क्रिकेट में चीटिंग एक वायरस की तरह घर कर गई है, जिसने पहले तो गेंदबाजों को अपने आगोश में लिया. जब वहां लंबे समय तक बात नहीं बनी, तो उसने अपना दूसरा शिकार बल्लेबाजों को बनाया. बल्लेबाज बल्ले में टेंपरिंग करने लगे. आईसीसी के नियमों के अनुसार, सामान्य तौर पर बल्ले का आकार और प्रकार निश्चित है. उसके अलावा बल्लेबाज अन्य किसी पदार्थ का इस्तेमाल नहीं कर सकते, जिससे कि बल्लेबाज को फायदा मिले या बल्ले से गेंद पर ज्यादा तेजी से प्रहार किया जा सके, लेकिन हाल ही में संपन्न हुई ऐशेज सीरीज के दौरान बल्ले में सिलिकॉन स्ट्रिप का उपयोग कर डीआरएस प्रणाली को धता बताने की कोशिश का वाकया सामने आया है. सीरीज के ओल्ड ट्रैफर्ड में हुए टेस्ट मैच के दौरान इंग्लैंड के पूर्व कप्तान केविन पीटरसन पर बल्ले में फाइबर ग्लास टेप (सिलिकॉन) का इस्तेमाल करने का आरोप लगा, जिसकी वजह से हॉट स्पॉट तकनीक भी उनके बल्ले पर गेंद के एज को जज नहीं कर पाई. दरअसल, यह मामला ओल्ड ट्रैफर्ड टेस्ट के बाद तब सुर्खियों में आया, जब हॉट स्पॉट को बनाने वाले वॉरेन ब्रेनन ने इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन को किए गए एक ट्वीट में लिखा कि वह चिंतित हैं, क्योंकि उनके हिसाब से कुछ

खिलाड़ी फाइबर ग्लास टेप (सिलिकॉन) को अपने बल्लों के किनारों पर लगा रहे हैं, ताकि वह हॉट स्पॉट से बच सकें. हॉट स्पॉट एक ऐसी तकनीक है, जो थर्मल इमेजिंग के जरिये गेंद और बल्ले के बीच की टक्कर को दिखाती है, लेकिन इस प्रकार के किसी टेप के लगाने से इस तकनीक से बचा जाना भी मुमकिन है. ब्रेनन ने ही यह भी लिखा कि यह मुद्दा केविन पीटरसन के ओल्ड ट्रैफर्ड में गिरे विकेट के बाद नजर आ रहा है, जहां पर बल्ले और गेंद की टक्कर पर आवाज तो आई थी, लेकिन हॉट स्पॉट में फिर भी कुछ नजर नहीं आया. पीटरसन पर लगे आरोप का बचाव करते हुए कप्तान एलिस्टर कुक ने कहा कि खिलाड़ी वर्षों से अपने बल्लों पर टेप का इस्तेमाल करते आए हैं. मुझे लगता है कि यह सवाल उठाना ही बकवास है कि लोग अपने बल्लों पर टेप क्यों लगा रहे हैं. बल्लों पर फाइबर ग्लास टेप लगाना वर्षों से चल रहा है. यह सिर्फ बल्ले को लंबे समय तक बचाने के लिए किया जाता है. इसी दौरान ऑस्ट्रेलियाई खेल चैनल-चैनल नाइन ने रिपोर्ट दी कि हॉट स्पॉट तकनीक के ऑस्ट्रेलियाई जनक वॉरेन ब्रेनन ने आईसीसी से प्रणाली की खामियों के बारे में गंभीर चिंताएं व्यक्त की थीं और इसके लिए परीक्षण भी किए थे, जिसमें यह साबित हुआ था कि टेप की दूसरी परत चढ़ाने से गेंद का बल्ले से हुए संपर्क पता करना मुश्किल हो गया था. इसके बाद आईसीसी ने भी ब्रेनन द्वारा इस संबंध में चिंता व्यक्त करने की पुष्टी की थी, लेकिन शिकायत के दौरान आईसीसी नें उल्टे ब्रेनन को ही शांत रहने की नसीहत दे डाली थी.

दो साल पहले भारत के इंग्लैंड दौरे के दौरान भारतीय बल्लेबाज वीवीएस लक्ष्मण पर डीआरएस में हॉट स्पॉट तकनीक से छेड़छाड़ करने के लिए बल्ले पर वैसलिन लगाने का आरोप लगा था. लक्ष्मण को तीसरे अंपायर ने रिव्यू के बाद नाबाद करार दिया था. इसके बाद इंग्लैंड के पूर्व कप्तान मॉइकल ने ट्वीट किया था कि क्या बल्ले पर लगी वेसलीन लक्ष्मण को बचा लिया. केविन पीटरसन और लक्ष्मण के बीच इसे लेकर थोड़ी कहासुनी भी हो गई और बाद में तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्राड ने पत्रकारों से कहा कि उनकी टीम को पूरा भरोसा था कि गेंद बल्ले से लगी थी. ब्राड ने कहा कि खिलाड़ियों को लगता है कि हॉट स्पॉट में कभी-कभी हल्का सा टकराव नहीं दिखता. यह इसका एक नुकसान भी है, लेकिन विवाद तब शुरू हुआ, जब वान ने ट्वीट कर लक्ष्मण पर यह आरोप लगाया, क्योंकि बल्ले पर वैसलीन और इस तरह का कोई तरल पदार्थ हॉट स्पॉट तकनीक से नहीं दिखता. इस दौरान ब्रॉड ने तो हद कर दी थी. उन्होंने लक्ष्मण का बल्ला भी चेक किया कि उस पर किसी तरह की वैसलीन या तरल पदार्थ तो नहीं लगाया हुआ. उन्होंने कहा कि मुझे लगा था कि गेंद उनके बल्ले से लगी थी, लेकिन बल्ले पर कोई वैसलीन या तरल पदार्थ नहीं था.

इसके अलावा कई बल्लेबाज भी बल्ले के साथ छेड़छाड़ करते रहे हैं. एक बार श्रीलंका के विस्फोटक बल्लेबाज सनथ जयसूर्या के बल्ले से स्टील की रॉड निकली थी. इसी तरह ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पॉटिंग द्वारा बल्ले में ग्रेफाइट स्ट्रिप का उपयोग करने की बात सामने आई थी. उन पर आरोप था कि ऐसा करने पर उनके द्वारा बल्ले पर किए गए प्रहार और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं. ग्रेफाइट स्ट्रिप के इस्तेमाल से बल्लेबाज को अतिरिक्त फायदा मिलता देख आईसीसी ने ऐसे बल्ले के इस्तेमाल को क्रिकेट के नियमों का उल्लंघन बताया और पॉन्टिंग को ऐसा न करने की चेतावनी दी. ये सभी बल्ले नियम विरुद्ध बनाए गए थे, इसलिए बाद में इन पर प्रतिबंध लग गया था. इसके बाद पॉन्टिंग के लिए बल्ला बनाने वाली कंपनी कुकाबुरा ने ग्रेफाइट स्ट्रिप वाले सारे बल्ले बाजार से वापस मंगवा लिए थे. मैथ्यू हेडन ने इंग्लिश कंपनी ग्रे निकोल्स का बल्ला उपयोग किया था. यह बल्ला भी नियम विरुद्ध बनाया गया था. दरअसल, कुकाबुरा ने बैट पर ग्रेफाइट की परत लगाई गई थी और ग्रे निकोल्स कंपनी ने बैट का हैंडल हल्का बनाने के लिए ग्रेफाइट टाइटेनियम का प्रयोग किया तथा जो वजन बचा, उससे ब्लेड को मजबूत कर दिया गया. इससे बैट का भार बढ़े बिना बल्लेबाज को ज्यादा वजन वाले ब्लेड से खेलने का मौका मिल गया था. वैसे नये नियम के अनुसार, बैट के हैंडल का एक प्रतिशत हिस्सा केन, वुड और ट्वाइन का बना होना चाहिए. कंपन रोकने के लिए एक फीसद हिस्सा रबर जैसे दीगर सामान का हो सकता है. साथ ही हत्थे (हैंडिल) की लंबाई बैट की लंबाई से 62 प्रतशित से ज्यादा नहीं होनी चाहिए.

एक कहावत है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है. जिस गति से क्रिकेट में तकनीक का उपयोग बढ़ा, उससे खेल में तेजी और पारदर्शिता आई, लेकिन उसी गति से तकनीक का तोड़ भी खिलाड़ी ढूंढने में लगे रहे और तकनीक को मात देने की कोशिश का इज़ाफा करते हुए आईसीसी ने डीआरएस (डिसीजन रिव्यू सिस्टम) की शुरुआत की, लेकिन बीसीसीआई इसकी मुख़ालफत शुरुआत से ही करता रहा है. बीसीसीआई का तर्क रहा कि तकनीक की भी अपनी सीमा है, डीआरएस त्रुटिहीन प्रणाली नहीं है, लेकिन जब तक इसकी कमियों को दूर नहीं कर लिया जाएगा, तब तक भारत इसका उपयोग नहीं करेगा. ■

navinchauhan@chauthiduniya.com

पी वी संधू ने इतिहास रचा

जो कारनामा अब तक भारत की बैडमिंटन सनसनी सायना नेहवाल नहीं कर सकीं, वह कारनामा 18 वर्षीय पी वी संधू ने कर दिखाया है. पी वी संधू ने चीन के ग्वांगझू में हुई विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया है. वह ऐसा करने वाली पहली भारतीय महिला हैं. संधू पहली बार विश्व चैंपियनशिप में भाग लिया था. उन्होंने क्वाटर फाइनल में विश्व की सातवें नंबर की चीन की शिजियान वांग को लगातार गेमों में 21-18, 21-15 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया था. सेमीफाइनल में थाइलैंड की रैनेचॉक इंटेनॉन ने संधू को सीधे सेटों में 10-21,13-21 से हराया. हार के बावजूद संधू ने अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में दर्ज करा लिया है. सिंधु विश्व चैंपियनशिप में सिंगल्स वर्ग में 1983 के बाद कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी हैं. उनसे पहले यह कारनामा प्रकाश पादुकोण ने किया था. ■

- चौथी दुनिया ब्यूरो

www.chauthiduniya.com
चौथी दुनिया
जगमग दुनिया
Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2012-13-14, RNI No. DELHIN/2009/30467
26 अगस्त–01 सितंबर 2013

बचपन में खेल–खिलौनों से लेकर हमारे देश–दुनिया घूमने के सपनों में ट्रेनें बेतहाशा दौड़ती हैं. फिल्मी कल्पनालोक में हम ट्रेनों के रोमांचक दृश्यों से अपने आपको जोड़ पाते हैं. ट्रेनें फिल्म की भव्यता और उसके जादुई प्रभाव को बढ़ाकर दर्शकों को बांधने में भी काफी मदद करती हैं.

पटरी पर सवार बॉलीवुड एक्सप्रेस

फिल्मों में ट्रेन के बढ़ते इस्तेमाल और शूटिंग की अनुमति न मिलने की लगातार शिकायतों के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय अब फिल्मकारों का काम आसान करने जा रहा है. मंत्रालय की पहल पर रेलवे की ओर से एक या दो ऐसे स्टेशनों की व्यवस्था होगी, जिन पर सिर्फ शूटिंग होगी.

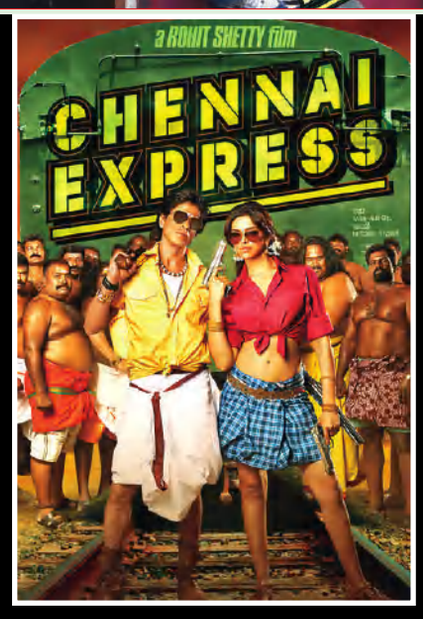

कृष्णकांत

भारतीय सिनेमा, खासकर हिंदी फिल्मों में कई ऐसी चीजें हैं, जो बार-बार दोहराई जाती हैं, लेकिन भारतीय दर्शक उनसे ऊबता नहीं, बल्कि और ज्यादा गर्मजोशी से उन दोहरावों का स्वागत करता है. ट्रेन भी भारतीय फिल्मों में बार-बार दिखाई जाती रही हैं. बॉलीवुड में ट्रेनों की एंट्री आजादी के पहले से ही हो गई थी और तब से यह सिलसिला चला आ रहा है. ट्रेन और सिनेमा का संबंध सिनेमा के इतिहास से थोड़ा ही कम पुराना है. 1936 में रिलीज फिल्म अछूत कन्या में रेलवे ट्रैक के इर्द-गिर्द कहानी बुनी गई थी. हाल ही में रिलीज शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण अभिनीत रोहित शेट्टी की नई फिल्म का तो नाम ही चेन्नई एक्सप्रेस रखा गया. फिल्म में राहुल यानी शाहरुख अपने दादाजी की अस्थियां विसर्जित करने के लिए ट्रेन से रामेश्वरम के लिए निकलता है. हालांकि, उसकी योजना है कि वह ट्रेन से उतर कर गोवा जाएगा और वहां दोस्तों के साथ मौज-मस्ती करेगा. इत्तेफाकन उसे ट्रेन में मीना लोची यानी दीपिका पादुकोण मिल जाती है और वह ट्रेन से उतर नहीं पाता. वह मुंबई पहुंच जाता है और इस तरह कहानी आगे बढ़ती है. इस रेल कथा को दर्शकों ने खूब पसंद किया. फिल्म ने लोकप्रियता के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त करते हुए तीन दिन में सौ करोड़ से अधिक कमाई की.

भारतीय फिल्मों में ट्रेनों की आवाजाही अब और आसान होने वाली है. दरअसल, फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस सहित तमाम फिल्मों में ट्रेन के बढ़ते दृश्यों को देखते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय फिल्मकारों को स्टेशनों पर शूटिंग की अनुमति प्रक्रिया को और आसान बनाने पर विचार कर रहा है. अभी ट्रेनों में या रेलवे स्टेशन पर फिल्मों की शूटिंग करने के लिए रेल अधिकारियों से इजाजत पा लेना किला फतह करने से जरा भी कम मुश्किल नहीं है. फिल्मकारों को रेलवे से शूटिंग की अनुमति लेने के लिए बार-बार, कभी-कभी महीनों तक अधिकारियों के चक्कर लगाने पड़ते हैं. फिल्मकारों की ओर से सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के पास बार-बार शिकायतें आ रही थीं. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने इस मामले पर रेल मंत्रालय से हल निकालने को कहा, तो रेल मंत्रालय ने इस बाबत सैद्धांतिक तौर पर एक प्रस्ताव पास कर दिया, जिसके तहत एक ऐसा रेलवे स्टेशन व्यवस्थित किया जाएगा, जहां पर सिर्फ शूटिंग होगी. ऐसे स्टेशनों पर आम ट्रेनें नहीं रुकेंगी, जिससे यहां शूटिंग करना आसान होगा. मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि इस प्रस्ताव पर अभी काम हो रहा है और जल्द ही एक या दो स्टेशनों की घोषणा कर दी जाएगी.

इसके अलावा, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय इस बात पर भी विचार कर रहा है कि फिल्मकारों को शूटिंग के लिए अलग-अलग विभागों में अनुमति के लिए चक्कर लगाने की जगह एक सिंगल विंडो क्लीयरेंस की व्यवस्था की जाए. इससे एक ही खिड़की से फिल्मकारों को शूटिंग के लिए परिवहन, पुलिस, प्रशासन, पुरातत्व आदि सभी विभागों की अनुमति मिल सकेगी. हाल ही में मंत्रालय की ओर से संबंधित विभागों के साथ एक बैठक की जा चुकी है. यदि यह प्रस्ताव लागू कर दिया जाता है, तो फिल्मकारों को एक ही जगह से सब विभागों की अनुमति मिल जाएगी.

दरअसल, ट्रेन ऐसी चीज है, जो बचपन से ही हमें बहुत लुभाती है. बचपन में खेल-खिलौनों से लेकर हमारे देश-दुनिया घूमने के सपनों में ट्रेनें बेतहाशा दौड़ती हैं. फिल्मी कल्पनालोक में हम ट्रेनों के रोमांचक दृश्यों से अपने आपको जोड़ पाते हैं. ट्रेनें फिल्मों की भव्यता और उसके जादुई प्रभाव को बढ़ा कर दर्शकों को बांधने में भी काफी मदद करती हैं. शायद यही वजह है कि फिल्मकार ट्रेनों के इस्तेमाल से यादगार दृश्य रचने को प्रेरित होते हैं.

चेन्नई एक्सप्रेस सहित शाहरुख खान की एक दर्जन फिल्में ऐसी हैं, जिनमें ट्रेनों पर यादगार सीन फिल्माए गए और दर्शकों ने उन्हें खूब पसंद किया. इनमें से ज्यादातर फिल्में हिट रहीं. रिकॉर्ड तोड़ने वाली फिल्म दिलवाले दुल्हनियां ले जाएंगे, का क्लाइमेक्स ट्रेन में पूरा होता है, जब नायक-नायिका एक दूसरे से मिलते हैं. फिल्म दिल से के गाने छैंया-छैंया में तो शाहरुख और मलाइका ने ट्रेन की छत पर डांस करके दर्शकों को हतप्रभ कर दिया था. इसके अलावा उनकी फिल्में रॉ वन, कुछ कुछ होता है, वीर जारा, देवदास, मैं हूं ना, स्वदेश और कल हो न हो में ट्रेन के जबरदस्त सीन हैं. शोले के जय-वीरू का ट्रेन स्टंट तो आपको याद दिलाने की जरूरत नहीं. सन ऑफ सरदार में सोनाक्षी सिन्हा और अक्षय कुमार मजेदार अंदाज में ट्रेन में ही मिलते हैं. 70 के दशक में फिल्मों में ट्रेनों का खूब इस्तेमाल किया गया. 1980 में तो द बर्निंग ट्रेन नाम से फिल्म ही बन गई थी, जिसकी पूरी कहानी ही ट्रेन पर आधारित थी. 1955 में सुनील दत्त की फिल्म आई थी रेलवे प्लेटफार्म. यश चोपड़ा अपनी फिल्मों में प्राय: ट्रेन वाले रखते थे. सलमान खान की दबंग, तेरे नाम और वांटेड में भी रेलवे प्लेटफॉर्म और ट्रेन के दृश्य दिखे. हाल ही में वन्स अपॉन ए टाइम इन मुंबई दोबारा, गुंडे, डेढ़ इश्किया फिल्मों की शूटिंग हुई, जो कि रिलीज होने वाली हैं. ट्रेन के दृश्यों वाली फिल्मों की फेहरिश्त काफी लंबी है. रेलवे द्वारा प्रस्तावित शूटिंग की अनुमति प्रक्रिया आसान करने के बाद आपको फिल्मों में और भी मजेदार दृश्य, कहानियां, स्टंट और रोमांस देखने को मिल सकते हैं. ■

feedback@chauthiduniya.com

मासूम का रीमेक बनने से खफा हैं नसीर

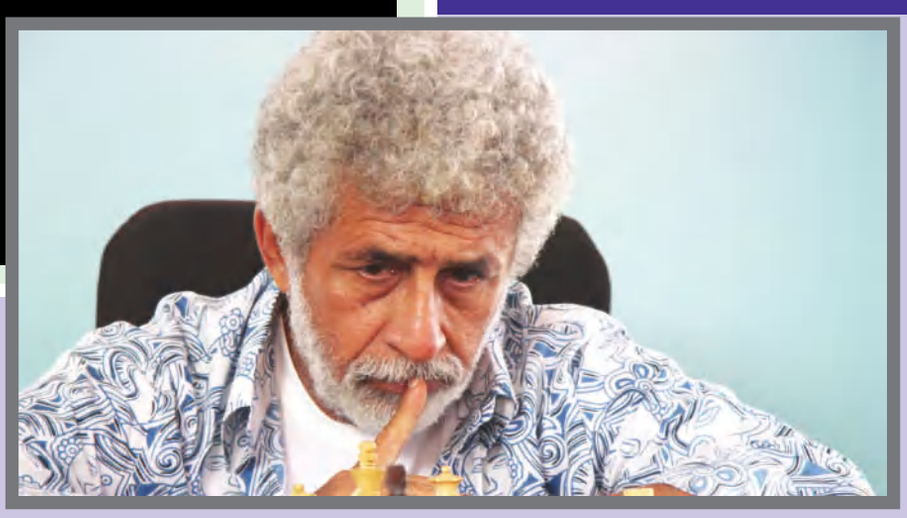

मचाएंगे धमाल आलिया और वरुण

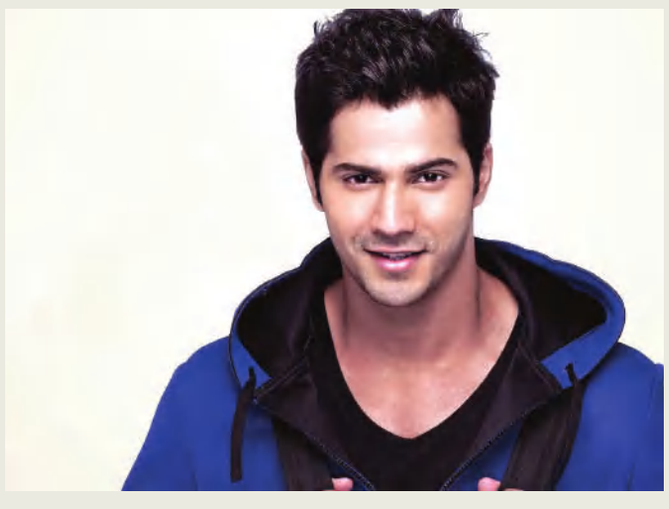

फिल्म स्टूडेंट आंफ द ईयर से बालीवुड में कदम रखने वाले वरुण धवन और आलिया भट्ट की जोड़ी शायद करन जौहर को ज्यादा पसंद आ गई है. इस जोड़ी को लेकर वह एक रोमांचक फिल्म हंप्टी शर्मा की दुल्हनिया बना रहे हैं. शशांक खेतान इस फिल्म से निर्देशक के तौर पर अपनी पारी की शुरुआत कर रहें हैं. स्टूडेंट ऑफ द ईयर में वरुण और आलिया की केमिस्ट्री को ज्यादा पसन्द किया गया था. इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर भी खूब कलेक्शन किया था. दोनों के नये होने कारण भी उनके पास काम की कमी नहीं है. अभी वरुण डेविड धवन की फिल्म मैं तेरा हीरो की शूटिंग में वयस्त है. वरुण और आलिया अक्टूबर तक खाली हो सकते हैं और हंप्टी शर्मा की फिल्म दुल्हनिया की शूटिंग इसके बाद ही शूरू हो सकेगी. इस बात की पुष्टि करन जौहर ने खुद की है कि वह वरुण और आलिया की जोड़ी को लेकर फिल्म बना रहे हैं. करन ने कहा है कि शशांक फिल्म दुल्हनिया को डायरेक्ट करेंगे और यह उनकी पहली फिल्म होगी. इस फिल्म की कहानी भी शशांक ने ही लिखी है. यह एक लव स्टोरी फिल्म होगी. इस फिल्म के जून, 2014 में रिलीज होने की संभावना है. आलिया भट्ट की करन के साथ यह तीसरी फिल्म होगी. वैसे तो उन्हें अनुराग बसु और रणबीर कपूर के प्रोडक्शन हाउस में शुरू से ही रणबीर के अपोजिट रोल का ऑफर मिला है. अब यह देखना होगा कि क्या आलिया और वरुण की जोड़ी बाकी आने वाली फिल्मों भी स्टूडेंट ऑफ द ईयर की तरह धमाल मचा पाती है . ■

इन दिनों रीमेक फिल्में बनाने का चलन जोरों पर है, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि कालजयी फिल्मों का रीमेक बनाना उचित नहीं है. जाने-माने अभिनेता नसीरुद्दीन शाह भी रीमेक फिल्मों के चलन से खासा नाराज दिखते हैं. वह कहते हैं कि रीमेक फिल्में बनाना उनकी समझ से परे है और वह 1983 में आई अपनी फिल्म मासूम के रीमेक के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं हैं.

नसीरुद्दीन कहते हैं कि पहली बात तो यह कि फिल्मों का रीमेक बनना ही नहीं चाहिए. यह धोखा है. बॉलीवुड रीमेक फिल्मों के माध्यम से अपने मानसिक आलस्य और उदासीनता को छिपाना चाहता है. पहले यह अलग तरीके से किया जाता था, लेकिन जब तक आपके पास फिल्म के लिए कोई दूसरा दृष्टिकोण न हो, रीमेक नहीं बनाना चाहिए. निर्देशक शेखर कपूर की फिल्म मासूम की कहानी एक ऐसे परिवार की कहानी है, जो पति की नाजायज संतान की खबर से बिखर जाता है. नसीरुद्दीन ने फिल्म में पति की भूमिका निभाई थी, जबकि अभिनेत्री शबाना आजमी पत्नी की भूमिका में थीं. नसीरुद्दीन के लगभग 40 साल के फिल्मी करियर में मासूम उनकी पसंदीदा फिल्मों में से है. खबर है कि अभिनेता-गायक और निर्माता हिमेश रेशमिया ने हाल ही में फिल्म का रीमेक बनाने के लिए अधिकार खरीदे हैं. नसीरुद्दीन का कहना है कि फिल्म की कहानी वर्तमान समय के हिसाब से बिल्कुल भी प्रासंगिक नहीं है. उनका मानना है कि मासूम किसी भी तरह पहले से ज्यादा बेहतर नहीं बनाई जा सकती. वह यह भी कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि किसी को भी मासूम का रीमेक बनाने की कोशिश करनी चाहिए. आज ई-मेल और मोबाइल फोन के दौर में ऐसा कैसे हो सकता है कि 10 साल के किसी बच्चे के पिता को उसके होने की खबर ही न हो. हाल के वर्षों में बॉलीवुड में पिछले दौर की कई फिल्मों की रीमेक फिल्में आई हैं, जिनमें अग्निपथ, हिम्मतवाला, चश्मे बद्दूर, डॉन, उमराव जान और कर्ज हैं. इनमें से अधिकतर को बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं मिला. वहीं हीरो, जंजीर और बातों-बातों में वगैरह कुछ फिल्में बन रही हैं. ■

चौथी दुनिया

26 अगस्त-01 सितंबर 2013

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

बिहार - झारखंड

बेगूसराय

जनता त्रस्त सरकार मस्त

बिहार में विकास के दावे करने वाले नीतीश के शासन में उद्योग धंधे ख़त्म होने के क़गार पर हैं. सरकार का ध्यान राज्य के विकास पर कम और राजनीति करने में ज़्यादा है. सरकार की उदासीनता के कारण बेगूसराय में फर्टिलाइजर उद्योग बंद हो गया, जिससे यहां हज़ारों लोगों की रोजी-रोटी बंद हो गई है.

विजय कुमार

बिहार के विकास की चर्चा जोर-शोर से प्रचारित-प्रसारित की जाती रही है. जनता बिहार, बढ़ता बिहार का स्लोगन भी ख़ुब यहां सुनाया जाता है, लेकिन विकास के शोर के बीच में विपक्ष हमेशा कहता रहा है कि एक सुई का कारखाना तो पिछले सात साल में लगा नहीं, फिर किस विकास की बात की जा रही है. ख़ुद मुख्यमंत्री भी यात्राओं के ज़रिये सूबे की जनता को विकास और सुशासन के बारे में बताते रहते हैं. कैबिनेट की एक बैठक भी बेगूसराय के एक गांव में की गई. ढेर सारे वादे भी किए गए. लोगों में उम्मीद जगी थी कि यहां भी विकास की हवा बहेगी, फर्टिलाइजर का कायाकल्प होगा, रोजगार के अवसर मिलेंगे. वैसे एक बार तत्कालीन केंद्रीय उर्वरक मंत्री रहे रामविलास पासवान के साथ नीतीश और लालू दोनों बेगूसराय के बंद पड़े फर्टिलाइजर कारखाना पहुंचे थे. सभी ने वादा किया था कि उसे चालू करवाने के लिए दलीय राजनीति से उठकर काम किया जाएगा, लेकिन दुखद यह है कि अबतक किसी ने अपने किए वादे पर सोचने तक की जहमत नहीं उठाई है.

बरौनी फर्टिलाइजर कारखाना पिछले 11 साल से बंद पड़ा है. फिलहाल बंद पड़े बरौनी खाद्य कारखाना की ज़मीन पर

असामाजिक तत्वों का क़ब्ज़ा है. कारखााने से क़ीमती कल-पूर्जे की भी लगातार चोरी हो रही है. गत 10 मई को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति सीसीईए की बैठक में भारतीय खाद्य निगम लिमिटेड एफसीआईएल की पांच बीमार इकाइयों को चालू करने का निर्णय लिया गया, जिसमें गोरखपुर, सिंदरी, तालचर, रामागुंडम और कोरबा खाद्य कारखाना शामिल है. केंद्र सरकार के इस भेदभावपूर्ण निर्णय के ख़िलाफ़ सूबे के किसी दल ने कुछ भी नहीं कहा. मंत्रिमंडल के इस निर्णय की निंदा करते हुए पूर्व सांसद शत्रुध्न प्रसाद सिंह कहते हैं कि फर्टिलाइजर कारखाना बंद होने के लिए एनडीए की सरकार ज़िम्मेदार है. जिस समय यह निर्णय लिया गया था, नीतीश और रामविलास दोनों केंद्र में मंत्री थे. साथ ही सिंह यह भी कहते हैं कि जबतक भारत सरकार यहां गैस पाइप लाइन नहीं लाएगी, कारखाना चालू करना मुश्किल है. बताते चलें कि नबंवर, 1976 में जब उस कारखाने में उत्पादन शुरू हुआ था, तब उसमें कामगारों की संख्या 1345 थी और उसकी उत्पादन क्षमता एक हजार टन प्रतिदिन थी. बाद के दिनों में उस कारखाने में कामगारों की संख्या बढ़कर 2800 तक पहुंच गई.

- शेष पृष्ठ संख्या 18 पर

ऑपरेशन यादव पटाओ शुरू

प्रेम कुमार

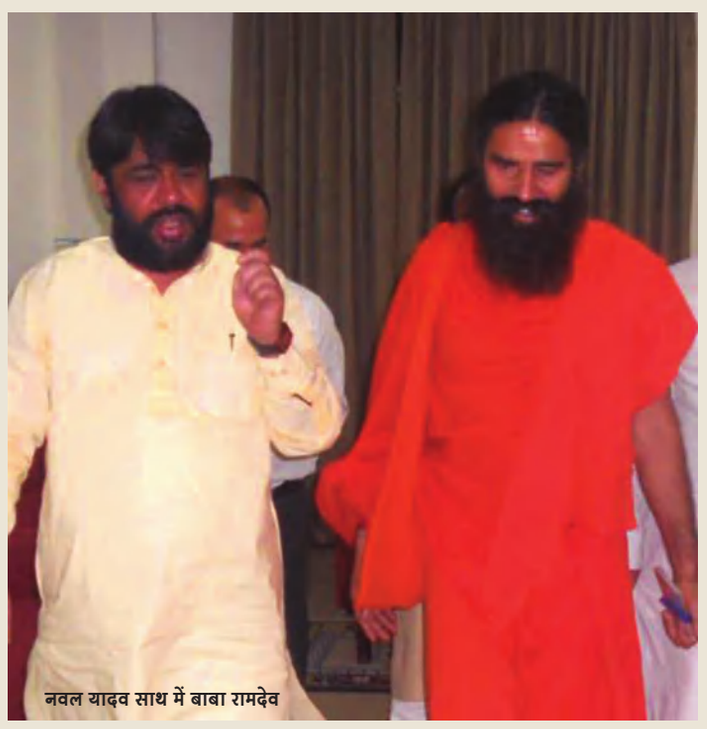

नवल यादव साथ में बाबा रामदेव

नंद किशोर यादव

नरेंद्र मोदी के मुरीद नवल यादव कहते हैं कि लालू प्रसाद के साथ वही यादव नेता रह सकते हैं, जिन्हें चारण संस्कृति पर भरोसा है, जो लालू प्रसाद का पीकदान उठा सकते हैं या उनकी हर बात में हां में हां मिला सकते हैं. एक पार्टी में दो नियम नहीं चल सकता है. लालू प्रसाद ने जब कहा कि देश में नरेंद्र मोदी की हवा चल रही है तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और जब मैंने कहा कि मोदी लोकप्रिय नेता हैं तो, मुझे पार्टी से निलंबित कर दिया गया.

सरोज सिंह

बिहार की राजनीति में इन दिनों कई तरह के राजनीतिक प्रयोग शुरू हो गए हैं. इनमें एक प्रयोग यादव वोटरों को लेकर भी किया जा रहा है. हल्के व अनमने ढंग से यह प्रयोग हर चुनाव से पहले इस सूबे में होता रहा है, लेकिन इस बार ज़्यादा संभावनाओं के मद्देनज़र इसमें गंभीरता आ गई है. चारा घोटाले में लालू प्रसाद की अर्जी सुप्रीम कोर्ट में खारिज हो जाने के बाद भाजपा व जदयू समेत कई पार्टियों को ऐसा लगने लगा है कि बिहार की चुनावी राजनीति को बड़े स्तर पर प्रभावित करने वाले यादव वोटर अब इधर-इधर हो सकते हैं. अभी चारा घोटाले में फ़ैसला आना बाक़ी है, लेकिन इन पार्टियों का अनुमान है कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले से लालू प्रसाद को गहरा झटका लगा है और इसका अहसास राजद के वोटरों को भी हो गया है. उन्हें लगा कि लालू प्रसाद को राजनीतिक तौर पर कमजोर करने और यादव वोटरों में सेंध लगाने का यही माकूल मौक़ा है. भाजपा व जदयू का आकलन यह है कि अगर यादव वोटों में सेंधमारी हो गई तो एक नया चुनावी सामाजिक तानाबाना तैयार होगा, जो मौजूदा सभी समीकरणों पर भारी पड़ेगा. मौटे तौर पर माना जाता है कि 14 फ़ीसदी यादव वोटर, बिहार की चालीस लोकसभा सीटों में से लगभग 20 सीटों को निर्णायक तौर पर प्रभावित करते हैं. लालू प्रसाद के उत्थान के साथ ये वोटर आज की तारीख तक ज़्यादा संख्या में उनके साथ जुड़े हुए हैं. चुनाव दर चुनाव यह बात साबित भी होती रही है, लेकिन उनके विरोधियों को सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले ने बहुत उत्साहित कर दिया है. भाजपा को लगता है कि अगर सही तरीक़े से गोटी फिट की जाए तो, यादव वोटरों का बड़ा हिस्सा पार्टी अपने पाले में कर सकती है. इसलिए बिना समय गंवाए भाजपा ने अपना ऑपरेशन यादव पटाओ शुरू कर दिया है. इस मिशन में भाजपा नरेंद्र मोदी का अपना सबसे बड़ा हथियार बना रही है. नरेंद्र मोदी अपने भाषणों में जिन मुद्दों को उठा रहे हैं, इनसे आम यादवों को कोई परेशानी नहीं है. नरेंद्र मोदी जैसे जैसे आक्रमक होते जा रहे हैं, यादव बिरादरी में उनकी पैठ बढ़ती जा रही है. विधान पार्षद व तेजतर्रार राजद नेता नवल यादव ने नरेंद्र मोदी का ऐसा गुणगान किया कि उन्हें पार्टी से छह साल के लिए निलंबित कर दिया गया. नवल यादव की अपनी बिरादरी में काफ़ी गहरी पैठ है और बिहार में वह बाबा रामदेव के राजनीतिक सारथी भी माने जाते हैं. बाबा रामदेव ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प ले रखा है. ऐसे में नवल यादव द्वारा नरेंद्र मोदी के गुणगान करने का रहस्य आसानी से समझा जा सकता है. चर्चा है कि नवल यादव भाजपा के टिकट पर पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र से चुनावी अखाड़े में उतर सकते हैं. इसके अलावा, भाजपा की नज़र राजद व जदयू के दूसरे मजबूत राजद नेताओं पर भी है. बाबा रामदेव के इशारे पर नवल यादव इस ऑपरेशन में जोर शोर से लगे हैं. बताया जा रहा है कि नंद किशोर यादव को नेता विपक्ष बनाकर भाजपा ने यह संदेश देने की कोशिश की कि अब यादवों को भाजपा से परहेज नहीं करना चाहिए और पूरे मान-सम्मान के साथ भाजपा उनका ख्याल रखेगी. नंदकिशोर यादव के नेता विपक्ष बनने से यह संदेश गया कि भाजपा केवल अगड़ी जाति व बनियों की पार्टी नहीं है. यह ऐसी पार्टी है, जिसने देश की सर्वोच्च सत्ता के लिए एक अति पिछड़े नेता नरेंद्र मोदी को आगे किया है और नंदकिशोर यादव को नेता प्रतिपक्ष बनाया है. लालू प्रसाद के कमजोर होने से भाजपा को एक मौक़ा दिख रहा है, इसलिए अब भाजपा के अंदर बैठे यादवों के बड़े नेताओं को भी इस ऑपरेशन में शामिल किया जा रहा है. उनका टास्क साफ है, बिरादरी को यह समझा देना कि भाजपा से जुड़ने में उन्हें कोई हर्ज नहीं है और इस पार्टी में किसी पार्टी की तुलना में कहीं ज़्यादा सम्मान के साथ सत्ता में हिस्सेदारी मिलनी तय है. बताया जा रहा है कि भाजपा के नंदकिशोर यादव, हुकुमदेव यादव, नित्यानंद राय, फाल्गुनी यादव व आनंदी यादव अपने अपने स्तर से इस काम में लगे हैं. इस ऑपरेशन को और तेज करने के लिए बाबा रामदेव जल्द ही बिहार आने का कार्यक्रम बना रहे हैं. नरेंद्र मोदी के मुरीद नवल यादव कहते हैं कि लालू प्रसाद के साथ वही यादव नेता रह सकते हैं, जिन्हें चारण संस्कृति पर भरोसा है, जो लालू प्रसाद का पीकदान उठा सकते हैं या उनकी हर बात में हां में हां मिला सकते हैं. एक पार्टी में दो नियम नहीं चल सकता है. लालू प्रसाद ने जब कहा कि देश में नरेंद्र मोदी की हवा चल रही है तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और जब मैंने कहा कि मोदी लोकप्रिय नेता हैं तो मुझे पार्टी से निलंबित कर दिया गया. लालू प्रसाद के लिए अलग नियम और मेरे लिए अलग नियम कैसे चलेगा. उन्होंने दावा किया कि बिहार की राजनीति में जल्द ही सुनामी आने वाली है. यादवों को नीतीश कुमार ने सत्ता से बेदख़ल कर उनकी सत्ता को छीना है, इसलिए हमारा पहला लक्ष्य पहले इस सरकार को बेदख़ल करना है. यादव समाज एक नये विकल्प की तलाश में है और यह विकल्प जल्द ही मिलने वाला है.

जदयू को भी लग रहा है कि लालू के वोटर उनकी गैरमौजूदगी में भाजपा के बजाय जदयू से जुड़ना ज़्यादा पसंद करेंगे, लेकिन राजद नेता प्रेम कुमार मणि इन बातों से सहमत नहीं हैं. मणि कहते हैं कि पहले तो इस मामले में अभी फ़ैसला आना बाक़ी है और अगर संभावनाओं के आधार पर भी बात की जाए तो यह कहा जा सकता है कि राजद को कोई फर्क नहीं पड़ेगा. राजद तो संकट से निकलकर बनने वाली पार्टी है.

- शेष पृष्ठ संख्या 18 पर

www.chauthiduniya.com
चौथी दुनिया

» एक नज़र «

परिसर में हुआ वृक्षारोपण

इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ हेल्थ एजुकेशन एंड रिसर्च पटना में एक्सिस बैंक के सौजन्य से वृक्षारोपण किया गया. कार्यक्रम का उद्घाटन संस्थान के निदेशक व बिहार प्रदेश कांग्रेस के बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष अनिल सुलभ ने अमरूद का पौधा लगाकर किया. मौक़े पर अनिल सुलभ ने कहा कि प्रदूषण की समस्या धीरे-धीरे गहरा रही है. यह विश्वव्यापी ख़तरा है और पेड़ लगाकर ही इससे बचा जा सकता है. कार्यक्रम में बैंक के बिहार-झारखंड के वरीय प्रबंधक [illegible] संस्थान के प्रबंध निदेशक आकाश सुलभ, डॉ. तापसी देब, प्रो. अनिल साह, बैंक के वरीय प्रबंधक हिमांशु अग्रवाल, अमित बाबुल, उत्कर्ष राज, सोनम प्रकाश, दिवाकर स्वरूप, सत्यप्रकाश, सुजीत सहित बड़ी संख्या में छात्र-छात्राओं ने भी भाग लिया. **– शिवानी पाण्डेय**

भवन का उद्घाटन

दस लाख की लागत से बने रामनारायण मेमोरियल महाविद्यालय के भवन का उद्घाटन राज्यसभा के सांसद धीरज साहू ने किया. यह भवन सांसद साहू के मद से बनवाया गया है. दौरे पर आए साहू ने प्रतापपुर प्रखंड का भी निरीक्षण किया और अरबी कालेज में आयोजित इफ्तार पार्टी में भी भाग लिया. उस दौरान जिला कांग्रेस के अध्यक्ष धर्मेन्द्र साहू, कमल कुमार केशरी, प्रदीप कुमार गुप्ता, इमदाद आजी, प्रो. जनेंद्र कुमार सिंह, अरविंद कुमार और बृजनंदन सिंह उपस्थित थे.

विश्व स्तनपान दिवस मना

विश्व स्तनपान दिवस के मौक़े पर बस्तर जिले के सभी आंगनवाड़ी केंद्रों पर स्तनपान दिवस मनाया गया. एक से सात अगस्त के बीच चले इस कार्यक्रम के तहत आंगनवाड़ी के सभी केंद्रों पर सेविकाओं द्वारा बच्चों को स्तनपान कराया गया. बाल विकास परियोजना पदाधिकारी मीना ठाकुर ने कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें पंचायत के प्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया. सेविका अंकिता कुमारी और प्रवेक्षिका चंद्रावती ने उपस्थित महिलाओं को स्तनपान के महत्व को बताया. साथ ही उन लोगों द्वारा गर्भवती महिलाओं की गोदभराई भी की गई. जिला प्रशासन ने भी आंगनवाड़ी के इस कार्यक्रम को सराहा.

– अमरेन्द्र प्रताप

बेगूसराय

भितरघात से कैसे निपटेगी भाजपा

सशक्त संगठन का दंभ भर रही भाजपा के लिए नमो के नाम पर आगामी लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज कराना आसान नहीं होगा ...

कुमार मनीष

आगामी लोकसभा चुनाव की वैतरणी पार करना भाजपा के लिए आसान नहीं होगा. इसकी दो वजहें मानी जा रही हैं. पहला तो यह कि अभी जदयू को अपनी राजनीतिक हैसियत का आकलन करना है. दूसरा यह कि बेगूसराय जिला भाजपा एनडीए कालखंड से ही बेगूसराय संसदीय सीट को झटक कर अपने खाते में लाना चाह रही है. ऐसे में उसे एक दमदार प्रत्याशी का चुनाव भी करना है, जो असरदार जीत दर्ज करा सके और इस स्थिति में जिला भाजपा की परेशानी यह है कि बेगूसराय में सांसद पद की उम्मीदवारी के लिए खुद योग्य बताने वाले नेताओं की कमी नहीं है.

स्थानीय और प्रभावशाली नेताओं के बावजूद भी सूबे की औद्योगिक राजधानी बेगूसराय का अपेक्षित विकास नहीं हो सका है. जिले की जनता इसे अपना दुर्भाग्य मानती है. [illegible]

[illegible]

... साथ-साथ अन्य मोर्चा व प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों व पुराने कार्यकर्ताओं से तालमेल बैठाने की.

दरअसल, एनडीए गठबंधन में भाजपा कार्यकर्ताओं की उपेक्षा से नाराज होकर [illegible] थी. सतही अवलोकन के दौरान ही वे अचानक नाराज हो गए और कार्यक्रम छोड़ चले गए. वापस लौटने पर उनके संबोधन ने राजनीतिक समझ रखने वाले लोगों को एक बड़ा संकेत दिया है. यह मंच सांसद की [illegible] के लिए टिकट के टकराव और आपसी खींचतान को झेलते हुए जनता के बीच नमो नारायण के जयघोषों के साथ चुनावी समर में उतरना एक बड़ी चुनौती है. अब देखना यह है कि भाजपा द्वारा शीर्ष नेतृत्व मिशन 2014 के लिए बेहतर उम्मीदवार के चयन को लेकर कौन सी रणनीति अपनाई जाती है. ■

feedback@chauthiduniya.com

भोला सिंह

रजनीश

रामलखन सिंह

संजय सिंह

संजय सिंह, जिलाध्यक्ष

उपेंद्र सिंह

आतंकियों का गढ़ बना सीमांचल

काठमांडू निवासी आईएसआई एजेंट इस्माइल की दो वर्ष पूर्व थिम्पू में हत्या के बाद उन गतिविधियों का संचालन डॉ. ब्रेन के नाम से चर्चित आईएसआई ऐजेंट कर रहा है. सिलीगुड़ी एवं न्यू जलपाईगुड़ी के जयगांव में हूजी का नेटवर्क काफी मजबूत हो चुका है.

निरंजन

बिहार के सीमांचल में आईएसआई एवं हूजी आतंकवादी संगठनों ने अपना पांव पसारना शुरू कर दिया है. आईएसआई सीमांचल के कई ठिकानों पर अपनी जड़ें जमा चुका है और यहीं से अपने आकाओं के संपर्क में रहकर आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दे रहा है. वक्त रहते अगर सरकार ने इनके खिलाफ कड़े कदम नहीं उठाए तो आने वाले समय में सीमांचल के कई जिलों में आतंकवादी अपना प्रशिक्षण केंद्र बना चुके होंगे. कुछ दिनों पहले ही प्रशिक्षण देने आए आतंकवादी सरगना के मुखिया मिर्जा खान उर्फ गुलाम रसूल खान को पूर्णिया से दबोचा गया था. वहीं कटिहार में गुलाम वसीर और किशनगंज के पौआखाली से रियाजुल सरकार की गिरफ्तारी हुई थी. पूर्णिया से कोसी प्रमंडल में अपने नेटवर्क को मजबूत करने के लिए आईएसआई के सहयोग से हूजी और इंडियन मुजाहिद्दीन मिलकर काम कर रहे हैं. न्यू जलपाईगुड़ी के धूपगूड़ी, तालचीनी, बांग्लादेश से सटा सीमा माथाभंगा, उफानगंज तथा भूटान सीमा का चामूला आतंकी संगठनों का संचालन केंद्र बनता जा रहा है. हूजी आतंकी (बांग्लादेश का) शेख रफीक 2010 के अक्टूबर माह में अपने नेटवर्क को मजबूत करने के लिए अररिया, किशनगंज तथा तीन वर्ष पूर्व कोसी त्रासदी के कारण डूबे इलाकों का दौरा कर चुका है. 2011 में शेख रफीक ने जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग एवं दुरवास (बंगाल) में पहुंच कर हूजी एवं इंडियन मुजाहिद्दीन जैसे संगठनों के साथ बैठक भी की थी. उन सारी बातों की जानकारी खुफिया विभाग को मिली. सीमांचल के जिलों के खुफिया विभाग के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, आतंकी गतिविधियों का संचालन भूटान की राजधानी थिम्पू से हो रहा है.

काठमांडू निवासी आईएसआई ऐजेंट इस्माइल की दो वर्ष पूर्व थिम्पू में हत्या के बाद उन गतिविधियों का संचालन डॉ. ब्रेन के नाम से चर्चित आईएसआई ऐजेंट कर रहा है. सिलीगुड़ी एवं एनजेपी के जयगांव में हूजी का नेटवर्क काफी मजबूत हो चुका है. खुफिया विभाग की मानें तो किशनगंज से इस्लामपुर तक चिकेननेट के रूप में जाना जाने वाला 32 किलोमीटर का इलाका आतंकियों का विश्रामगाह बन चुका है. चिकेननेट के समीप स्थित धर्मपुर, देवीगंज, पांजीपाड़ा, दालकोला, पानतापुर आदि क्षेत्र हथियार, पशु तस्करी, मादक पदार्थ एवं मानव व्यपार का प्रमुख केंद्र हैं. उस क्षेत्र में अफीम की खेती को बढ़ावा देकर आतंकी संगठन अपना आर्थिक संसाधन जुटाते हैं. लश्कर-ए-तैयबा ने अलग-अलग नामों से डेढ़ दर्जन संगठन सीमाचंल में बनाया है. खुफिया विभाग ऐसे संगठनों की तह तक पहुंचने में जुटा हुआ है. पूर्णिया प्रमंडल में ऐसे तीन संगठनों द्वारा काम करने की बात खुफिया विभाग के अधिकारी भी बताते हैं. सीमांचल के जिलों में लश्कर-ए-तैयबा के संगठन को मजबूत करने का काम नेपाल के छापा इलाके से हो रहा है. समय-समय पर लश्कर आतंकियों के पूर्णिया, पं. बंगाल के दिनाजपुर एवं मुर्शिदाबाद से आने की बात भी प्रमाणित हो चुकी है.

आतंकी गुलाम बशीर

आतंकी मीरजा खान

भारत-नेपाल सीमा का लाभ उठाकर आतंकी आसानी से सीमाचंल के रास्ते होते हुए देश के विभिन्न हिस्सों में पहुंचते हैं. भारत नेपाल एवं भारत बंग्लादेश सीमा पर एसएसबी की तैनाती के बाद घुसपैठ के मामलों में कमी जरूर आई है, लेकिन खुफिया जानकारी के आदान-प्रदान नहीं होने की वजह से घुसपैठ पर पूरी तरह से नियंत्रण नहीं हो पाया है. वहीं बांग्लादेश से लगती सीमा के कई स्थानों पर तारबंदी नहीं की गई है, जिसका उपयोग घुसपैठ के लिए आतंकी संगठन करते हैं. कश्मीर में सेना और सुरक्षाबलों के बढ़ती दबिश के बाद आतंकी संगठन नेपाल और बंग्लादेश से सटी सीमा से भारत में प्रवेश करते हैं. पुलिस के वरीय अधिकारियों का कहना है कि इस दिशा में स्थानीय पुलिस और एसएसबी संयुक्त ऑपरेशन चला रही है, लेकिन यह कवायद कहां तक सफल होगी, यह समय बताएगा. बहरहाल, इस समस्या से जल्द न निपटा गया तो आने वाले समय में सीमांचल की जनता और बिहार के साथ साथ पूरे देश को आतंकियों का दंश झेलना पड़ेगा. ■

feedback@chauthiduniya.com

जदयू को भरनी होगी दरार

राजेश कुमार

सुरक्षित जमुई लोकसभा सीट के साथ-साथ जिले की सभी विधानसभा सीटों पर परोक्ष रूप से जदयू का ही कब्जा है. लेकिन एनडीए से अलगाव के बाद अब यह भी सवाल उठने लगा है कि क्या उन सीटों पर जदयू का दबदबा बरकरार रह पाएगा या नहीं. बनते-बिगड़ते समीकरण को देखें तो ऐसा नहीं लगता है. जदयू के समर्पित कार्यकर्ताओं की अनदेखी और पार्टी के प्रति कार्यकर्ताओं की बेरुखी जिले में साफ दिखती है. दरअसल ऊपर-ऊपर सब कुछ सामान्य दिखने-दिखाने वाला जदयू दो खेमों में बंटा हुआ है.

सूबे के वर्तमान कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह और भवन निर्माण मंत्री दामोदर रावत की कर्मभूमि और गृह जिला जमुई ही है. क्षेत्रवार देखें तो अलग-अलग क्षेत्रों में दोनों मंत्रियों का अपना दबदबा भी है. साथ ही अपनी-अपनी विरादरी के वोटरों पर अच्छी पकड़ भी है. दोनों मंत्रियों के समर्थकों का एक खेमा ऐसा भी है, जो समय-समय पर पाला भी बदलता रहता है. भीतर-भीतर कई समर्थक नाराज भी चल रहे हैं. जदयू कार्यकर्ताओं के अंदर पनप रहे असंतोष से जिले के दोनों मंत्री परेशान भी चल रहे हैं. गठबंधन टूटने का असर यह है कि दोनों मंत्री व उनके समर्थक मुस्लिम मतदाताओं के बीच खुद को उनके सबसे बड़े हिमायती बताने में ही सारी ऊर्जा लगाए हुए हैं. जदयू नेता सह जिप अध्यक्ष ब्रहमदेव रावत कहते हैं कि जिले के सभी चार विधानसभा सीटों पर जदयू का कब्जा है. भाजपा का उस जिले में कोई जनाधार नहीं है.

दोनों मंत्रियों के बीच का विवाद जिलाध्यक्ष के मनोनयन के दौरान भी देखने को मिला. संगठन पर दबदबा बनाये रखने के लिए दोनों के बीच शीत युद्ध का दौर भी चला. यही वजह रही कि दोनों मंत्रियों के बीच चल रहे विवाद को सुलझाते हुए सबसे अंत में जमुई जिलाध्यक्ष का मनोनयन संभव हुआ. सूत्र बताते हैं कि विवाद को सुझाने में प्रदेश संगठन को बीच में आना पड़ा. साथ ही दोनों खेमों के एक-एक नेता को प्रदेश महासचिव का पद देना पडा. जदयू कार्यकर्ता दबी जुबान यह भी कहते हैं कि जिलाध्यक्ष राजकुमार दास की संगठन के कार्यकर्ताओं के बीच कोई पहचान नहीं रहने के बावजूद उनका मनोनयन हुआ. राजकुमार दास कहते हैं कि नीतीश हमारे रोल माडल हैं. जनता विकास पुरुष के नाम पर लोकसभा चुनाव में फिर से जदयू को वोट देगी. अब बात अगर आने वाले लोकसभा चुनाव की करें तो जमुई सुरक्षित लोकसभा सीट पर कब्जा बरकरार रखना जदयू के लिए आसान नहीं दिख रहा है. भाजपा से गठबंधन टूटने का असर साफ तौर पर यहां देखा जा सकता है. अगले लोकसभा चुनाव में अब यह सीट जदयू के पास रहेगी या नहीं उस पर भी संशय है. वर्तमान सांसद भूदेव चौधरी से लोकसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता असंतुष्ट ही नजर आते हैं. जदयू के एक कार्यकर्ता बड़ी ही नाराजगी से कहते हैं कि आखिर उतने दिनों में भूदेव चौधरी ने ऐसा क्या किया है कि जनता उन्हें याद रखे. उनकी एक भी घोषणाएं पूरी नहीं हुई हैं. जदयू के प्रदेश महासचिव राजेश सिंह कहते हैं कि गठबंधन टूटने का कोई भी असर जदयू के सेहत पर नहीं पड़ा है. आगामी लोकसभा चुनाव में किसी भी प्रत्याशी को टिकट उनके पिछले कार्यकाल का हिसाब लेकर दिया जाएगा. वहीं जदयू के एक और प्रदेश महासचिव शंभूशरण का मानना है कि विकास के अलावा जनता किसी को नहीं चुनेगी और यह भी कहते हैं कि जदयू कार्यकर्ता समर्पित पार्टी है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का फैसला ही अंतिम है. जमुई जिले में जदयू का झंडा मजबूती से लहराता रहेगा. ■

ब्रह्मदेव रावत

राजेश सिंह

शंभुशरण

feedback@chauthiduniya.com

पृष्ठ 17का शेष

ऑपरेशन यादव पटाओ शुरू

लोगों को शायद ख्याल नहीं है कि लालू प्रसाद के जेल जाने के बाद पार्टी और भी मजबूती से उभर कर सामने आई है. ऐसे हालात में पार्टी का हर कार्यकर्ता लालू प्रसाद हो जाता है. एक लालू से निपटना ही विरोधियों के लिए मुश्किल है और जब राजद का हर कार्यकर्ता लालू प्रसाद हो जाएगा तो विरोधियों का क्या होगा, इसकी कल्पना की जा सकती है. लालू प्रसाद को हमेशा परेशान करने की कोशिश होती रही है, लेकिन इन सब बातों से राजद को फर्क नहीं पड़ेगा. हमारे विरोधियों को भारी निराशा होने वाली है. भाजपा के लोग माहौल खराब कर रहे हैं, लेकिन राजद बिहार में सांप्रदायिक ताकतों को मजबूत नहीं होने देगा. लोजपा के वरिष्ठ नेता सत्यानंद शर्मा भी मानते हैं कि राजद की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा. लालू प्रसाद बहुत बड़े नेता हैं और राजद व लोजपा का गठबंधन बिहार में सांप्रदायिक ताकतों को मजबूत नहीं होने देगा. राजद व लोजपा के नेता भले दावा कर रहे हों कि सब कुछ ठीक रहेगा, लेकिन जमीनी सच्चाई यह है कि आठ सालों से सत्ता से दूर रहने और अब चारा घोटले के प्रकरण ने यादवों के बीच एक असमंजस की स्थिति पैदा कर दी है. अब यह भाजपा व अन्य दूसरी पार्टियों पर है कि वह इस असमंजस की स्थिति से कितनी मजबूत राजनीतिक लाइन खींच पाती हैं. ■

feedback@chauthiduniya.com

जनता त्रस्त सरकार मस्त

बिहार के बंटवारे से पहले यहां कई उद्योग हुआ करते थे, जिसमें बेगूसराय ज़िले के बरौनी प्रखंड में बरौनी रिफाइनरी, बरौनी थर्मल पावर स्टेशन के अलावा बरौनी खाद्य कारखाना शामिल था, लेकिन बिहार से झारखंड के अलग होने के बाद सिंदरी खाद्य कारखाना सहित कई महत्वपूर्ण कारखाने झारखंड में चले गए. 1992 में बरौनी खाद्य कारखाना को बीमार औद्योगिक इकाई की श्रेणी में डाल दिया गया. उसी क्रम में 1996 में कारखाने की व्यवसायिक उत्पादन क्षमता 1000 टन से घटाकर 556 टन प्रतिदिन कर दिया गया. बाद में स्थिति ऐसी हुई कि 2002 में केंद्र की तत्कालीन एनडीए सरकार ने उसे बंद करने का निर्णय लिया. बाद के दिनों में उसे चालू करने के लिए कई जांच कमेटी गठित की गई. कमेटी ने जांच रिपोर्ट में उस कारखाने को चालू करने के लिए पूंजी निवेश एवं नई मशीन लगाने का सुझाव दिया, लेकिन कमेटी के सुझाव को केंद्र सरकार ने ठंडे बस्ते में डाल दिया. पहले से ही विकास के मामले में पिछड़े बिहार को एक और झटका लगा. बिहार में तत्कालीन राजद की सरकार ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया. ऐसा नहीं है कि बिहार से केंद्र सरकार में मंत्री नहीं हुए. नीतीश कुमार, लालू प्रसाद, रामविलास पासवान से लेकर कई नेता केंद्र में महत्पूर्ण मंत्रालयों को संभाल चुके हैं. जब बरौनी फर्टिलाइजर को हमेशा के लिए बंद किया जा रहा था या कमेटी के सुझावों को ठंडे बस्ते में डाला जा रहा था, तब किसी ने फर्टिलाइजर के पक्ष में आवाज़ बुलंद नहीं की. डॉ. भगवान प्रसाद सिन्हा कहते हैं कि तीनों नेताओं नीतीश, रामविलास और लालू ने फर्टिलाइजर को चालू कराने की घोषणा कर के यहां की जनता को ठगने का काम किया है. सिन्हा याद करते हुए बताते हैं कि ज़िले में फर्टिलाइजर की स्थापना वामपंथी आंदोलनों की देन थी. कहते हैं कि उस समय योगिंद्र शर्मा सीपीआई से सांसद हुआ करते थे और उन्हीं के पहल पर किसानों ने अपनी ज़मीन दी और फर्टिलाइजर कारखाना लगा. बाद में उद्योग राज्यमंत्री रहीं कृष्णा शाही ने भी वादा किया था कि यहां पेट्रोकेमिकल्स के साथ-साथ अन्य कारखाने भी लगेंगे, लेकिन सभी के वादे और दावे हवा-हवाई ही निकले. उन्होंने कहा कि एक बार फिर से फर्टिलाइजर को पुनर्जीवित करने के लिए जनआंदोलन की ज़रूरत है.

जब केंद्र सरकार में रामविलास पासवान उर्वरक एवं रसायन मंत्री थे, तब यहां के निवासियों में उम्मीद जगी कि अब बरौनी खाद्य कारखाने की किस्मत बदलेगी. 12 नबंवर, 2008 को बरौनी उर्वरक नगर में तत्कालीन केंद्रीय उर्वरक व रसायन मंत्री रामविलास पासवान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव जैसे बिहार के तीनों दिग्गज नेताओं ने मंच से घोषणा की थी कि राजनीति से ऊपर उठ कर बिहार के विकास के लिए हम काम करेंगे. बरौनी खाद्य कारखाने को चालू करने के साथ ही 2011 से उत्पादन भी शुरू करने की घोषणा की गई थी, लेकिन दुर्भाग्य कि उस मंच से की गई घोषणा पर किसी ने अमल करने की कोशिश नहीं की. आज स्थिति यह है कि लगभग पांच किलोमीटर के दायरे में फैला यह खाद्य कारखाना जीर्णशीर्ण अवस्था में है. कभी यहां का गुलजार रहने वाला टाउनशिप आज वीरान पड़ा हुआ है. कारखाने की सुरक्षा में पदस्थापित सीआईएसफ के सैकड़ों जवान की जगह आज यहां प्राइवेट सेक्टर के 10-12 सुरक्षा गार्ड मौजूद हैं. कारखाने के क़ीमती समानों की लगातार चोरी की बातें स्थानीय लोग बताते हैं. साथ ही कारखाना और टाउनशिप परिसर से लाखों रूपए के पेड़ों की भी असामाजिक तत्वों द्वारा कटाई जारी है. बेगूसराय के आरटीआई कार्यकर्ता गिरीश प्रसाद गुप्ता ने लोक सूचना अधिकार के तहत बरौनी फर्टिलाइजर के बारे में जब सूचना मांगी तो हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत सरकार के उपक्रम के लोक सूचना अधिकारी एससी पंवार ने जानकारी दी कि बरौनी खाद्य कारखाना में उत्पादन जनवरी, 1999 से बंद था. जिससे कंपनी को सरकारी आदेशानुसार, 2002 में बंद कर दिया गया. गिरीश प्रसाद गुप्ता ने रासायन व उर्वरक मंत्रालय को एक आवेदन भेजकर बरौनी खाद्य कारखाने को पुनर्जीवित करने संबंधी सूचना मांगी थी. गुप्ता आरोप लगाते हैं कि लोक सूचना आधिकारी ने उन्हें आधी-अधूरी जानकारी दी है. कारखाने को पुनर्जीवित करने के प्रश्न पर पल्ला झाड़ते हुए संबंधित मंत्रालय से जानकारी प्राप्त करने के लिए आवेदक को परामर्श दिया गया. ■

feedback@chauthiduniya.com

पंडित उगम पाण्डेय महाविद्यालय, मोतिहारी
बी.आर. अम्बेदकर बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर की स्थायी सम्बद्ध इकाई
हमारी मुख्य विशेषताएँ
- कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय के सभी प्रचलित एवं पारम्परिक विषयों के साथ-साथ समाज शास्त्र, गृह विज्ञान, भूगोल, संगीत, प्रा.भा. इतिहास एवं संस्कृति, संस्कृत, उर्दू, परसीयन एवं भोजपुरी में भी प्रतिष्ठा स्तर तक समुचित अध्यापन की सुविधा
- विद्वान एवं अनुभवी प्राध्यापक
- समृद्ध पुस्तकालय एवं प्रयोगशाला
- छात्रों के मार्गदर्शन के लिए यू.जी.सी. द्वारा प्रायोजित कैरियर काउंसेलिंग एवं समय-समय पर रीमेडियल कोचिंग की व्यवस्था
- सी.सी.टी.वी. कैमरे से सुव्यवस्थित महाविद्याल कैम्पस
- सुव्यवस्थित कम्प्यूटर रूम जिसमें कम्प्यूटर की शिक्षा प्रदान की जायेगी।
- एन.एस.एस. की इकाई कार्यरत
- यू.जी.सी. से 2 एफ एवं 12वीं में रजिस्टर्ड
स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं
श्री किशोर पाण्डय, सचिव, शासी निकाय, पंडित उगम पाण्डेय महाविद्यालय, मोतिहारी
डॉ. कर्मात्मा पाण्डेय, प्रधानाचार्य, पंडित उगम पाण्डेय महाविद्यालय, मोतिहारी

रक्षा बन्धन और स्वतंत्रता दिवस की सीतामढ़ीवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं प्रस्तुति - वाल्मीकि ब्यूरो प्रमुख

समस्त बिहारवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं
निवेदक शोभा देवी, जिलाध्यक्ष, जिला जनता दलयू, महिला प्रकोष्ठ, सीतामढ़ी

स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं
निवेदक डॉली देवी, सदस्य, पंचायत समिति रुन्नीसैदपुर, ग्राम/पोस्ट - मोरसंड, जिला - सीतामढ़ी

समस्त बिहारवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं
निवेदक शंभु पासवान, प्रखंड कृषि पदाधिकारी, पुपरी, सीतामढ़ी

समस्त बिहारवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं
निवेदक दिलीप कुमार राय, प्रदेश महासचिव, युवा राष्ट्रीय जनता दल बिहार -आवास- रुन्नीसैदपुर, सीतामढ़ी

समस्त प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं
निवेदक अतुल कुमार, सचिव, रेडक्रास सोसायटी सह अनुमंडल खेल संघ, पुपरी एवं संयोजक राजवाग युवा संस्थान पुपरी, सीतामढ़ी

रक्षा बन्धन और स्वतंत्रता दिवस की गोगरी-परबत्ता प्रखंडवासियों हार्दिक शुभकामनाएं
ईद, स्वतंत्रता दिवस एवं रक्षा बन्धन के शुभ अवसर पर प्रखंड के समस्त नागरिकों, पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों, छात्र/छात्राओ एवं किसान, मजदूर भाईयों को हार्दिक बधाई। निवेदक नौशाद आलम, प्रखंड विकास पदाधिकारी, गोगरी, खगड़िया
स्वतंत्रता दिवस एवं रक्षा बन्धन के शुभ अवसर पर प्रखंड के समस्त नागरिकों, पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों, छात्र/छात्राओ एवं किसान-मजदूर भाईयों को हार्दिक बधाई। निवेदक संजय यादव, प्रखंड प्रमुख प्रतिनिधि, गोगरी, खगड़िया
स्वतंत्रता दिवस एवं रक्षा बन्धन के शुभ अवसर पर प्रखंड के समस्त नागरिकों, पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों, छात्र/छात्राओ एवं किसान-मजदूर भाईयों को हार्दिक बधाई। निवेदक मनीष कुमार, सहायक थानाध्यक्ष, भरतखंड, प्रखंड-परबत्ता, जिला-खगड़िया
स्वतंत्रता दिवस एवं रक्षा बन्धन के शुभ अवसर पर प्रखंड के समस्त नागरिकों, पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों, छात्र/छात्राओ एवं किसान-मजदूर भाईयों को हार्दिक बधाई। निवेदक अमर यादव, मुखिया प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत राज-वासुदेवपुर, प्रखंड-गोगरी, जिला-खगड़िया

नौनिहालों का रखें ध्यान
रक्षा बन्धन की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ
ariskon Pharma Pvt.Ltd. डॉ. मेजर कुन्दन
नवजात बच्चों में सांस लेने की समस्या होती है. इस समय में उनमें इंफेक्शन का खतरा भी अधिक रहता है इसीलिए नवजात बच्चों को हम एनआईसीयू में रखते हैं. बच्चे को जन्म के आधे घंटे के अंदर ही मां का दूध मिलना चाहिए. इस दौरान मां के दूध के अलावा कोई और चीज न दें. इससे संक्रमण से उनका बचाव होता है. जन्म के तुरंत बाद शिशु को पोलियो की दवा, बीसीजी और हिपेटाइटिस का टीका देना चाहिए. साथ ही बच्चे को मां के ही समीप रखना चाहिए, इससे बच्चे को मां के शरीर की गर्मी मिलती है. मां को भी स्वच्छता का पूरा ख्याल रखना चाहिए तकि बच्चा गंदगी और संक्रमण की चपेट में नहीं आये. बच्चे का मालिश करना भी वैज्ञानिक रूप से सही माना गया है, लेकिन दोपहर के समय में. अब तो हमारे जिले बेगूसराय नवजात शिशु के लिए आधुनिक तकनीक उपलब्ध है. यहां भी बच्चों के लिए सरफेक्टेंट थेरेपी मौजूद है. इसमें बच्चों को हम दो-तीन दिन वेंटीलेटर पर रखते है, इसके बाद ही बच्चे सामान्य स्थिती में आते हैं. जब बच्चे का वजन एक से आठ किलो का हो जाए और बच्चा ब्रेस्ट फिडिंग करने लगे तभी हम उसे डिस्चार्ज करते हैं.
ACOBA CAP/SYP/INJ Methylcobalmin, Lycopene, Multivitamin Multimineral, Ginseng & Antioxident
Carbo - XT Ferrous Ascorbate with Folic Acid Tab.
AREX Dextromethorphan, Guaiphenesine Ammonium chloride Cough Syp.
ACOBA CAP/SYP/INJ Methylcobalmin, Lycopene, Multivitamin Multimineral, Ginseng & Antioxident
Carbo - XT Ferrous Ascorbate with Folic Acid Tab.
NOKSIRA Pharma Pvt.Ltd. A Division of AriskonPharma
प्रस्तुति: शशि

स्वतंत्रता दिवस समारोह एवं रक्षा बन्धन पर समस्त झारखण्डवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं
Regd. No. : 33 DHN 1978 Amendment Regd. No. 43 DHN 30.04.2011
JORAPOKHAR PACS LTD.
H.O. : At - Jorapokhar, P.O. : Jamadoba, Dhanbad (Jharkhand) 828112
मनोज कुमार प्रबंधक सखी चन्द महतो अध्यक्ष
Affiliated with DHANBAD CENTRAL CO-OP BANK LTD.

भाई-बहनों का पवित्र त्योहार रक्षा बन्धन की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ :-
EXPERT BANK COACHING
MODERN STUDY CENTER
West of Patel Field, Kashipur, SAMASTIPUR
बेहतर मार्गदर्शन, अधिकतम सफलता की गारंटी, न्यूनतम शुल्क के साथ
• Expert & Experienced Faculties के मार्गदर्शन में नोट्स, प्रैक्टिस सेट्स एवं परीक्षा पूर्व विशेष TEST SERIES के साथ. अब जून 2011 से Test With Discussion Classes. सप्ताह में कम से कम 2–3 Test Series • English Classes For XI & XII Speaking & Competitive Courses के लिए • Notes, Practice-set, Model Paper With Answer, Competitive Test Series अब पत्राचार द्वारा भी मंगवा सकते हैं. • Bank (Clerk/P.O.), SSC, RLY (Non Tech & ALP Tech), Sachivalya Sahayak, TET (Teacher Eligibility Test) की तैयारी एवं मार्गदर्शन हेतु EXPERT BANK COACHING अवश्य Join करें.
एक विशेष सूचना बिहार के किसी भी जिला/ब्लॉक/मुहल्ला या गांव में चलने वाली कोचिंग संस्थान के संचालक हमारे यहां से Notes, Test Srries etc. के लिए 'Franchies' लेकर हमारे संस्थान का अभिन्न अंग बन सकते हैं. इस वर्ष November 2013 से मैट्रिक के लिए भी Notes, Practice-set, Model Paper With Answer & ATOM BOMBS (सभी विषयों का) उपलब्ध करायी जायेगी.
A. Kumar (Anil Kumar) Chairman, Modern Study Centre & Expert Bank Coaching
Contect : 9835006852, 9471043020.

भाई-बहन के प्यार का पवित्र त्योहार रक्षा बन्धन की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ
लक्ष्य+ परिश्रम+ मार्गदर्शन = सफलता
लक्ष्य साईंस&कॉमर्स कोचिंग
XI, XII (B.S.E.B., C.B.S.E.) Med. & Engg.
स्थानः पटेल मैदान से पश्चिम, काशीपुर, समस्तीपुर ठाकुर उदयशंकर चेयरमैन
Tel : 06274-227029, www.lakshyacoaching.in

Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2012-13-14, RNI No. DELHIN/2009/30467

रामसखा चौधरी की हेचरी में फिलहाल सिल्वर कॉर्प, ग्रास कॉर्प, कतला, रोहू, नैनी, कौमन कॉर्प व भांकुर समेत कई अन्य प्रकार की मछलियों को विधिवत तैयार किया जा रहा है. प्रति सीजन क़रीब सवा करोड़ बीज तैयार करने की क्षमता वाली इस हेचरी से वैशाली, मधुबनी, दरभंगा समेत उत्तर बिहार के कई ज़िले के मत्स्यपालक बीज लेने आने लगे हैं.

सीतामढ़ी

मतस्य पालन में मिला मुक़ाम

पुपरी अनुमंडल क्षेत्र के बररी बेहटा निवासी रामसखा चौधरी और उनकी पत्नी ने जलालपुर में वर्ष 2005 में मतस्य पालन की शुरुआत की. 7 साल में मतस्य पालन का उनका तरीक़ा इतना चर्चित हो गया कि ख़ुद मुख्यमंत्री को यहां आना पड़ा.

ब्रजेश/गोविंद

सीतामढ़ी ज़िले में पुपरी अनुमंडल क्षेत्र के बररी बेहटा निवासी रामसखा चौधरी की लगन और मेहनत की चर्चा हर कोई कर रहा है. चौधरी अपनी पत्नी निर्मला देवी के सहयोग से जलालपुर बेंगरी स्थित तक़रीबन 11 एकड़ ज़मीन में आरएन फिश हेचरी के साथ मतस्य पालन की शुरुआत 2005 से शुरू की. आज सच्ची लगन और कड़ी मेहनत की बदौलत चौधरी ने न केवल हेचरी का विकास किया, बल्कि गौ पालन से लेकर वर्मी कंपोस्ट तक तैयार करने की योजना बना डाली. महज साल साल में ही उनके मतस्य पालन का तरीक़ा इतना चर्चित हुआ कि पिछले तीन मई को अपनी यात्रा के दौरान ज़िले की यात्रा पर पहुंचे मुख्यमंत्री को भी यहां आना पड़ा. मुख्यमंत्री ने उन्हें उचित मदद का भरोसा भी दिया. फिलहाल, उनकी हेचरी में सिल्वर कॉर्प, ग्रास कॉर्प, कतला, रोहू, नैनी, कौमन कॉर्प व भांकुर समेत कई अन्य प्रकार की मछलियों का विधिवत पालन किया जा रहा है. प्रति सीजन क़रीब सवा करोड़ बीज तैयार करने की क्षमता वाली उस हेचरी से वैशाली, मधुबनी, दरभंगा समेत उत्तर बिहार के कई ज़िले के मत्स्य पालक बीज लेने आने लगे है. मांग इतनी अधिक बढ़ गई है कि अब बीज उपलब्ध कराना हेचरी कर्मियों के लिए बड़ी चुनौती बन गई है. मतस्य पालकों के लिए प्रतिमाह चार बार किसान पाठशाला का भी हेचरी परिसर में विधिवत आयोजन किया जाता है, जिसमें आसपास के भी किसान पहुंच कर लाभ उठा रहे हैं. मत्स्य विभाग से बतौर प्रशिक्षक संजीव कुमार किसानों को प्रशिक्षण देते हैं. व्यवस्थापक चौधरी का कहना है कि अगर किसान चाहें तो मछली पालन के साथ कई अन्य कार्य भी एक साथ कर सकते हैं, इससे न केवल उन्हें एक पहचान मिलेगी, बल्कि आर्थिक तंगी से भी निजात मिलने की पूरी उम्मीद है. ■

feedback@chauthiduniya.com

हेचरी में तैयार होता बीज

प्रिमियम ऑफिसेस

एक सर्वोत्तम उच्च स्तरीय सुसज्जित ऑफिस

- बेहतरीन लाकेशन पर तैयार और फर्निश्ड ऑफिस स्पेस
- कर्मचारियों तथा आगंतुकों के लिए सीधी पहुंच
- बेहतरीन लोकेशन पर होने की वजह से बेहतर रिटर्न
- स्पेस के उत्तम उपयोग के लिए कार्यकुशल ऑफिस स्पेस तथा हाई फ्लोर-टू फ्लोर क्लीयरेंस के साथ प्रीमियम डिजाइन
- कैफेटीरिया, फूड कोर्ट, ईट आउट जोन के साथ रिटेल स्पेस
- आगन्तुकों एवं सर्विस के लिए अलग लिफ्ट की व्यवस्था
- 24 घंटे जलापूर्ति, दोहरा बेसमेन्ट, कार पार्किंग स्पेस

- एयर कंडीशनर्स
- दोहरा बेसमेंट कार पार्किंग स्पेस
- स्टाफ के लिए खास डिजाइन की गई कुर्सियां
- वाल पेन्टिंग्स
- अग्नि सुरक्षा प्रणाली
- चौबीसो घंटो जलापूर्ति
- पावर बैक अप

Earth Infrastructures Ltd.
EARTH
innovation beyond imagination
4th Floor, Bhagwati Dwarika Acrade Exhabition Road, Patna - 800001
Ph : 0612-3215709

इंटरव्यू

आईटी एजुकेशन पर देना होगा ख़ास ध्यान

अपने सतत प्रयास से विश्व कंप्यूटर साक्षरता मिशन (वीसीएसएम) ने बिहार ही नहीं, पूरे देश में अपनी पहचान बनाई है. दुनिया की बेस्ट आईटी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट भी इसे अपना टेस्टिंग सेंटर बना चुकी है. वीसीएसएम कंप्यूटर शिक्षा को घर-घर तक पहुंचाने की दिशा में काम कर रहा है. राम संजीव कुमार वीसीएसएम के सीईओ हैं. चौथी दुनिया से उनकी बातचीत का संक्षिप्त अंश-

राम संजीव कुमार

पूरे देश में ड्रॉपआइट स्टूडेंट की संख्या बढ़ती जा रही है. ऐसे युवाओं के लिए संस्थान के द्वारा वोकेशनल कोर्स बड़ी संख्या में कराये जा रहे हैं. इन वोकेशनल पाठ्यक्रम के बाद छात्रों के लिए रोजगार एवं स्वरोजगार की संभावनाएं बढ़ जाती हैं.

■ **आई. टी. एजुकेशन की भारत में क्या दशा और दिशा है?**

- आईटी एजुकेशन रोजगारोन्मुख शिक्षण की आधुनिकतम विधाओं में से एक है. पिछले कुछ दशकों में आईटी इंडस्ट्री का उल्लेखनीय योगदान रहा. देशभर में सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में आईटी एजुकेशन पर ध्यान दिया जा रहा है. अभी इस पर और भी काम करने की आवश्यकता है. देश के कई राज्यों में तो अभी तक आईटी पॉलिसी भी नहीं बन पाई है.

■ **आप खुद बिहार के रहने वाले हैं. यहां आईटी एजुकेशन के क्षेत्र में आपकी क्या भूमिका है?**

- विश्व कंप्यूटर साक्षरता मिशन की स्थापना सन 2002 में हुई. उस समय का संपूर्ण बिहार, जो अब दो प्रदेशों अर्थात बिहार एवं झारखंड के रूप में हमारे सामने है. दोनों ही प्रदेश समान रूप से अब भी हमारा कार्यक्षेत्र रहा है. हम समान रूप से दोनों प्रदेशों में समाज के प्रत्येक वर्ग तक अपनी संस्था के माध्यम से आईटी एजुकेशन को सुलभ करने का प्रयास कर रहे हैं और हमें सफलता भी मिली है.

■ **आईटी एजुकेशन को बेहतर कैसे बनाया जा सकता है ?**

- निजी क्षेत्र में बहुतेरे संस्थान आईटी एजुकेशन देने का काम कर रहे हैं. इसके लिए एक मजबूत रेग्युलेटरी बॉडी का होना अत्यंत आवश्यक है. इन संस्थानों में गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण और आधारभूत संरचना को विकसित करने की आवश्यकता है.

■ **आपने समाज के प्रत्येक वर्ग की बात की. समाज में कुछ ऐसे वर्ग भी हैं, जो अभावों में जी रहे हैं. ये उच्च शिक्षा पर धन व्यय नहीं कर सकते, ऐसे में इनके लिए आपकी क्या योजना है?**

- बिहार में विश्व कंप्यूटर साक्षरता मिशन के माध्यम से और केंद्र सरकार की स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के तहत कई ज़िलों में बीपीएल एवं महादलित वर्ग के जिज्ञासुओं को नि:शुल्क कंप्यूटर प्रशिक्षण देने का कार्य किया है. हमें इसमें आशातीत सफलताएं भी प्राप्त हुई हैं.

■ **आपने बिहार में बीपीएल एवं महादलित वर्ग के बच्चों को नि:शुल्क कंप्यूटर शिक्षा प्रदान करने का कार्य किया है. क्या झारखंड के लिए आपकी कोई ऐसी योजना है ?**

- देखिये हम केवल बिहार या झारखंड की नहीं, बल्कि पूरे देश में अपनी संस्थान के माध्यम से उपस्थित हैं और बिहार की तरह अन्य प्रदेशों में भी मौक़ा मिला तो हम इसी आधार पर अपनी सेवा प्रदान करने के लिए संकल्पित हैं.

■ **क्या भारत कभी आईटी सुपर पावर बन सकता है?**

- भारत मानव संसाधन के मामले में अत्यंत समृद्ध देश है. युवाओं में मेधा शक्ति भी गजब की है. आईटी इंडस्ट्री में बहुत कम पूंजी व संसाधन की आवश्यकता होती है. इसमें बहुत बड़ी आधारभूत संरचना की भी जरूरत नहीं है. ग्लोबल आईटी ट्रेड में हम अपनी मजबूत दावेदारी पेश करके अपने राजकोष में विदेशी मुद्रा की उपस्थिति बढ़ा सकते हैं.

■ **तकनीकी शिक्षा, खासकर सूचना प्रौधोगिकी के क्षेत्र में भारतीय महिलाओं की क्या स्थिति है ?**

- भारतीय महिलाएं परिश्रमी व प्रतिभावान होती हैं. आईटी सेक्टर में महिलाओं की भागीदारी 12 से 15 प्रतिशत ही है. इस क्षेत्र में वीमेंस डेवलपमेंट काउंसिल की भूमिका सराहनीय है.

■ **मैट्रिक और इंटर के बाद के ड्रॉपआउट स्टूडेंट्स के लिए आपकी क्या योजना है?**

- पूरे देश में ड्रॉपआउट स्टूडेंट की संख्या बढ़ती जा रही है. ऐसे युवाओं के लिए संस्थान के द्वारा वोकेशनल कोर्स बड़ी संख्या में कराये जा रहे हैं. इन वोकेशनल पाठ्यक्रम के बाद छात्रों के लिए रोजगार एवं स्वरोजगार की संभावनाएं बढ़ जाती हैं.

■ **आप एक सफल इंटरप्रेन्योर होने के साथ-साथ शिक्षाविद् भी हैं. समाज के कमजोर वर्गों की उन्नति के लिए आप काफी कुछ करते हैं, तो क्यों नहीं आप नेतृत्व की मुख्यधारा में जुड़ कर अपनी सेवा प्रदान करते हैं ?**

- बड़ी अच्छी बात आपने कही है. मेरे पिता शिक्षक रहे हैं. मैं भी हूं. तत्पश्चात व्यवसाय की ओर मुड़ा. व्यवसाय भी किया आईटी एजुकेशन सेक्टर के क्षेत्र में. मैं लगभग 10 वर्षों तक वित्तरहित शिक्षा से जुड़ा रहा. यही वजह है कि मैं वित्तरहित शिक्षाकर्मियों के दर्द से भी अवगत हूं. शिक्षक का बेटा हूं, इसलिए प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा की हालात से भी अवगत हूं. इसीलिए इस बार आप जैसे शुभेक्षु मित्रों की सलाह पर कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से चयनित होने की इच्छा है. ताकि अपनी संपूर्ण क्षमता एवं समग्र भावना के साथ जरूरतमंदों की सेवा करने का संकल्प पूरा कर सकूं.

चौथी दुनिया ब्यूरो

feedback@chauthiduniya.com

Running with Spectacular Success

TECHNO MISSION SCHOOL

Samastipur - 848101 (Bihar), Phone : 06274 225309

e-mail : technomission.principal@gmail.com

Run & Managed by : Apurva Welfare Society, Samastipur

The whole school family expresses wholehearted wishes to all citizens, guardians, students and the teachers for their peace, prosperity and relishes on the eve of this most pious National festival "Independence Day" of our country.

SPECIAL ATTENTION :

Awareness to the Guardian about their wards' Day to Day absentee & progress in completion of Home - Work through SMS.

UNIQUE FEATURES

UP-TO-DATE TECHNOLOGY DRIVEN CLASSES

- Located in the heart of town, Eco-Friendly Campus.
- Built up with well-ventilated & spacious rooms.
- Spread over Free & Open Areas with Gorgeous Playground.
- Easily accessible & Congestion Free.
- English Medium, Co-educational, C.B.S.E.Curriculum.
- Special emphasis on co-curricular activities and Continuous Comprehensive Evaluation (CCE).
- Well-Skilled & devoted teachers, Special classes for weaker students.
- Learning Through Activities. Dance, Yoga, Games & Sports, Book Club etc.
- Conveyance facilities on the major routes .
- Special attention to "SPOKEN ENGLISH" & "PERSONALITY DEVELOPMENT"
- No need of any private tuition for our students.
- Regular Health Check-up, Regular Physical & Cultural Activities. Compulsory Book club.
- Periodical Seminars & Symposium, Compulsory Educational Tour.

Mr. A. K. Lal
Chairman
9431245057

Mr. M. K. Karna
Manager
9304051574

Mr. V. K. Mishra
Principal
9386951010

"EMPOWERMENT THROUGH EDUCATION"

चौथी दुनिया

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

26 अगस्त–01 सितंबर 2013

उत्तर प्रदेश – उत्तराखंड

सियासत के पहले पायदान पर बुंदेलखंड

बुंदेलखंड कभी पूरी तरह से आत्मनिर्भर हुआ करता था, आज दाने-दाने को मोहताज है. यहां के विकास के लिए सरकार अरबों-खरबों रुपये खर्च कर चुकी है, यहां के मंत्री नेता और नौकरशाह करोड़ों के मालिक हो गए. बुंदेलखंड के विकास के नाम पर कई नेता विधानसभा से लेकर संसद तक पहुंच गए. लालबत्ती हासिल कर ली, लेकिन यहां की जनता के हिस्से में निराशा और अभाव के अलावा कुछ भी नहीं आया.

संजय सक्सेना

उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड का विकास और सूखे की समस्या हमेशा यक्ष प्रश्न रही है. आजादी के 67 वर्षों के बाद भी बुंदेलखंड की जनता अन्न के लिए तरस रही है. सिंचाई आदि की बात तो दूर, पीने का पानी तक जुटाने के लिये यहां के निवासियों को कई-कई किलोमीटर दूर जाना पड़ जाता है. भूख और प्यास से मौतें यहां प्रदेश में सबसे अधिक होती हैं. काफी बड़ी आबादी तो सिर्फ इसीलिए बुंदेलखंड से पलायन करके अन्य जगह बस गई, क्योंकि यहां जीने लायक न्यूनतम हालात भी नहीं हैं. माताएं अपने बच्चों को चंद रुपये की खातिर बेच देती हैं.

सभी सरकारों ने बुंदेलखंड की जनता के साथ छल किया. बसपा, सपा कांग्रेस और भाजपा सभी दलों को राजनीतिक रोटियां सेंकने के लिए यह इलाका काफी रास आता है. खासकर केन्द्र और राज्य सरकारों (चाहे वह किसी भी दल की क्यों न हों) के बीच बुंदेलखंड को लेकर टकराव कभी न खत्म होने वाला सिलसिला बना हुआ है. बुदेलखंड के विकास के मसले पर केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच पैकेज वार (आर्थिक मदद) भी खूब देखने को मिलती है. चुनावी मौसम में तो बुंदेलखंड सभी सियासतदारों के लिए पहले पायदान पर रहता है. लोकसभा चुनाव की सुगबुगाहट होते ही एक बार फिर बुंदेलखंड के तथाकथित हमदर्द सामने आ गए हैं. अखिलेश सरकार एक बार फिर केन्द्र को बुंदेलखंड पैकेज की राजनीति में उलझाना चाहती है. राज्य सरकार केन्द्र पर दबाव बनाने के लिए शीघ्र ही बुंदेलखण्ड पैकेज के दूसरे चरण में लगभग 4737.13 करोड़ रुपये के नये प्रस्ताव केन्द्र सरकार को मंजूरी के लिए भेजने जा रही है. यह प्रस्ताव बुंदेलखंड को पानी की समस्या से निजात दिलाने के लिए भेजा जाएगा. पानी की समस्या से जूझ रहे बुंदेलखंड को उससे निजात दिलाने के लिए राज्य सरकार लगभग 178 सामूहिक नलकूपों, 800 चेकडैमों, 2500 गहरे नलकूपों तथा 6000 मध्यम गहरे नलकूपों का निर्माण कराना चाहती है. उसके लिए उसे लगभग 465.20 करोड़ रुपये की जरूरत पड़ेगी. वहीं वन क्षेत्रों से गुजरने वाले नालों के पानी को रोककर भूगर्भ के जलस्तर को बढ़ाने एवं गांव के निकट सिंचाई एवं पेयजल हेतु पानी उपलब्ध कराने के लिए बुंदेलखण्ड के 7 जनपदों में लगभग 166 नालों में चेकडैमों का निर्माण कराया जाएगा. सिंचाई विभाग की नौ परियोजनाओं-रतौली वीयर बांध, क्योलारी बांध सहायक परियोजना, पहाड़ी बांध आधुनिकीकरण, भौरट बांध परियोजना, इटारी बांध परियोजना, चिलीमल पम्प नहर का पुनरुद्धार, एरच बांध परियोजना, बबीना ब्लाक के ग्रामों में सिंचाई सुविधा, अर्जुन सहायक परियोजना के लगभग 2237.69 करोड़ रुपये के प्रस्ताव भी अनुमोदित कर भारत सरकार को भेजने के निर्देश दिए गए हैं. राज्य सरकार की मंशा यह भी है कि बुंदेलखण्ड क्षेत्र के जनपद मुख्यालयों पर 7 विशिष्ट मंडी तथा 168 ग्रामीण अवस्थापना केन्द्र (रिन) का, बुंदेलखण्ड क्षेत्र के समस्त जनपदों में वर्षा जल संचयन एवं संवर्धन हेतु 588 चैक डैमों का भी जल्द से जल्द निर्माण हो जाए. चेकडैमों के निर्माण से वर्षा जल का संचयन एवं संरक्षण होगा तथा उस जल को किसानों द्वारा सिंचाई के लिए उपयोग में लाया जाएगा. सिंचाई जल उपयोग क्षमता में वृद्धि करने हेतु स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली को प्रोत्साहित किया जाना तथा उस प्रणाली के तहत बुंदेलखण्ड क्षेत्र के समस्त जनपदों में 15980 स्प्रिंकलर सेट वितरित करने का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है. उस योजना के अन्तर्गत लघु एवं सीमान्त किसानों को 90 प्रतिशत अनुदान तथा सामान्य किसानों को 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा. बुंदेलखण्ड पैकेज से कुछ अनुदान भारत सरकार की योजनाओं को तथा शेष अनुदान राज्य सरकार की बुंदेलखण्ड क्षेत्र में वर्षा जल संचयन योजना से दिया जाएगा.

बुंदेलखण्ड के किसानों की आर्थिक दशा में सुधार आए, उसके लिए क्षेत्र में सोयाबीन की खेती, बकरी इकाईयों, चारा विकास, दुग्ध सहकारी समितियों का गठन किया जाएगा. सोयाबीन की खेती को बढ़ावा देने के लिए एक सोयाबीन आयल मिलिंग प्लांट की स्थापना कराने के बारे में भी राज्य सरकार ने एक प्रस्ताव तैयार कराया है, जिसपर लगभग 10,100 लाख रुपये व्यय होंगे. उसके अलावा ग्राम स्तर पर लगभग 18.43 करोड़ रुपये की लागत से साइलेज इकाईयों की स्थापना तथा 8.43 करोड़ रुपये की लागत से बकरी इकाईयों की स्थापना कराने के साथ-साथ 11.67 करोड़ रुपये की लागत से बुंदेलखण्ड में चारा विकास कराया जाएगा.

शेष पृष्ठ संख्या 18 पर

सरकारी मशीनरी की नाकामी

बुंदेलखंड के विकास में सरकारी इच्छाशक्ति का अभाव है, तो सरकारी मशीनरी भी यहां आकर पंगु हो जाती है. दिसंबर, 2012 तक के सर्वे के नतीजे बताते हैं कि राजघाट कमांड एरिया डेवलपमेंट करने में जहां 69500 हेक्टेअर क्षेत्र का विकास करना था, उसकी तुलना में केवल 39140 हेक्टेअर ही डेवलपमेंट हो सका. सरकारी मशीनरी काम करने में पीछे तो जरूर रही, लेकिन अपने हितों के साथ उसने कोई समझौता नहीं किया. बुंदेलखंड में तैनात अफसरों ने खूब चांदी काटी. 7200 करोड़ के विशेष पैकेज में चित्रकूट धाम मंडल बांदा को 1226 करोड़ और झांसी मंडल के हिस्से में 2272 करोड़ रुपये आए थे. बाकी धनराशि मध्य प्रदेश के हिस्से वाले बुंदेलखंड को दी गई थी. यूपी के भ्रष्ट, बेलगाम अफसर अपने-अपने हिस्से की पूरी धनराशि खर्च ही नहीं कर पाए. जो काम हुआ भी, उसका फायदा किसको मिला कोई नहीं जानता. चित्रकूटधाम मंडल में दुग्ध विकास विभाग को 8 करोड़ 61 लाख रुपये उस पैकेज से दिया गया. लोगों को उसका कोई फायदा नहीं मिला. सारा पैसा कागजों में खर्च दिखा दिया गया. स्थानीय दुग्ध उत्पादन केन्द्र आज भी तालाबंदी का शिकार हैं. लघु सिंचाई विभाग को सिंचाई की छोटी योजनाओं चेकडैम आदि के लिए 177 करोड़ 46 लाख रुपये स्वीकृत किए गए थे. उस धनराशि में विभाग ने 58 करोड़ 2 लाख रुपये चेकडैम आदि के निर्माण में खर्च दिखाया हैं . ठेकेदारी पद्धति से बनवाए गए सारे चेकडैम एक साल में ही ध्वस्त हो गए हैं. अब जांच की बात कही जा रही है.■

कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ सकती हैं जयाप्रदा

दर्शन शर्मा

सिने तारिका जयाप्रदा अब कांग्रेस की सियासी कश्ती पर सवार होने की फिराक में हैं. संभव है 2014 के लोकसभा चुनाव में दिल्ली दरबार उन्हें अपना प्रत्याशी बना ले. राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि जयाप्रदा कांग्रेस आलाकमान सोनिया गांधी से उस बाबत मुलाकात कर अपनी मंशा जाहिर कर चुकी हैं और लगातार संपर्क में है. उम्मीद जताई जा रही है कि जया जल्द ही कांग्रेस का दामन थाम लेंगी.

फिल्मों में धूम मचाने वाली जया का राजनीतिक सफर भी काफी लंबा है. फिल्मी दुनिया से होते हुए वे 1994 में तेलगु देशम के संस्थापक एनटी रामराव की राजनीतिक पार्टी टीडीपी से जुड़ गईं. जिसके टिकट पर 1996 में वह राज्यसभा की सदस्य चुनी गईं, लेकिन टीडीपी के शीर्षस्थ नेता चंद्रबाबू नायडू से पटरी न खाने की वजह से उन्हें टीडीपी छोड़नी पड़ी. उसी दौरान जया की मुलाकात सपा में दखल रखने वाले अमर सिंह से हुई. सपा में अमर सिंह के प्रभाव के चलते जयाप्रदा ने रामपुर लोकसभा सीट से दो बार 2004 और 2007 में चुनाव जीत चुकी हैं. अमर सिंह का राजनीतिक तिलस्म तब टूट गया, जब उन्हें सपा से पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते निष्कासित कर दिया गया. साथ में यह खामियाजा जयाप्रदा को भी भुगतना पड़ा. अमर सिंह के सपा से निष्कासन के बाद जया अलग-थलग पड़ गईं. हालांकि अमर सिंह ने अपना नया राजनीतिक दल लोकमंच जरूर बना लिया है, लेकिन उससे जया का राजनीतिक कद ऊंचा नहीं उठ पा रहा था. अमर सिंह चाहते थे कि सपा से बदला चुकता करने के लिए जयाप्रदा को बसपा में शामिल करवा लें. यह अटकलें अखबारों की सुर्खियां बनती रही हैं. वहीं राजनीति का स्वाद चख चुकीं जया प्रदा भी सपा से नाता तोड़ने के बाद से किसी ऐसी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी की प्रत्याशी बनने की लगातार जुगत भिड़ाने में जुटी हैं. उससे पहले उनके चुनाव लड़ने के बारे में कयास यह लगाए जा रहे थे कि जया अपने गृह राज्य आन्ध्र प्रदेश के राजमुंदरी संसदीय क्षेत्र से वाईआरएस कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ सकती है. राजनीतिक डगर पर कब, कौन, किधर मुड़ जाए, कुछ पता नहीं. ऐसा ही सांसद और अभिनेत्री जया प्रदा के साथ हुआ. उन्हें जाना था वाईआरएस कांग्रेस में, लेकिन पहुंच गईं कांग्रेस की आलाकमान के दरबार में. सोनिया गांधी से मिलकर जया ने इच्छा जताई है कि वह रामपुर या राजमुंदरी कहीं से भी चुनाव मैदान में उतरने को तैयार हैं. आंध्र की राजमुंदरी लोकसभा सीट से कांग्रेस के वी अरुण कुमार वर्तमान में सांसद हैं. इसलिए अच्छे प्रत्याशियों की तलाश कर रही कांग्रेस की आलाकमान का नजरिया है कि जया को रामपुर संसदीय सीट से चुनाव लड़ाया जाए और रामपुर से सांसद रह चुकीं बेगम नूरबानों को मुरादाबाद सीट से टिकट दिया जाए. वहीं मुरादाबाद के कांग्रेस के वर्तमान सांसद अजहरूद्दीन को आन्ध्र प्रदेश से चुनाव लड़ने की संभावना जताई जा रही है. ■

feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया

आवश्यकता है

संवाददाता, विज्ञापन प्रतिनिधि, प्रसार प्रतिनिधि

चौथी दुनिया के लिए उत्तर प्रदेश के सभी मंडल और जिला मुख्यालयों पर अनुभवी संवाददाताओं, विज्ञापन और प्रसार प्रतिनिधियों की. पारिश्रमिक योग्यता अनुसार. शीघ्र आवेदन करें.

E-mail- konica@chauthiduniya.com
ajaiup@chauthiduniya.com
चौथी दुनिया F-2, सेक्टर 11, नोएडा (गौतमबुद्ध नगर)
उत्तर प्रदेश-201301,
PH : 120-6450888, 6451999

www.chauthiduniya.com
चौथी दुनिया

सियासत के पहले पायदान पर बुंदेलखंड

पृष्ठ 17 का शेष

पशुधन विभाग द्वारा 6 प्रस्ताव 63.06 करोड़ रुपये की लागत से भारत सरकार को भेजे जा रहे हैं. दुग्ध विकास के अंतर्गत 24.85 करोड़ रुपये के 03 प्रस्ताव अनुमोदित किए गए हैं, जिसमें बुंदेलखंड के समस्त जनपदों में प्रतिवर्ष 40 ग्रामीण दुग्ध सहकारी समितियां अर्थात आगामी 3 वर्षों में 120 दुग्ध समितियां गठित की जाएंगी. दुग्ध विकास कार्यक्रम द्वारा ग्रामीण सीमांत किसानों, दुग्ध उत्पादकों को उनके दुग्ध उत्पाद का ग्रामीण स्तर पर दुग्ध का मार्केट उपलब्ध कराने एवं उनकी आय में वृद्धि कराने के दृष्टिकोण से डेयरी सेक्टर को ग्रामीण लेवल तक सुदृढ़ करने के लिए बुंदेलखंड के 7 जनपदों में 3 वर्षीय वित्तीय सहायता लगभग 1370.056 लाख रुपये कुल उपलब्ध कराए जाएंगे.

बहरहाल, एक तरफ़ राज्य और केंद्र सरकार बुंदेलखंड के विकास के लिए लंबे –चौड़े दावे कर रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ़ सच्चाई यह भी है कि बुंदेलखंड वासियों का विश्वास विभिन्न सरकारों और नेताओं पर से उठता जा रहा है. बुंदेलखंड पर केंद्र और यूपी दोनों ही अपनी राजनीतिक रोटियां सेंक रहे हैं. केंद्र सरकार पैसा देने में सुस्त है, तो उत्तर प्रदेश उसे ख़र्च करने में कंजूस है. नेशनल रेनफेड एरिया अथॉरिटी की जांच रिपोर्ट बताती है कि मार्च 2013 तक बुंदेलखंड राहत पैकेज में से यूपी सरकार केवल 43 प्रतिशत राशि ही ख़र्च कर पाई. इधर, कुल आवंटित पैकेज में प्रदेश को मार्च तक केंद्र से केवल 71 प्रतिशत पैसा ही आवंटित हुआ. उनमें से भी केंद्र की ओर से केवल 61.38 फ़ीसदी राशि ही जारी की जा सकी. प्रदेश सरकार को 2009 में तीन साल के लिए 3606 करोड़ का पैकेज दिया गया था. मार्च 2013 तक उनमें से केवल 1695 करोड़ धनराशि ही आवंटित हो सकी. उसमें भी केवल 1212 करोड़ की केंद्रीय सहायता से भेजे गए. वहीं केंद्रीय योजनाओं से इस पैकेज के लिए दिए जाने वाले 1318 करोड़ में से केवल 263 करोड़ धनराशि ही मिल सकी.

सपा सरकार की प्राथमिकता में बुंदेलखंड

समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी कहते हैं कि समाजवादी सरकार के गठन के तुरंत बाद यह प्राथमिकता तय की गई थी कि एक विशेष योजना बनाकर प्रदेश के क्षेत्रीय असंतुलन को दूर कर समग्र विकास की नींव रखी जाएगी. उसी क्रम में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव प्रदेश के उपेक्षित क्षेत्रों बुंदेलखंड एवं पूर्वांचल के विकास पर विशेष ध्यान दे रहे हैं. वर्ष 2013–14 के बजट में पूर्वांचल की विशेष योजनाओं एवं सड़क संयोजकता में सुधार कार्यों के लिए 291 करोड़ रुपये तथा बुंदेलखंड की विशेष योजनाओं एवं सड़क संयोजकता में सुधार कार्यों के लिए 109 करोड़ रुपये बजट की व्यवस्था की गई. चौधरी कहते हैं कि सपा सरकार द्वारा पूर्वांचल और बुंदेलखंड के समग्र विकास के लिए सड़क, बिजली, पानी और उद्योगों के विस्तार की विशेष योजनाएं बनाई गई हैं. वाटर बॉडीज के रिपेयर, रिनोवेशन और रिस्टोरेशन (आरआरआर) संबंधी परियोजना प्रारंभ की जा रही है, जिसके लिए 200 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है. प्रारंभ में यह योजना बुंदेलखंड क्षेत्र के जनपद बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, चित्रकूट, झांसी एवं ललितपुर में चलाई जानी है. इस योजना में वाटर बॉडीज की क्षमता की पुनर्स्थापना और मरम्मत संबंधी कार्य कराए जाने से भूजल स्तर में वृद्धि होगी और कृषि की उपज भी बढ़ेगी, जिससे किसानों के जीवन स्तर में सुधार आएगा. झांसी में एक एस्ट्रो टर्फ भी बनाया जाएगा.

बसपा के समय में भी चलती थी तनातनी

बसपा सरकार के समय बुंदेलखंड पैकेज को लेकर ख़ुद केंद्रीय योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया को ही तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती को पत्र लिखना पड़ा था. उन्होंने लिखा था कि बुंदेलखंड में मिली धनराशि का काम सुस्त ढंग से हो रहा है. फरवरी में पैकेज की निगरानी करने वाली नेशनल रेनफेड एरिया अथारिटी के सीईओ डॉ. जेएस सामरा आए, तो उन्होंने भी राज्य सरकार पर सुस्ती का आरोप लगाया था. उस समय सामरा ने दुख व्यक्त करते हुए कहा था कि यूपी बुंदेलखंड के लिए प्रस्ताव भेजने में ही सुस्ती कर रहा है. दस महीनों में यूपी की ओर से केंद्र को केवल सौ करोड़ के प्रस्ताव मिले थे. ■

feedback@chauthiduniya.com

सत्ता के गलियारे से

राजनीति का शिकार दुर्गा

सरकार दुर्गा शक्ति के मामले में इतना आगे बढ़ गई हैं कि वहां से क़दम पीछे खींचने का मतलब मुस्लिमों की नाराज़गी मोल लेना होगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सरकार को दुर्गा के हितों की चिंता नहीं है. संभवत: कहीं न कहीं युवा सीएम को इस बात का मलाल ज़रूर है कि दुर्गा राजनीति का मोहरा बन गई हैं...

समाजवादी सरकार पंजाब कैडर के 2010 बैच की युवा आईएएस अधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल के साथ सख्ती से पेश आ रही है. तमाम दबाओं को अनदेखा करके सपा सरकार ने दुर्गा के साथ कोई समझौता नहीं किया, जबकि उस बात की प्रबल संभावना है कि अदालत से सरकार को दुर्गा के मामले में क़रारा सबक मिल सकता है. राजनीतिक पंडित इस मामले को अखिलेश सरकार की वोट बैंक की मजबूरी से जोड़कर देख रहे हैं. सरकार दुर्गा शक्ति के मामले में इतना आगे बढ़ गई है कि वहां से क़दम पीछे खींचने का मतलब मुस्लिमों की नाराज़गी मोल लेना होगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सरकार को दुर्गा के हितों की चिंता नहीं है. संभवत: कहीं न कहीं युवा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को उस बात का मलाल ज़रूर है कि दुर्गा राजनीति का मोहरा बन गई हैं. यही वजह है की दुर्गा से नाराज़ चल रही राज्य सरकार ने उसके पति को अच्छी तैनाती देकर नवाजा है.

दुर्गा के 2011 बैच के आईएएस पति अभिषेक सिंह को झांसी में संयुक्त मजिस्ट्रेट के पद पर तैनाती दी गई है. अभिषेक अपनी पत्नी से एक वर्ष जूनियर थे और हाल में ही उनकी गाजियाबाद में ट्रेनिंग समाप्त हुई थी. पहली पोस्टिंग में अभिषेक को मिली उक्त तैनाती सरकारी दृष्टि से अच्छी और महत्वपूर्ण मानी जाती है. प्रदेश सरकार ने अभिषेक के साथ–साथ यूपी के 16 और नये आईएएस अधिकारियों को भी स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के पद पर तैनाती दी है. वैसे, ऐसे लोगों की भी संख्या कम नहीं है, जिनका मानना है कि पति को अच्छी पोस्टिंग देकर सरकार दुर्गा शक्ति के ताप को कम करना चाहती है. अब दुर्गा सरकार के इस फ़ैसले से कितना खुश होंगी, यह तो वही जानें, लेकिन उनके लिए व्यक्तिगत रूप से एक और अच्छी खबर यह है कि बालू खनन माफ़ियाओं के ख़िलाफ़ कार्रवाई से बौखलाई समाजवादी सरकार ने भले ही एक धर्म का सहारा लेकर उन्हें दंडित किया हो, लेकिन कुछ दिनों के भीतर ही सरकार को मानना पड़ गया कि राज्य में खनन का अवैध धंधा चल रहा है. यूपी सरकार ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के समक्ष स्वीकारा है कि राज्य में अवैध खनन हो रहा है और गौतमबुद्ध नगर में खनन के लिए एक भी पर्यावरण मंजूरी नहीं दी गई थी. ■

feedback@chauthiduniya.com

चूल्हा चौका कर रही हैं महिला अध्यक्ष

पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं तथा दलितों को उचित प्रतिनिधित्व दिए जाने की मंशा से आरक्षण का प्रावधान किया गया. लेकिन यह व्यवस्था व्यवहारिक धरातल पर नहीं उतर सकी. ज्यादातर महिलाएं अध्यक्ष व ब्लाक प्रमुख चूल्हा–चौका तक ही सिमट गई हैं.

शिवनाथ चतुर्वेदी

प्रदेश में अधिकांश जनपदों के नगरपालिका परिषद समेत नगर पंचायत और विकास खंडों में खड़ाऊं राज चल रहा है. असली अध्यक्ष, प्रमुख का कभी दर्शन नहीं होता, पर उनके परिजन या सरपरस्त दबंगई के साथ नगर पंचायत, ब्लॉक मुख्यालयों पर आवंटित अध्यक्ष, प्रमुख के कक्ष और उनकी कुर्सी पर बैठकर अधिकारियों व कर्मचारियों पर हुक्म चलाते हैं. उनके साथ लकज़री गाड़ियों में चलने वाले बंदूकधारियों से सभी ख़ौफ़ खाते हैं. दहशत में सरकारी मुलाजिमों को तमाम सही ग़लत काम भी करने पड़ते हैं. हस्तक्षेप (मानवाधिकार जन निगरानी समिति) के राष्ट्रीय महासचिव डीपी यादव ने उस स्थिति को गंभीरता से लेते हुए शिकंजा कसना शुरू कर दिया है.

पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं तथा दलितों को उचित प्रतिनिधित्व दिए जाने की मंशा से आरक्षण का प्रावधान किया गया. लेकिन यह व्यवस्था व्यवहारिक धरातल पर नहीं उतर सकी. प्रभावशाली नेताओं के घरों की महिलाएं उनके यहां मेहनत–मजदूरी करने वाले लोग कई नगर पंचायत और ब्लाकों अध्यक्ष प्रमुख निर्वाचित हो गए. ज्यादातर महिला अध्यक्ष व ब्लाक प्रमुख चूल्हा–चौका तक ही सिमट गई हैं. कुछ मालिक के यहां नौकरी बजा रहें हैं. उनका नाम केवल कागजों में चलता है. सारा काम उनके परिजन या सरपरस्त ही करते हैं. नेताजी के साथ चार–छह गाड़ियों का काफिला चलता है, जिसमें बंदूकधारी भी होते हैं. उनके नगर पंचायत व ब्लाक कार्यालय पर पहुंचते ही वहां का महौल बदल जाता है. वे बाकायदा अध्यक्ष व ब्लाक प्रमुख की कुर्सी पर बैठते हैं और अधिकारियों और कर्मचारियों को नगर पंचायत और अध्यक्ष ब्लाक प्रमुख की हैसियत से आदेश देते हैं, बंदूकों के साये में घिरे कर्मचारी दहशत में रहते हैं.

राष्ट्रीय महासचिव, हस्तक्षेप (मानवाधिकार जन निगरानी समिति) डीपी यादव ने उसका संज्ञान लेते हुए, कार्रवाई के लिए मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश समेत प्रमुख सचिव और नगर विकास व ग्राम विकास सचिव को अगल–अलग पत्र लिखा है. डीपी यादव ने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि नगरपालिका समेत नगर पंचायत व विकास खंड मुख्यालयों पर दंबगों का राज है. निर्वाचित अध्यक्ष व ब्लाक प्रमुखों के कक्ष में हथियारबंद लोगों के उठने–बैठने से सरकारी अधिकारी व कर्मचारी अपने को असुरक्षित महसूस करते हैं, उनके विकास कार्य भी प्रभावित होते हैं. डीपी यादव ने उस संबंध में राज्य पुलिस प्रमुख को भी एक पत्र अलग से लिखा है. पत्र के माध्यम पुलिस प्रमुख से निवेदन किया गया है कि वह अपने स्तर से राज्य के सभी जिला पुलिस महाकमे के आला अफसरों को निर्देश दे कि वह नगरपालिका समेत नगर पंचायत व ब्लाक मुख्यालयों पर हथियारों के प्रदर्शन करने वाले दबंगों के हथियारों के लाइसेंस निलंबित करें. ■

feedback@chauthiduniya.com

खिलाड़ियों की कद्र नहीं

भारत में प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की कोई कमी नहीं है. आज खेलों की ऐसी स्थिति इसलिए है कि उस पर भी राजनीति हावी है. ऐसे में प्रतिभावान खिलाड़ी गुमनामी के अंधेरे में खो जाते हैं या खेल को अलविदा कह अन्य उद्योग धंधों में लग जाते हैं...

वह बेहद खास है जिसने देश को फिगर आइस स्केटिंग में पहला गोल्ड मेडल दिलाया हो और सिल्वर मेडल भी साथ लेकर आया हो. ऐसा युवा आम तो नहीं हो सकता. लेकिन वह अपनी प्रतिभाओं की वजह से वह महत्व नहीं पा सका, जिसका हकदार है. उसकी शारीरिक अक्षमता उसे कमजोर नहीं कर सकी. उसने लगन और जज्बे से विशेष दर्जा हासिल किया है. मेहनत और हुनर ने इस 19 साल के युवा को स्पेशल ओलिंपिक में फिगर आइस स्केटिंग में देश का पहला गोल्ड मेडलिस्ट बनाया. लेकिन मेडल की चमक इसकी गरीबी दूर न कर सकी. नवंबर में आयोजित होने वाली एक अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में उसे फिर से देश का प्रतिनिधित्व करने का मौक़ा मिला है, लेकिन पैसों की कमी उसे अपने कदम आगे बढ़ने नहीं दे रही. मजबूर यह स्पेशल गोल्ड मेडलिस्ट अपने पिता के साथ सदर में पटरी लगाकर इयररिंग्स और क्लचर बेच रहा है. दूसरे गेम्स में भी आगे है. राजकुमार के पिता सदर में पटरी लगाकर इयररिंग्स और क्लचर बेचते हैं. राजकुमार को मिलाकर उनके पांच बच्चे हैं. राजकुमार को बचपन से ही मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन जैसी बीमारी है. उसे आम बच्चों के मुकाबले कुछ सीखने समझने में ज़्यादा समय लगता है. जल्दी गुस्सा आ जाता है. उसने पांचवीं क्लास तक ही पढ़ाई की. इसके बाद उसमें खेलने कूदने की प्रतिभा को दिशा दी राम बाग, पहाड़गंज स्थित दिल्ली प्रतिभा इस्टिट्यूट फॉर स्पेशल चिल्ड्रन ने. यहां मिली ट्रेनिंग और कोचिंग ने उसे स्पेशल ओलिंपिक तक पहुंचाया. उसके कोच रोहित मनचंदा ने बताया कि राजकुमार सिर्फ आइस स्केटिंग में ही बेहतर नहीं है, वह हैंडबॉल, फुटबॉल भी अच्छा खेलता है.

नवंबर में आयोजित होने वाली एक अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में उसे फिर से देश का प्रतिनिधित्व करने का मौक़ा मिला है, लेकिन पैसों की कमी उसे अपने क़दम आगे बढ़ाने नहीं दे रही. मजबूरन यह स्पेशल गोल्ड मेडलिस्ट अपने पिता के साथ सदर में पटरी लगाकर इयररिंग्स और क्लचर बेच रहा है.

ऑस्ट्रेलिया से बुलावा, पर पैसे नहीं: दरअसल गर्मियों में होने वाले स्पेशल ओलिंपिक में विजेताओं को 5, 3 और 2 लाख तक का इनाम दिया जाता है, जबकि सर्दियों में इनाम राशि करीब 25 हजार के आसपास ही रहती है. राजकुमार को अभी अपनी पहली जीत की रकम भी नहीं मिली. लेकिन उसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपने देश का प्रतिनिधित्व करने का फिर से मौका जरूर मिल रहा है. नवंबर में ऑस्ट्रेलिया में होने वाले स्पेशल ओलिंपिक एशिया पेसिफिक गेम्स में उसे बैडमिंटन के लिए चुना गया है. लेकिन उसके पास खेल प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं है. उसे वहां जाने के लिए कम से कम 85 हजार रुपये की जरूरत है. लेकिन उसके लिए 85 हजार की रकम जुटाना किसी नामुमकिन को मुमकिन करने जैसा है.

नेताओं ने नहीं की कोई मदद: स्पेशल ओलिंपिक भारत, दिल्ली के डायरेक्टर वीरेंद्र कुमार ने बताया कि सरकार की तरफ से ऐसे बच्चों के लिए पांच साल के डेवेलपमेंट प्रोग्राम चलाए जाते हैं और यह प्रोग्राम पिछले साल ही संपन्न हुआ है. इस वजह से राजकुमार को नवंबर में आयोजित होने वाले गेम्स के लिए स्कॉलरशिप नहीं दी जा सकती. हां, कोई उसे स्पांसर करना चाहे तो जरूर कर सकता है. लेकिन फिर भी पूरा पैसा मिलने की उम्मीद कम है. राजकुमार के पिता ने बताया कि वह जब मदद की गुहार लेकर स्थानीय नेताओं के पास पहुंचे तो उन्होंने भी टाल दिया. लेकिन गरीबी के इस फटे लिबास से उसके अंदर अब भी उम्मीद भरी आंखों से झांक रहे हैं. राजकुमार को इंतजार है उन हाथों का जो उसे अपनी छोटी सी मुट्ठी में आसमान भरने का मौका देगा. ■

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

सामूहिक प्रयास की ज़रूरत

उत्तराखंड में आई तबाही का असर स्वतंत्रता दिवस के मौक़े पर भी देखने को मिला और हमेशा की तरह स्वतंत्रता दिवस पर हर्षोउल्लास भी देखने को नहीं मिला. उत्तराखंड में स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह में राज्य के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने ध्वजारोहण किया. उत्तराखंड में स्वतंत्रता दिवस सादगी से मनाया गया. अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देने के साथ ही देहरादून के ऐतिहासिक परेड ग्राउंड में झंडारोहण करने के बाद हाल में आई दैवीय आपदा में मृत और लापता लोगों को श्रद्धांजलि दी और उनके परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की. बहुगुणा ने प्रदेशवासियों पर इस बात के लिए गर्व जताया कि उन्होंने खुद अभावों में रहते हुए भी अपने दुख भूल कर आपदा में फंसे श्रद्धालुओं और पर्यटकों की सेवा और सहायता की. उन्होंने कहा कि देवभूमि के लोगों के इस जज्बे पर पूरे देश को गर्व है. मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि आपदाग्रस्त राज्य के पुनर्निर्माण के लिए सामूहिक प्रयास की ज़रूरत है. बहुगुणा ने कहा कि आपदा से राज्य में हुए भीषण नुक़सान को देखते हुए एक नया उत्तराखंड बनाने की ज़रूरत है और इसके लिए सभी को मिल–जुलकर प्रयास करने होंगे. समृद्ध और सुरक्षित उत्तराखंड के निर्माण के लिए राज्य सरकार वचनबद्ध है. आइये हम सब मिलकर अपनी मातृभूमि के प्रति निष्ठा का संकल्प लें. उन्होंने कहा कि मैं विश्वास दिलाता हूं कि हम सभी के सहयोग से सपनों को साकार करेंगे. इस मौक़े पर मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारियों और जवानों को भी सलाम किया और जवानों की आपदा के दौरान की गई सेवा के लिए उनकी प्रशंसा की. मुख्यमंत्री साहसीय सेवा पदक से पुलिस उपाधीक्षक गिरीश चंद्र टण्टा, इंस्पेक्टर इंदुभूषण नौटियाल, इंस्पेक्टर चक्रधर अथवाल, इंस्पेक्टर शेखर जोशी तथा पुलिस कांस्टेबल केसी प्रसाद को सम्मानित किया. मुख्यमंत्री ने वहां पर मौजूद स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों से मुलाकात की और उन्हें शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया. उत्तराखंड के राज्यपाल अजीज कुरैशी ने राजभवन में ध्वजारोहण किया. उसके बाद राज्यपाल ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी सहित देश को आजादी दिलाने वाले सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि दी. राज्यपाल ने कहा कि हाल ही में हुई आपदा प्रकृति का प्रकोप थी. हमें निजी स्वार्थों से ऊपर उठकर और सभी मतभेदों को भुलाकर इसका सामना करना होगा. हमेशा की तरह राजभवन में आयोजित होने वाले सायंकालीन स्वल्पाहार का कार्यक्रम भी निरस्त कर दिया गया और राज्यपाल की अपेक्षा के अनुसार राज्य में आई आपदा के कारण इस बार यह राष्ट्रीय पर्व अत्यंत सादगी से मनाया गया. ■

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

अब 60 साल में रिटायरमेंट

लंबे समय से रिटायरमेंट की मांग कर रहे कर्मचारियों की इच्छा अब पूरी हो गई है. वित्त विभाग ने स्वशासी संस्थाओं में कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु 60 वर्ष तय करने का शासनादेश जारी कर दिया है. शासनादेश में गैर जरूरी पदों को समाप्त करने का भी निर्देश भी दिया गया है. स्वशासी संस्थाओं को इस व्यवस्था को लागू करने से जुड़े दिशा–निर्देशों का पालन करते हुए प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराने को कहा गया है. गौरतलब है कि वित्त विभाग की अंतिम मंजूरी के बाद ही स्वशासी संस्थाएं अपने यहां रिटायरमेंट की आयु सीमा 60 साल कर सकेंगी. उम्मीद की जा रही है कि स्वशासी संस्थाओं में काम कर रहे 50 हजार कर्मचारियों को इससे फायदा होगा. प्रदेश की डेढ़ दर्जन स्वशासी संस्थाओं के कर्मचारी अभी 58 वर्ष की उम्र में ही रिटायर हो जाते हैं. इन संस्थाओं से जुड़े कर्मचारी संगठन लंबे अरसे से राज्य कर्मियों की तरह रिटायरमेंट की आयु सीमा 60 वर्ष करने की मांग कर रहे थे.

एक अगस्त को कैबिनेट की बैठक में सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी गई. सचिव वित्त अजय अग्रवाल ने अब शासनादेश जारी कर स्वशासी संस्थाओं को इस संबंध में जरूरी कार्यवाही करने का रास्ता साफ कर दिया है.

सचिव वित्त ने प्रमुख सचिवों और सचिवों से कहा है कि वे अपने नियंत्रण वाली स्वशासी संस्थाओं में इसके लिए तेजी से कार्यवाही कराएं.

इस तरह करनी होगी कार्यवाही

- स्वशासी संस्थाओं को सबसे पहले कम उपयोगी व गैर जरूरी पदों को समाप्त करने की कार्यवाही करनी होगी.
- सेवानिवृत्ति आयु सीमा बढ़ाने से बढ़ने वाले खर्च का संस्था को आकलन करना होगा.

खर्च कहां से पूरा होगा इसकी व्यवस्था करते हुए प्रस्ताव गवर्निंग बॉडी से पास कराकर संस्था उसे संबंधित विभाग को भेजेगी.

- प्रशासकीय विभाग (स्वशासी संस्था जिस विभाग से जुड़ी है) देखेगा कि प्रस्ताव में वित्तीय आकलन ठीक से किया गया है या नहीं.
- विभाग अपनी संस्तुति के साथ प्रस्ताव वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग को भेजेगा जो वित्त विभाग की सहमति प्राप्त करेगा.
- वित्त विभाग की सहमति मिलने के बाद प्रशासकीय विभाग उम्र बढ़ाने संबंधी प्रस्ताव पर कैबिनेट का अनुमोदन प्राप्त करेगा. इसके बाद वित्त विभाग उम्र बढ़ाने संबंधी शासनादेश जारी करेगा.

इन स्वशासी संस्थाओं के कर्मियों को मिलेगा लाभ

- उत्तर प्रदेश स्वतंत्रता सेनानी कल्याण संस्थान
- भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण
- राज्य ललित कला अकादमी
- ग्रेटर नोएडा
- लीडा
- जिला ग्राम्य विकास अभिकरण
- हिंदी संस्थान, संस्कृत संस्थान, उर्दू अकादमी, फखरुद्दीन अली अहमद मेमोरियल कमेटी, भाषा संस्थान और सिंधी अकादमी.
- मत्स्य पालक विकास अभिकरण
- संगीत नाटक अकादमी
- अयोध्या शोध संस्थान

जनपद वासियों को रक्षाबंधन व कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं

सुनील सर्राफ
जिलाध्यक्षः सर्राफा मंडल
प्रदेश उपाध्यक्ष : उत्तर प्रदेश स्वर्णकार संघ

कपिलदेव यादव
पूर्व ब्लॉक प्रमुख पंदह
प्रबंधक : योगीराज चुहिया बाबा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, जगदरा, बलिया उत्तर प्रदेश

संपर्क :
09628111520

आकर्षक फिजिक ने नहीं, अभिनय ने दिलाई सफलता

सलमान, आमिर, शाहरूख जैसे अभिनेताओं को दर्शकों ने खूब पसंद किया. कुछ समय से सिनेमा में काफी प्रयोग हो रहे हैं, दर्शकों की पसंद भी अब बदल रही है. अब वे चॉकलेटी इमेज से बाहर निकल कर साधारण शक्ल सूरत वाले अच्छे अभिनेताओं को भी दर्शक काफी पसंद कर रहे हैं.

धर्मेंद्र सिंह

फिल्म गैंग ऑफ वासेपुर में शानदार अभिनय से अपनी पहचान बनाने वाले अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी उत्तर प्रदेश मुज़फ्फरनगर जिले से 40 किलोमीटर दूर भुवाना के रहने वाले हैं. उनके पिता किसान हैं. वह उन लोगों में से हैं, जो सड़क से उठकर लोगों के दिलों में बस जाते हैं. हालांकि नवाजुद्दीन का फिल्मी सफर काफी उतार चढ़ाव भरा था. उन्होंने सोचा भी नहीं था कि उत्तर प्रदेश के एक छोटी सी जगह से निकलकर वह बी टाउन की गलियों को रौशन करेंगे.

उनके पास कोई काम धंधा नहीं था, न ही जीवन का कोई मकसद. अगर यहां कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि वह गलियों में आम आवारागर्दी करते थे. अपने बचपन को याद करते हुए नवाज कहते हैं कि उन्हें जब फ़िल्में देखना होता था तो ईद या दिवाली के मौके पर पैसा जमा करके वह अपने गांव से शहर में जाकर फ़िल्में देखते थे. तभी अचानक उनके जीवन में एक मोड़ आया और उन्होंने थियेटर की राह पकड़ी. नवाजुद्दीन ने अपनी पढ़ाई मुज़फ्फरनगर में पूरी करने के बाद थिएटर करना शुरू किया. वह बताते हैं कि छोटे मोटे नाटक करते हुए उन्हें लगा कि वह भी अभिनय कर सकते हैं. यहीं से उनकी जीवन की दिशा बदल गई. कुछ साल बाद उन्हें दिल्ली में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में प्रवेश मिला और वहीं से उन्होंने अपनी कला को तराशा. फिर दिल्ली में ही वह कोई चार साल तक छोटे मोटे नाटक करके गुज़ारा करते रहे. साल 2000 में उन्होंने मुंबई का रुख किया और उन्हें उम्मीद थी कि वहां जल्द ही अच्छा काम मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. टीवी सीरियलों में भी उनको काम नहीं मिलता था. नवाज कहते हैं, मुंबई में करीब पांच साल तक मुझे बहुत संघर्ष करना पड़ा. टीवी प्रोडक्शन हाउस के चक्कर काटते रहे. अपनी फोटो हर जगह देते रहे, लेकिन कोई रोल देने को तैयार ही नहीं था, क्योंकि भिखारी का रोल करने के लिए भी उन्हें छह फुट का जवान चाहिए था. मैं साधारण–सा दिखने वाला व्यक्ति. उन लोगों को हीरो मटेरियल की तलाश रहती. फिर नवाज ने फ़िल्मों में काम ढूंढना शुरू किया. और कुछ फ़िल्मों जैसे सरफ़रोश और मुन्नाभाई एमबीबीएस में एक एक सीन के रोल मिलने भी लगे. उन्होंने ये सोचकर रोल लिए कि शायद एक सीन से दो सीन फिर और कोई बड़ी भूमिका हाथ लगेगी, लेकिन जल्द ही नवाज को लगा कि अब उन्हें सिर्फ़ एक सीन के ही रोल के लिए बुलाया जाने लगा है. तब उन्होंने तय किया कि अब वह एक सीन का रोल नहीं करेंगे.

नवाज बताते हैं कि मुंबई में संघर्ष का यह ऐसा समय था कि वह एक समय खाना खाते तो दूसरे समय के लाले पड़ जाते. उन्होंने कई बार हार मानने की सोची और सब कुछ छोड़कर वापस गांव जाने का विचार बनाया. लेकिन फिर याद आता कि वह गांव क्या मुंह लेकर जाएंगे. नवाज कहते हैं, अगर मैं वापस जाता तो गांव में सब मज़ाक उड़ाते कि बड़ा बन रहा था, हीरो बनने गया था, वापस आ गया. तो वापस गांव जाने का विचार मैंने छोड़ ही दिया था. मुझे कोई और काम आता भी नहीं था तो कुछ और कर भी नहीं सकते थे, लेकिन मैंने सोच लिया था कि अब मरना जीना मुंबई में ही होगा. उस बीच फ़िल्मकार अनुराग कश्यप ने उनका एक नाटक दिल्ली में देखा और उन्हें अपनी फ़िल्म ब्लैक फ्राइडे में काम दिया, जिससे उन्हें अपनी क्षमता दिखाने का मौका मिला. उसके बाद फ़िराक़, न्यूयॉर्क और देव डी जैसी फ़िल्मों में काम मिला. पर यहां समस्या यह थी कि न्यूयॉर्क फ़िल्म के बाद कई फ़िल्मों के रोल के लिए बुलाया गया, लेकिन सभी या तो गुंडे या आतंकवादी के रोल थे, तो मुझे कई रोल से इन्कार करना पड़ा. फिर उन्हें पीपली लाईव में कुछ ठीक रोल मिला. और सुजोय घोष की कहानी में तो उनके काम की काफी सराहना हुई. अनुराग के साथ नवाज आगे भी दिखेंगे.

पतंग, मॉनसून शूटआउट और देख इंडियन सर्कस जैसी फ़िल्मों के अलावा अनुराग की गैंग्स ऑफ़ वासेपुर और असीम अहलूवालिया की मिस लवली में भी नवाजुद्दीन ने अहम भूमिका निभाई है. उसके अलावा, आमिर खान और करीना कपूर के साथ तलाश में भी नवाज मुख्य भूमिका में थे. वह फिल्म आत्मा में अभिनेत्री विपाशा बसु के पति की भूमिका में थे. ■

feedback@chauthiduniya.com

स्वतंत्रता दिवस , रक्षाबंधन व कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर मीना देवी, अध्यक्ष एवं समस्त सदस्यगण जिला पंचायत, फैजाबाद की ओर से जनपदवासियों को कोटि-कोटि बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं. जिला पंचायत अपने सभी करदाताओं एवं लाइसेंस धारकों से सादर अपील करती है कि अपने समस्त देयकों का भुगतान समय से करें. जिला पंचायत विकास के लिए सतत प्रयत्नशील है.

(मीना देवी)
अध्यक्ष, जिला पंचायत, फैजाबाद.

(शीलेंद्र कुमार सिंह)
अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, फैजाबाद.

(अखण्ड प्रताप सिंह)
मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, फैजाबाद.

सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन व कृष्ण जन्माष्टमी पर सभी सम्माननीय जनप्रतिनिधियों/अधिकारियों/कर्मचारियों/शिक्षकों एवं सम्मानित अभिभावकों को हार्दिक बधाईयां. सभी से अनुरोध है, कि स्वतंत्रता दिवस पर संकल्प लें, कि स्कूल न जाने वाले बच्चों को स्कूल में शिक्षा प्राप्त करने हेतु प्रवेश दिलायें.

राज कमल मेहरोत्रा
सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी
फैजाबाद

ज्ञान प्रकाश श्रीवास्तव
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
फैजाबाद

Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2012-13-14, RNI No. DELHIN/2009/30467

www.chauthiduniya.com

चौथी दुनिया

26 अगस्त–01 सितंबर 2013

मुलायम ने सीमाओं पर संकट को गंभीर बताते हुए कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ जब मैंने निंदा प्रस्ताव का सुझाव दिया तो केंद्र ने नहीं माना. जब पाकिस्तान ने निंदा प्रस्ताव पारित कर दिया तो हमने भी प्रस्ताव पास कर लिया. हमें देश को शक्तिशाली बनाना होगा.

साक्षर भारत
SAAKSHAR BHARAT

फैजाबाद

भष्टाचार के मकड़जाल में साक्षर भारत मिशन

साक्षरता मिशन की तरह केंद्र सरकार का साक्षर भारत मिशन भी भ्रष्टाचार के मकड़जाल मे फंसकर दिशा से भटक गया है. वित्तीय वर्ष 2011–12 से शुरू साक्षर भारत मिशन को एक साल बीत चुका है, लेकिन अभी तक न तो प्रेरक और न ही समन्वयक की नियुक्ति हो पाई है. फिर भी निरक्षरों की दो बार कागजी परीक्षाएं संपन्न करा दी गईं.

राकेश कुमार यादव

सरकार सर्व शिक्षा अभियान के तहत प्रयास तो काफी करती है, विभिन्न योजनाओं के लिए केंद्र से पैसे भी आते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाते हैं. फैजाबाद लोक शिक्षा समिति के खाते में मिशन संचालन के लिए 51 लाख 55 हजार 536 रुपये जमा हैं. धनराशि उपलब्ध होने के बावजूद जिला समन्वयक की नियुक्ति कागजों में दर्शाई गई है, उन्हें कोई मानदेय नहीं दिया जा रहा है. अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 नवंबर, 2009 को केंद्र सरकार ने साक्षर भारत मिशन शुरू किया था. मिशन के तहत ग्राम पंचायतों मे 15 वर्ष से ऊपर आयु वर्ग के निरक्षरों को बेसिक साक्षरता प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. जनगणना 2001 को दृष्टिगत रखते हुए जिस जिले में महिला साक्षरता की दर 50 फीसदी से कम है, उसको चयनित किए जाने का मानक निर्धारित किया गया है. उसी मानक के तहत वित्तीय वर्ष 2011–12 में फैजाबाद जिले का भी चयन किया गया है. चयन के बाद साक्षरता एवं वैकल्पिक शिक्षा निदेशक ने मिशन संचालन के लिए धनराशि भी उपलब्ध करा दी. यह धनराशि मुख्य कोषाधिकारी व सचिव जिला लोक शिक्षा समिति के संयुक्त खाते में जमा है.

साक्षर भारत मिशन मे प्रत्येक ग्राम पंचायत में लोक शिक्षा केंद्र के माध्यम से 15 वर्ष आयु से ऊपर के निरक्षरों के लिए कार्यात्मक साक्षरता बुनियादी और समकक्ष शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा और एकीकृत निरंतरता के रूप में सतत शिक्षा कार्यक्रमों की परिकल्पना की गई है. योजना में महिलाओं, अनुसूचित जाति, जनजाति, मुस्लिम और अन्य अल्पसंख्यकों को साक्षर बनाने पर बल दिया गया है. हालात यह हैं कि किसी भी ग्राम पंचायत में अभी तक लोक शिक्षा केंद्र की स्थापना नहीं हो पाई है. फैजाबाद के जिलाधिकारी विपिन कुमार द्विवेदी का इस संबंध में कहना है कि साक्षर भारत मिशन के लक्ष्य और उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बारहवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि सन् 2012–17 में जारी रखने का निर्णय लिया गया है. फैजाबाद जिले में अपेक्षा के अनुरूप कार्य न हो पाने के कारण मिशन का सुचारु रूप से क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है. नये सिरे से मुख्य विकास अधिकारी के माध्यम से कार्यक्रम के क्रियान्वयन की कवायद शुरू की गई है. आधारभूत प्रारंभिक कार्यवाही जैसे समितियों का गठन, संविदाकर्मियों का चयन, सब्सिडियरी खाता खुलवाना और प्रेरकों के चयन की कार्यवाही पूरी की जानी है.

क्या कहते हैं अधिकारी

''फैजाबाद जिले में महिला साक्षरता की दर 50 फीसदी से कम है इसीलिए साक्षर भारत मिशन के लिए जनपद को चयनित किया गया है. मिशन संचालन वर्ष 2011–2012 से शुरू किया जाना था, लेकिन अपेक्षा के अनुरूप कार्य न हो पाने के कारण कार्यक्रम का सुचारू रूप से क्रियान्वयन नहीं हो रहा है''

–विपिन कुमार द्विवेदी (जिलाधिकारी, फैजाबाद)

''साक्षर भारत मिशन के प्रेरकों का चयन जिले के ब्लाकों में शीघ्र पूरा कर लिया जाएगा. जिले के कुछ विकास खण्डों में दिक्कतें आ रही हैं. परीक्षा में निरक्षरों के मानसिक स्तर का मूल्यांकन कराया जाना आरंभ कर दिया गया है''

–ज्ञान प्रकाश श्रीवास्तव (बी.एस.ए. फैजाबाद)

मिशन संचालन के तहत सर्वेक्षण के लिए 4032 रुपये, पठन–पाठन सामाग्री के लिए 20,160 रुपये, एसटी प्रशिक्षण के लिए 5376 रुपये, अनावर्ती धनराशि के लिए 48 लाख 61 हजार 968 रुपये, जिला समन्वयकों के मानदेय के लिए एक लाख 44 हजार रुपये, कार्यालय व्यय के लिए 80 हजार रुपये और कम्युनिटी मोबलाइजेशन के लिए 40 हजार रुपये निर्धारित किए गए हैं. चूंकि योजना पहले ही चरण मे औंधे मुह गिर गई है, इसलिए एक साल बीत जाने के बावजूद खाते में जमा धन में से एक रुपया भी व्यय नहीं किया गया है. फिलहाल, जिला लोक शिक्षा समिति के सचिव का दायित्व तत्कालीन डीडीओ से लेकर जिला विद्यालय निरीक्षक व डायट प्राचार्य को दिया गया. वर्तमान में यह दायित्व पुन: जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को सौंप दिया गया है. जिला समन्वयक को मानदेय न दिए जाने के पीछे यही वजह बताई जा रही है.

मिशन के प्रचार–प्रसार के लिए जिला, ब्लाक और ग्राम पंचायत स्तर पर नुक्कड़ नाटक, प्रभात फेरी, वाल राइटिंग, समितियों की नियमित बैठकें, स्थानीय उत्सव, मेला, हाट, बाजार के माध्यम से जन समुदाय को जागरूक करने की भी योजना है. लोक शिक्षा केंद्रों के माध्यम से सर्वे में चिन्हित निरक्षरों को बेसिक साक्षरता प्रदान कराकर राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान के सहयोग से 25 अगस्त, 2013 और मार्च 2014 में लाभार्थियों की परीक्षाएं कराई जाएंगी.

गौरतलब है कि निरक्षर लोगों की दो परीक्षाएं अबतक संपन्न कराई जा चुकी हैं. विभागीय सूत्रों की मानें तो लाभार्थियों की पहली परीक्षा 26 अगस्त, 2012 को और दूसरी परीक्षा 17 मार्च, 2013 को संपन्न कराई जा चुकी है. अब साक्षरता प्रकोष्ठ का कहना है कि लाभार्थियों की पुन: परीक्षाएं अगस्त व मार्च में कराई जाएंगी. परीक्षा में पढ़ना, लिखना, जोड़ना और घटाना आदि बिंदुओं पर निरक्षरों की परीक्षा 50 अंकों में होगी. मूल्यांकन के बाद ए और बी ग्रेड पाने वाले निरक्षर उत्तीर्ण माने जाएंगे. सवाल यह है कि जब निरक्षर लोगों को पढ़ाने वाले ही नहीं हैं तो उनकी किस आधार पर परीक्षा कराई गई और 25 अगस्त को कैसे कराई जाएगी?

बताते चलें कि ऐसे ही 2001 में लाखों करोड़ों के घोटाले उजागर होने के बाद साक्षरता मिशन को जनपद में ठप्प कर दिया गया था. उत्तर प्रदेश साक्षरता मिशन भी फैजाबाद जनपद में नहीं शुरू हो पाया. साक्षरता मिशन के तहत 2001 में उजागर हुआ था कि इस मद में बड़े–बड़े घोटाले हुए हैं. सचिव सा–क्षरता मिशन के द्वारा एक ही दिन में 80 हजार रूपये का लड्डू वितरित करा दिए जाने का मामाल उजागर हुआ था. यहीं नहीं, पांच स्वयंसेवी संस्थाओं को बिना प्रशिक्षण कराए कागजी भुगतान कर धनराशि की बंदरबांट करने का मामला भी उजागर हुआ था.

तत्कालीन सरकारी एनजीओ नेहरू युवा केंद्र के जिला समन्वयक राम किशोर यादव ने लिखित रूप से तत्कालीन जिलाधिकारी अर्चना अग्रवाल से शिकायत की थी कि सचिव साक्षरता मिशन प्रशिक्षण अवधि बीत जाने के बाद प्रशिक्षण संपन्न कराने के कागजी दस्तावेज प्रस्तुत करने और एवज में मद की 50 फीसदी धनराशि देने का लालच दे रहें हैं. जिला समन्वयक के उस पत्र को तत्कालीन जिलाधिकारी ने गंभीरता से लेते हुए, साक्षरता मिशन के सचिव को जहां बदल दिया, वहीं खाते भी सीज कर दिए थे. उसी के बाद निरक्षरों को साक्षर करने का मिशन फैजाबाद में आजतक नहीं शुरू हो पाया. बीते सत्र से साक्षर भारत मिशन फैजाबाद में लागू किया गया है, परंतु कोई भी अधिकारी मद का एक रुपया भी खर्च करने का साहस नहीं जुटा पा रहा है.■

feedback@chauthiduniya.com

पांच लाख किसान कर चुके हैं आत्महत्या : मुलायम

संजय सक्सेना

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने नौजवानों और महिलाओं से कहा कि वे गांधी–सुभाष, भगत सिंह–अशफाक उल्ला खां और लोहिया–जेपी के सपनों का भारत बनाने के लिए आगे आएं. उनका मानना है कि आजादी के 66 वर्षों के बाद भी स्थिति में कुछ सुधार तो आया है, लेकिन स्वतंत्रता सेनानियों ने जो सपने देखे थे. वह पूरे नहीं हो पाए हैं. आने वाले समय में सबको रोटी, कपड़ा और मकान मिले, इसका संकल्प लेना है. मुलायम सिंह समाजवादी पार्टी कार्यालय, लखनऊ में ध्वजारोहण के पश्चात उपस्थित कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे. उन्होंने सबको स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी और देश की आजादी के लिए संघर्ष करने और शहीद होने वाले सेनानियों को नमन किया. सपा प्रमुख ने दुख जताया कि आज भी देश में मुट्ठी भर लोग ऐशो–आराम की जिंदगी जी रहे हैं, जबकि देश में करीब पांच लाख किसान आत्महत्या कर चुके हैं. खाली पेट वालों की ही सर्दी और लू से मौत होती है. हमें ऐसी व्यवस्था करनी है कि कोई भूखा न मरे. आज देश में अमीरी–गरीबी के बीच गहरी खाई है. भूख, बेकारी और गरीबी है. सिचांई और शुद्ध पेयजल की कमी है. उन कमियों को दूर करने और व्यवस्था बदलने की आवश्यकता है. सपा प्रमुख का कहना था कि हिन्दुस्तान आबादी के हिसाब से बहुत बड़ा देश है. यहां के किसान–मजदूर ज्यादातर निरक्षर और गरीब हैं. गांधी जी उनकी चिंता करते थे. बहुसंख्यक–अल्पसंख्यक के बीच अविश्वास है. हमें उनको भाई मानकर उनके साथ खड़ा होना होगा. उन्होंने कहा कि हमें अब दिल्ली की सरकार बदलनी होगी. सपा नेता ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में 'करो या मरो' के नारे के साथ स्वतंत्रता आंदोलन की चर्चा की और कहा कि तब पूरा देश अंग्रेजी शासन के खिलाफ उठ खड़ा हुआ था. गांधी जी ने सुराज का सपना देखा था. उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता आंदोलन में जिन लोगों ने बलिदान दिया, वे हमारे लिए श्रद्धेय हैं. आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण और डॉ लोहिया का स्वतंत्रता आंदोलन में भी महत्वपूर्ण योगदान था. हमारे सामने उनका आदर्श है.

यादव ने सीमाओं पर संकट को गंभीर बताते हुए कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ जब मैने निंदा प्रस्ताव का सुझाव दिया था तो केंद्र सरकार ने नहीं माना. जब पाकिस्तान ने निंदा प्रस्ताव पारित कर दिया तो हमने भी प्रस्ताव पास कर लिया. हमें देश को शक्तिशाली बनाना होगा. इस अवसर पर उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश सिंह यादव, स्वास्थ्य मंत्री अहमद हसन, जेल एवं खाद्य रसद मंत्री राजेंद्र चौधरी, पर्यटन मंत्री ओमप्रकाश सिंह, भगवती सिंह, एसआरएस यादव, डॉ मधु गुप्ता, राजकिशोर मिश्र आदि नेता भी मौजूद थे. ■

feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया

आवश्यकता है

संवाददाता, विज्ञापन प्रतिनिधि, प्रसार प्रतिनिधि

चौथी दुनिया के लिए उत्तराखण्ड के सभी मंडल और जिला मुख्यालयों पर अनुभवी संवाददाताओं, विज्ञापन, प्रसार प्रतिनिधियों एवं एजेंसियों के लिए शीघ्र आवेदन करें.

E-mail- konica@chauthiduniya.com
arifali@chauthiduniya.com
चौथी दुनिया F-2, सेक्टर 11, नोएडा (गौतमबुद्ध नगर)
उत्तर प्रदेश–201301,
PH : 120-6450888, 6451999

उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड के सभी ज़िलों में वितरण एवं विज्ञापन के लिए संपर्क करें : 0120–6450888, 6451999, मोबाइल : 09266627366